R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 । अंक : 04
16 से 30 नवम्बर 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

जनता मौन... वादे, दावे फेल

भाजपा-कांग्रेस में कांटे की टक्कर

मप्र में खिलेगा 'कमल' या शिवराज को हटा सत्ता में आएंगे नाथ

कहीं भाजपा-कांग्रेस में सीधी लड़ाई, कहीं त्रिकोणीय मुकाबला

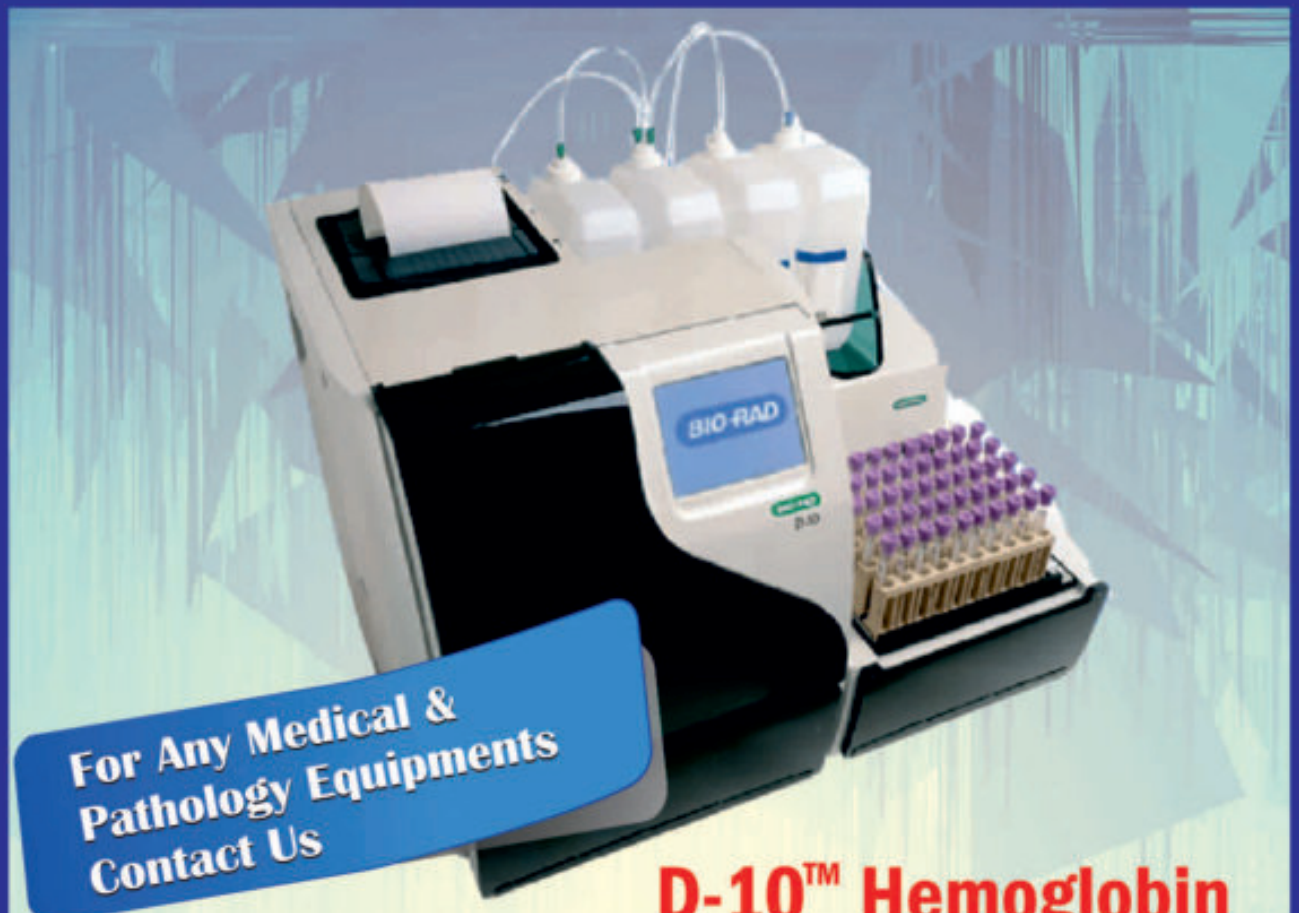

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

प्रशासनिक

9 | सरकारी खर्च में सेंसरशिप

आर्थिक तंगी से मप्र लगातार जूझ रहा है। सरकार का खजाना खाली हो चुका है। ऐसे में वित्त विभाग ने सरकारी खर्च पर सेंसरशिप लगा दी है। इससे कई विभागों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। आलम यह है कि विभागों ने...

राजपथ

10-11 | मुद्दों की अग्निपरीक्षा

मप्र के साथ 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इसलिए देश की दो प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने इन चुनावों में अपना पूरा दम-खम लगा दिया है। दोनों पार्टियों का सबसे...

पर्यावरण

14 | भरे गोदाम, भूखा इंसान

गंगा में 60 फीसदी सीवेज की निकासी जारी है वह भी तब जब राष्ट्रीय नदी के बिगड़े रंग-रूप को बदलने के लिए 30 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का बजट बनाया गया था। स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा...

समस्या

18 | महामारी बन रहा डेंगू

एक दशक पहले तक डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां दिल्ली जैसे महानगरों में ही पाई जाती थीं और देश के अन्य क्षेत्रों के लोग टीवी, अखबार के मार्फत ही जानते थे कि राजधानी में डेंगू, चिकनगुनिया जैसी भी बीमारियां होती हैं। वहीं छोटे शहरों में मलेरिया, डायरिया...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र में इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के मौन ने भाजपा और कांग्रेस के साथ ही सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि प्रदेश में हर बार की तरह इस बार भी भाजपा और कांग्रेस में ही टक्कर है, लेकिन कांटेदार। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गढ़ बचाने के लिए भाजपा ने अपना सबकुछ दांव पर लगा दिया। वहीं कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मप्र में इस बार कमल खिलेगा या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से हटाकर...

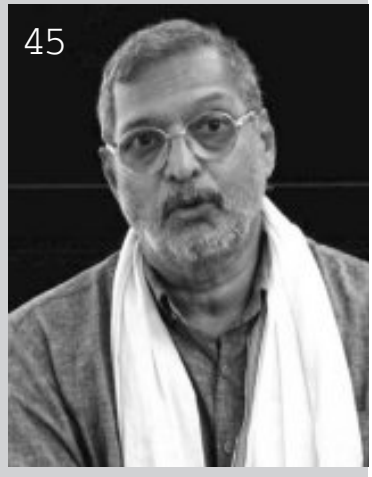

राजनीति

30-31 | इंडिया गठबंधन की चुनौतियां

सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के खिलाफ बने विपक्षी महागठबंधन इंडिया में दरार की चर्चा के बाद अखिलेश यादव ने खुलकर साफ कर दिया है कि कांग्रेस की विधानसभा में सीटों को न बांटने की स्थितियां लोकसभा में भी बनी रहेंगी। अखिलेश ने कहा है कि अगर अभी विधानसभा चुनाव...

महाराष्ट्र

35 | महाराष्ट्र में कलह

महाराष्ट्र की तीन पैरों वाली सरकार में अंदरूनी कलह चरम पर हैं। इस कलह को मराठा आरक्षण आंदोलन ने और बढ़ा दिया है। भाजपा और एनसीपी (अजित) के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके दल के विधायक-मंत्री अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं।

बिहार

38 | सुशासन बाबू की स्त्री शिक्षा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में महिलाओं को लेकर दिए अपने आपत्तिजनक बयान पर चाहे माफी मांग ली हो और स्वयं की निंदा कर ली हो पर सच यही है कि स्त्री अस्मिता और विधानसभा व विधान परिषद की गरिमा को जो क्षति उन्होंने...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

हद हो गई प्रचार की...

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव में प्रचार की जो तस्वीर देखने को मिली है उससे फना निजामी कानपुरी का एक शेर याद आ रहा है...

तिरे वादों पे कहां तक मिरा दिल फरेब खाए
कोई ऐसा कर बहाना मिरी आस टूट जाए

दरअसल, मप्र सहित 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा ने जिस तरह लाव-लश्कर के साथ चुनाव प्रचार किया है, उससे मतदाता भी आजीज आ चुके हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया, जब स्टार प्रचारक मप्र में न आएं हों और उनके लिए जनता को परेशान होना पड़ा हो। इस बार के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री को एक आम नेता की तरह चुनाव प्रचार करता देख हर कोई हैरान हुआ। लोग सवाल भी उठाते रहे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही है कि प्रधानमंत्री को देश की चिंता छोड़ एक प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री कोई आम नेता तो है नहीं... इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी प्रचार करने गए, वहां प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तकरीबन 4 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे मप्र में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री जैसे पदों पर बैठे नेताओं की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ऊपर से इनकी सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन चक्करघिन्नी बना रहा और जनता को परेशानी हुई सो अलग। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री सहित पूरी भाजपा डबल इंजन की सरकार और उसके विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव में तरह-तरह के वादे और प्रलोभन क्यों दिए जा रहे हैं। अगर वाकई मप्र में 20 साल और केंद्र में 10 साल के दौरान विकास के कार्य हुए हैं तो नेताओं को इस तरह पापड़ क्यों बेलने पड़े। दरअसल, सरकारों ने विकास योजनाओं से अधिक उनकी ब्रांडिंग पर पैसा बहाया है। इसका असर यह हुआ है कि सरकार को बार-बार कर्ज लेना पड़ा है। इस कारण स्थिति यह बन गई है कि करोड़ों का काम करने वाले ठेकेदारों को लाख रुपए थमाकर नई सरकार के भरोसे काम चलाया जा रहा है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम केंद्रीय नेताओं को प्रचार में झोंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात दिन मप्र आए और 15 जनसभाओं को संबोधित किया और रोड शो किए। इसी तरह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सात दिन में 21 सभाओं और रोड शो को संबोधित किया। पार्टी ने 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया था। इन स्टार प्रचारकों में से 39 ने चुनावों की तारीख घोषित होने के बाद 634 जनसभाएं और रोड शो किए गए। जिन नेताओं पर देश का दारोमदार है उन्होंने प्रचार में इस तरह समय गंवाया जैसे वे किसी वार्ड के पार्षद हों। कई केंद्रीय मंत्री तो विकास कार्य गिना-गिनाकर फूले नहीं समा रहे थे। हद तो यह भी देखने को मिली कि भाजपा के 18 साल के शासनकाल की तुलना कांग्रेस की 15 महीने की सरकार से करने से भी नेता नहीं चूक रहे थे। लगभग हर मंच से भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि मप्र में डबल इंजन की सरकार है और इसका फायदा प्रदेश के विकास में खूब मिल रहा है। डबल इंजन सरकार के कारण मप्र का हर व्यक्ति खुशहाल है। अगर वाकई इसमें वास्तविकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जैसे लोग देश की चिंता छोड़ मप्र में चुनावी सभाएं क्यों कर रहे हैं। प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, जनता अक्सर एक ही सवाल पूछती है कि क्या देश से बड़ा मप्र है?

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 4, पृष्ठ-48, 16 से 30 नवंबर, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र-संपादक के नाम

akshnews.com

आम आदमी की सोचें

चुनावी साल होने के कारण इस साल बिजली के टैरिफ में मामूली इजाफा हुआ था। बिजली कंपनियों ने करोड़ों का घाटा बताते हुए बिजली की दरों में इजाफा करने की मांग की थी। बिजली कंपनियों को आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए जिससे उस पर बोझ न पड़े।

● **अंकित पाराशर,** जबलपुर (म.प्र.)

नए वोटर तैयार

पांचों राज्यों में पहली बार करीब साठ लाख नए वोटर मतदान करने वाले हैं। जाहिर है कि उनमें पहली बार वोट डालने का उत्साह है और वे अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग भी पूरे उत्साह से करेंगे। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें जनसंख्या के लिहाज सबसे बड़ा राज्य मप्र है।

● **गीता साहू,** सीहोर (म.प्र.)

मेट्रो का इंतजार

मप्र के दो बड़े शहरों भोपाल और इंदौर में मेट्रो को लेकर आम जनता काफी उत्साहित है। अब भोपाल-इंदौर भी मेट्रो सिटी कहलाएंगे। मेट्रो स्टेशनों पर ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा। ये व्यवस्था लागू होने के बाद स्टेशनों पर टोकन और मेट्रो कार्ड से एंट्री-एग्जिट हो पाएगी।

● **बृजेश मीणा,** इंदौर (म.प्र.)

हाईटेक तरीके से लड़ा जा रहा चुनाव

चुनावी माहौल देखकर कहा जा रहा है कि इस बार पुराने मुद्दों पर ही वार-प्रहार हो रहा है। हालांकि मुद्दे भले ही पुराने हैं, लेकिन रणनीति जरूर नई है। इस बार भाजपा और कांग्रेस ने एक-दूसरे को घेरने के लिए हाईटेक तरीका अपनाया है। इस चुनाव में इंटरनेट मीडिया का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। इसलिए चुनाव बिना लहर और मुद्दे के भी आक्रामक तरीके से लड़ा जा रहा है। पिछले चुनावों की अपेक्षा इस बार चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं बदला है। मुद्दे वही हैं, जो हर चुनाव में होते रहे हैं। इस बार भाजपा ने किसी नेता का चेहरा तय नहीं किया है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा बदलाव दिखाई दे रहा है, वह यह कि राजनीतिक दल ज्यादा हाईटेक हो गए हैं।

● **हिमांशी राणा,** भोपाल (म.प्र.)

चुनाव में जातिगत जनगणना का असर

कई बार मुद्दे हैरान करते हैं, जरूरी नहीं कि वे नए हों, लेकिन वे ऐसे छा जाते हैं कि अपने में सबको समाहित कर लेते हैं। बिहार के व्यापक जातिवार सर्वेक्षण ने लगता है ऐसी ही फिजा तैयार कर दी है, जिसमें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताएं ही नहीं, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं भी विचारों के केंद्र में आ गई हैं। बेशक, यह मुद्दा इंडिया ब्लॉक की कांग्रेस समेत ज्यादातर केंद्रीय सत्ता की विपक्षी पार्टियों को उत्साहित कर रहा है जबकि सत्तासीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियां कुछ हद तक दुविधा में दिख रही हैं।

● **पंकज वर्मा,** नई दिल्ली

सरकार उठाए बड़े कदम

हर घर में नल से पानी पहुंचाने के अभियान और कई सिंचाई परियोजनाओं के चलते राज्य में जल संकट अभी भी जारी है। प्रदेश के करीब 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का पानी मिलने लगा है। इसके साथ ही कई लंबित परियोजनाएं अगले दो वर्षों में और 20 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा प्रदान कर सकती है। सरकार को पानी की समस्या के निराकरण के लिए बड़े कदम उठाने चाहिए।

● **राजेश सिंह,** ग्वालियर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स, एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

संन्यास या इमोशनल कार्ड?

राजस्थान के चुनावी संग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधराराजे के एक बयान ने हलचल पैदा कर दी है। झालावाड़ की एक रैली में उन्होंने कहा कि मेरे बेटे सांसद दुष्यंत सिंह की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। क्योंकि आप सभी ने उसे इतनी अच्छी तरह प्रशिक्षित किया है कि मुझे उसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सभी विधायक यहां हैं और मुझे लगता है कि उन पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। वे अपने दम पर लोगों के लिए काम करेंगे। अब इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल यह कि क्या वसुंधरा अब संन्यास लेने जा रही हैं या उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी को मजबूत करने के लिए इमोशनल कार्ड खेला है? राजनीतिक पंडित इसे राजे का एक मजबूत सियासी पैंतरा बता रहे हैं। क्योंकि तीसरी लिस्ट में उनके कई करीबियों को टिकट मिल चुके हैं। जबकि यह भाषण भाजपा की लिस्ट जारी होने के अगले ही दिन आया है। ऐसे में साफ तौर पर वह भाषण के जरिए समर्थकों को खास मैसेज दे रही हैं। अब तक घोषित किए गए टिकटों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें 50 से ज्यादा सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री के करीबियों को मौका मिला है। यानी वसुंधरा राजे की बात को हाईकमान ने तवज्जो दी है।

राजनीति में एंट्री करेंगी कंगना!

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जितना अपनी फिल्मों की वजह से चर्चा में रहती हैं उतना ही राजनीतिक बयानों को लेकर भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। अब उन्होंने राजनीति में एंट्री को लेकर भी बड़ी बात कही है। कंगना रनौत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर प्रभु श्रीकृष्ण की कृपा रही तो वह जरूर चुनाव में उतरेंगी। इसके साथ ही कयास तेज हो गए हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। पिछले हफ्ते कंगना रनौत ने श्रीकृष्ण की नगरी द्वारका में मंदिरों के दर्शन किए। इस बार दशहरे के मौके पर भी दिल्ली के लालकिले पर होने वाली मशहूर लवकुश रामलीला में रावण दहन करने कंगना रनौत पहुंची थीं। आमतौर पर यहां प्रधानमंत्री रावण दहन किया करते थे। इस बार कंगना का पहुंचना भी इस ओर संकेत था कि वह पॉलिटिकल एंट्री कर सकती हैं। बताया गया था कि महिला आरक्षण कानून बनने की वजह से इस बार महिला से रावण दहन कराया गया है। कंगना रनौत ने कहा कि 600 साल के संघर्ष के बाद आज राम मंदिर तैयार हो रहा है। भाजपा की वजह से देश को यह दिन देखने को मिला है। उन्होंने कहा, हम बड़ी धूमधाम से मंदिर को फिर से स्थापित कर रहे हैं। यह सनातन धर्म के लिए एक बड़े उत्सव की तरह है।

टूटने की कगार पर विपक्षी गठबंधन

गठबंधन और समीकरण सियासत की फिलहाल अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। हर दल सियासी समीकरणों के सहारे चुनावी नैया पार करना चाहता है। एनडीए ने ढ़ाई दर्जन से ऊपर राजनीतिक पार्टियों को लेकर गठबंधन बनाया है तो दो दर्जन के करीब दलों को लेकर विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है। लेकिन विपक्षी एकता बनने के साथ ही बिखराव के रुझान भी आने लगे हैं। एक ओर जहां समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन में रहते हुए आपस में ही जोर आजमाइश शुरू कर दी है वहीं दूसरी तरफ इसी महीने होने जा रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को राजनीतिक विश्लेषक अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे थे, उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि सेमीफाइनल इंडिया और एनडीए में हो रहा है या फिर विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के बीच? गौरतलब है कि उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच मप्र में आपसी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को किनारे कर दिया तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को चुनौती दे डाली। तीखे व्यंग्य बाण भी दोनों ओर से चलने लगे हैं।

अखिलेश की बढ़ेगी टेंशन!

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रवि प्रकाश वर्मा ने अपने इस्तीफे का कारण पार्टी के भीतर की अंतर्कलह को बताया है। अब अटकलें तेज हो गई हैं कि वे कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के लोग अंदर खाने इस बात को कबूल कर रहे हैं कि वर्मा के उनके साथ आने से एक बड़े कुर्मी वोट बैंक को साधने में वो कामयाब हो सकेगी। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले लखीमपुर खीरी के बड़े नेता और कुर्मी वोट बैंक में पकड़ रखने वाले रवि प्रकाश वर्मा के सपा छोड़ने पर समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। पॉलिटिकल पंडितों की मानें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुर्मी वोट बैंक को साधने की एक बड़ी रणनीति के तहत इसको देखा जा रहा है। रवि प्रकाश वर्मा की पहचान कुर्मी के दिग्गज नेताओं में होती है। उनके समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ने के साथ कांग्रेस में आने पर कांग्रेस को खीरी के अलावा आसपास की कई लोकसभा सीटों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है।

कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना

राजस्थान में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव के लिए मतदान नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे प्रदेश की राजनीति परवान चढ़ रही है। आलम यह है कि बीच चुनाव में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मान नहीं रहे हैं। सचिन पायलट से मतभेद अब नहीं रहे, यह बात कहने में भी वे राजनीतिक दांव-पेंच करना नहीं भूले। इस बीच उन्होंने कहा कि पायलट के साथ मानेसर गए सभी लोगों के टिकट क्लीयर हो चुके हैं। मैंने किसी एक पर भी आपत्ति नहीं जताई। आपत्ति नहीं जताने की बात कहकर वे ये भी कहना चाहते हैं कि ये सभी विधायक बगावत की कोशिश में शामिल हैं और इनके लिए खुद को त्याग करने वाले राजनेताओं में भी शुमार करना चाहते हैं। दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी परोक्ष रूप से निशाना ही साधा। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से वसुंधरा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे मुंह से तो गलती से निकल गया था कि हमारी सरकार को बचाने के लिए वसुंधरा का धन्यवाद।

आयोग से बचने पर्ची सिस्टम

विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और विवाद रहित बनाने के लिए चुनाव आयोग आचार संहिता लगाता है। इस दौरान पूरा प्रशासन आयोग के हाथों में रहता है। इस दौरान सख्ती से जांच पड़ताल की जाती है। ताकि मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां रेवड़िया न बांटें। इस बार भी चुनाव आयोग ने यही प्रक्रिया अपना रखी है। लेकिन आयोग की नजर से बचने के लिए नेताओं ने भी तरीका निकाल लिया। यह तरीका पर्ची सिस्टम का था। नेताओं ने इस बार आयोग की सख्ती और ताबड़तोड़ कार्यवाही से बचने के लिए पर्ची सिस्टम का इस कदर सहारा लिया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सूत्रों का कहना है कि नेताओं ने जमकर पर्चियां बांटीं। चुनाव लड़ रहे नेताओं की सेटिंग भी ऐसी है कि उनके यहां से पर्ची लेकर मतदाता जो चाहता वह उसे आसानी से मिल जाता है। बस नेताओं की एक ही अपील है कि वोट जरूर दे जाएं। दरअसल, मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब से लेकर साड़ी हो या कपड़े बस एक पर्ची का खेल। और तो और प्रतिबंधित नशाखोरी पर जोर। 50 की पुड़िया के लिए भी पर्ची बनाई जा रही है। नेताओं के क्षेत्र में फैले मैनेजरों का मैनेजमेंट चुनाव आयोग की तमाम कवायदों पर भारी पड़ रहा है। हालांकि नेताओं की तमाम चालबाजियों के बाद भी आयोग ने इस बार रिकार्ड सोना, चांदी, शराब, नगद और नशे का सामान जब्त किया है।

असमंजस में अफसर

मप्र के इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि भावी सरकार की पहले से ही कल्पना कर लेने वाले ब्यूरोक्रेट्स भी इस बार असमंजस में फंसे हुए हैं। पूर्व में ब्यूरोक्रेट्स आचार संहिता लगने से पहले ही भावी सरकार का आंकलन कर लेते थे और उस पार्टी के नेताओं के यहां चक्कर लगाने लगते थे। लेकिन इस बार अफसर चक्करघिन्नी बन गए हैं। जो अफसर आचार संहिता लगते ही 90 फीसदी तक आंकलन कर लेते थे कि चुनाव का ऊंट किस करवट बैठने वाला है, वे भी कोई गणित नहीं लगा पा रहे हैं। लंबे अर्से बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी एक तरफ की लहर को लेकर आला अफसर भी असमंजस में हैं। ऐसे अफसर नीति निर्धारकों से लेकर कई चुनाव एक्सपर्ट से कई बार मशवरा कर चुके हैं। लेकिन उनके अब तक के सभी प्रयास असफल ही रहे हैं। लेकिन हथियार अभी भी नहीं डाले गए हैं और चुनाव पूर्व की हवा के सही आंकलन तक पहुंचने के प्रयास सतत् जारी हैं। सूत्रों का कहना है कि कुछ अफसर तो ऐसे हैं जो कभी इधर तो कभी उधर जाकर अपनी जमावट में जुट गए हैं। उधर, भाजपा और कांग्रेस भी अपने माध्यमों से अफसरों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है।

आखिर मेरा क्या कसूर ?

कई बार अफसरों की कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी उन पर भारी पड़ जाती है। खासकर चुनावी वर्ष तो मैदानी अफसरों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होता है। एक तो वे पहले से ही विपक्ष के निशाने पर होते हैं और अगर उन्होंने चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया तो सत्तापक्ष के भी टारगेट पर आ जाते हैं। इस बार भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कई अफसर चुनाव आयोग के निशाने पर आ गए। सत्तापक्ष और विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग में कई अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें की गई हैं। इन्हीं में से एक हैं 2013 बैच के आईएएस अधिकारी। साहब वर्तमान में राजधानी में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अपनी स्वच्छ छवि और प्रशासनिक निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन साहब के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर दी गई कि वे भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हुए कार्यकर्ताओं के घर और वाहन से पार्टी के झंडे निकलवा रहे हैं। आयोग ने इस मामले कलेक्टर से प्रतिवेदन मांगा। जांच में पाया गया कि साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसे में चुनाव आयोग ने उन्हें क्लीनचिट दे दी है। लेकिन इस घटना क्रम के बाद साहब की चिंता बढ़ गई है कि बिना कुछ करे-धरे वे प्रदेश की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी के निशाने पर आ गया है। अब साहब अपने साथियों से पूछ रहे हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या है। साहब ही नहीं, ऐसे कई अफसर हैं जो चुनाव साल में कर्तव्यनिष्ठा की भेंट चढ़ जाते हैं।

विकास की खुली पोल

प्रदेश सरकार में सबसे विवादास्पद मंत्री के रूप में ख्यात एक नेताजी जब अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो वे स्थानीय मतदाताओं के आक्रोश का शिकार बन गए। दरअसल, प्रदेश सरकार के बड़े विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले माननीय ग्वालियर-चंबल अंचल के एक जिले की एक विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी वे यहीं से उपचुनाव जीतकर मंत्री बने थे। मंत्रीजी प्रदेश में जहां कहीं भी जाते थे तो दावा करते थे कि उन्होंने अपने जिले में 22 हजार करोड़ रुपए का विकास कार्य करवाया है। विकास की बड़ी-बड़ी डींगे हांकने वाले मंत्रीजी गत दिनों जब चुनाव प्रचार के सिलसिले में अपने विधानसभा क्षेत्र गए तो वे उस इलाके में पहुंच गए जहां जर्जर सड़क, टूटी नालियां और गंदगी से परेशान लोग खड़े थे। लोगों ने भी मौके का फायदा उठाते हुए मंत्रीजी को घेर लिया और उन पर सवालों की बौछार कर दी। लोगों का गुस्सा देख मंत्रीजी ने तत्काल माफी मांगी और लोगों को आश्वस्त किया कि इस बार जिता दो, आप लोगों की सारी समस्याएं सबसे पहले दूर करूंगा।

डीए बिगाड़ न दे खेल

केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 से दिया गया 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) मप्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा या नहीं, इसे लेकर संशय की स्थिति निर्मित हो गई है। भत्ता देने में देरी से नाराज कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी, जो नहीं मिली है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी और बढ़ गई है। क्योंकि 2020 में भी ऐसा ही हुआ था। कमलनाथ सरकार ने पांच प्रतिशत डीए देने के आदेश जारी कर दिए थे और तभी सरकार चली गई। नई सरकार ने वह आदेश नहीं माना, इससे न सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों, बल्कि रिटायर कर्मचारियों को महंगाई राहत का भी नुकसान हुआ। ऐसे में पहले से जले-भुने अधिकारी-कर्मचारी इस चुनावी माहौल में सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि कर्मचारी संगठनों ने अंदर ही अंदर सरकार के खिलाफ अभियान चला रखा है। अब देखना यह है कि डीए की आस में परेशान हो रहे अधिकारी-कर्मचारी किसका साथ देते हैं। गौरतलब है कि कई सीटों पर कर्मचारी ही जीत-हार तय करते हैं।

ड्रग्स, कैश, शराब, सोना...

मप्र में विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए पार्टियां साम, दाम, दंड, भेद सबका सहारा ले रही है। इसका संकेत आचार संहिता के बाद ड्रग्स, कैश, शराब, सोना, फ्रीबीज और नकदी की जब्ती से लगाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने इसे चुनाव खर्च पर निगरानी की निरंतर कोशिशों का नतीजा बताया है। मप्र में 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जब्ती के रुझान में काफी वृद्धि हुई है। इससे कहा जा रहा है कि पार्टियां इस बार का चुनाव ड्रग्स, कैश, शराब, सोना के दम पर जीतना चाहती हैं।

मप्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे यहां विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियां भी ज्यादा एक्टिव होती नजर आ रही हैं। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों ने ड्रग्स, शराब, सोना, फ्रीबीज और नकदी जब्त की है। चुनाव में शुचिता की न जाने कितनी बातें होती हैं। आचार संहिता की न जानें कितनी व्याख्याएं चलती हैं। आह्वान, अपील, सुझाव के साथ चुनाव आयोग के डंडे भी चलते हैं। शुचिता के दावों से कोई नहीं चूकता। मगर, कार्रवाइयों के आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। यह कि इस बार के चुनाव में न केवल शराब की खेप दर खेप खपाने की चहुंओर कोशिशें चल रही हैं, बल्कि पैसे से वोट खरीदने का मिजाज भी मस्ती पर है। अब तक हुई कार्रवाइयों के आंकड़े बताते हैं कि पिछले चुनाव की तुलना में यह चार गुनी ज्यादा रफ्तार पर है। उधर, आलम यह भी है कि इन तमाम कार्रवाइयों में किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी की संलिप्तता सामने नहीं है।

आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 31 करोड़ 82 लाख 65 हजार रुपए नकद, 52 करोड़ से अधिक राशि की अवैध शराब जब्त की जा चुकी है। पिछले चुनाव में आचार संहिता के दौरान 72 करोड़ 93 लाख रुपए की शराब, नकदी सहित अन्य सामग्रियों की जब्ती हुई। 15 नवंबर तक के आंकड़े के अनुसार 331 करोड़ 97 लाख रुपए से अधिक की जब्ती हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का कहना कि 9 अक्टूबर से अब तक 28 करोड़ 38 लाख 95 हजार 49 रुपए की जब्ती की कार्रवाई की गई है। इसमें 25 लाख लीटर से अधिक अवैध शराब सहित अन्य सामग्रियों शामिल हैं। सी विजाल एप पर साढ़े सात हजार से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं। इन पर त्वरित कार्रवाई भी ही रही है, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में छह अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच 72 करोड़ लाख रुपए की एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई मतदान तक जारी रहेगी। आचार संहिता लगने के बाद टीमें लगातार ढ़ाबों, होटलों, रेस्टोरेंट पर छापे मार रही है। टीम ने बीते दिनों कुल 1801 बल्क लीटर शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख 37 हजार 633 रुपए है। हालांकि, सख्ती से शराब तस्करी में हड़कंप जरूर मचा हुआ है, मगर मंशे की धार पर अंकुश लग गया हो, यह कतई नहीं कहा जा सकता।

सबसे बड़ी विडंबना यह देखने को मिल रही है कि इस बार भले ही रिकॉर्ड सामग्री और नगदी जब्त की गई है, लेकिन किसी भी पार्टी या नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्वालियर-चंबल का क्षेत्र दो राज्यों उप्र और राजस्थान से सटा है तो सीमा पर बनाई चौकियों पर नकदी, शराब, सोना-चांदी को पकड़ने की कार्रवाइयां भी अधिक हो रही हैं। देखने में आ रहा है कि एफएसटी और एसएसटी की टीमों ने अब तक राजनेता या उनके समर्थकों के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की है। व्यापारी, कारोबारी और उनके नुमाइंदे ही पकड़े जा रहे हैं। दो दिन पहले तक ग्वालियर में 1 करोड़ 93 लाख नगदी पकड़ी गई लेकिन यह राशि तकादे की ही रही या फिर व्यापार से संबंधित। मुरैना में एक दल विशेष के चुनाव चिन्ह वाली साड़ियां और टी-शर्ट पकड़ी गई और जौरा क्षेत्र में केस भी दर्ज हुआ। अंबाह के महुआ क्षेत्र में भाजपा के नाम पर साड़ियां बांटी गई, इस मामले में भी अज्ञात पर ही केस दर्ज हुआ। मुरैना शहर के आमपुरा में एक मकान से महिलाओं को स्टील के बड़े कटोरे बांटे गए। यह कटोरे वोट देने का लालच देकर बांटे गए। महाकौशल और विध्य अंचल के 17 जिलों में प्रशासन ने कार्रवाई कर करोड़ों रुपए जब्त किए हैं। हालाकि, जांच के बाद बहुत से लोगों का पैसा लौटा भी दिया गया। सिवनी के चार विधानसभा क्षेत्रों में एसएसटी की अलग-अलग टीमों ने 21 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 13 प्रकरणों पर 16.78 लाख रुपए जब्त किए। बालाघाट जिले में अब तक सात कार्रवाई हुई है। इसमें एसएसटी और एफएसटी टीम ने कुल 36 लाख 6 हजार 905 रुपए जब्त किए गए। उमरिया में एसएसटी की टीम ने चार व्यापारियों से 8 लाख रुपए जब्त किए थे, जिन्हें जांच के बाद लौटा दिए गए। मंडला जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों निवास, बिछिया और मंडला विधानसभा क्षेत्रों टीम में एफएसटी और एसएसटी की अब तक 50 लाख रुपए का सोना, 7 लाख रुपए प्रचार सामग्री और 5 लाख की अवैध शराब जब्त की जा चुकी है।

● **जय सिंह सेंधव**

1 लाख 85 हजार से अधिक लोगों पर हुई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

मप्र विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिता 9 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि पुलिस द्वारा शस्त्र लाइसेंस, विस्फोटक पदार्थों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में अब तक आपराधिक प्रवृत्ति के 1 लाख 85 हजार 354 व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही 48 हजार 83 गैर जमानती वारंटों की तामीली करा ली गई है। राजन ने बताया कि प्रदेश में अब तक 2 लाख 69 हजार 297 लाइसेंसी शस्त्र थानों में जमा करा लिए गए हैं। 758 शस्त्रों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान अब तक 3 हजार 135 अवैध हथियार, 759 कार्टिज, 3 हजार 920 विस्फोटक पदार्थ एवं 1 बम भी मिला हैं। ये सभी सामग्रियां तत्काल जब्त कर ली गई हैं। प्रदेश में कुल 376 अंतर्राज्यीय नाकों एवं 712 आंतरिक नाकों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। प्रदेश में 846 फ्लाईंग स्क्वाड (उड़नदस्ता), 996 सर्विलांस टीम (एसएसटी) एवं 109 क्विक रिसपांस टीम (क्यूआरटी) कार्य कर रही हैं।

सरकारी खर्च में सेंसरशिप

आर्थिक तंगी से मप्र लगातार जूझ रहा है। सरकार का खजाना खाली हो चुका है। ऐसे में वित्त विभाग ने सरकारी खर्च पर सेंसरशिप लगा दी है। इससे कई विभागों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। आलम यह है कि विभागों ने कई योजनाओं-परियोजनाओं की रफ्तार या तो कम कर दी है या बंद कर दिया है। उधर, वित्त विभाग केवल उन्हीं कामों के लिए मद की मंजूरी दे रहा है जो अति आवश्यक हैं। इस का असर यह हुआ है कि विभागों में काम करने वाले ठेकेदारों का भुगतान भी रुका हुआ है।

गौरतलब है कि चुनावी वर्ष में वित्त विभाग ने खर्च के मामले में पहले ही वित्तीय अनुशासन के नाम पर कई विभागों के खर्च में पाबंदी लागू कर दी है। केवल जरूरी खर्च के लिए ही राशि आहरण की अनुमति दी जा रही है। राशि खर्च करने के लिए भी विभागों को पहले वित्त विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। इस बीच निर्माण कार्य से जुड़े दो बड़े महकमे के लिए वित्त विभाग ने खर्च की सीमा तय की है। वे अक्टूबर माह से वित्त विभाग द्वारा तय की गई राशि से अधिक के बिल ट्रेजरी में नहीं लगा सकेंगे।

वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में केवल आवश्यक योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। उधर वित्त विभाग ने नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत नर्मदा घाटी विकास विभाग इस अवधि में 322 करोड़ रुपए खर्च कर सकेगा, वहीं जल संसाधन विभाग को 430 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई है। गत दिनों चिकित्सा शिक्षा विभाग को 327 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च की लिमिट तय की गई थी। अब ये विभाग अक्टूबर माह के लिए तय राशि से अधिक का भुगतान नहीं कर सकेंगे। यहां बता दें कि नर्मदा घाटी विकास विभाग के तहत एक दर्जन से अधिक बड़ी और मध्यम परियोजनाओं का काम तेजी से चल रहा है, जिससे कि नर्मदा नदी के पानी का पूरा उपयोग किया जा सके। नर्मदा के पानी से सरोकार रखने वाले प्रमुख राज्यों के बीच जो सहमति बनी है, उसके मुताबिक मप्र का वर्ष 2024 तक उसे आवंटित पानी का पूरा उपयोग करना है। ऐसे में राज्य सरकार नर्मदा घाटी से जुड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। इसी तरह जल संसाधन विभाग की भी छोटी-बड़ी 50 से अधिक परियोजनाओं पर इस समय तेजी से काम चल रहा है।

चुनावी साल में हो रही घोषणाएं सरकार के खजाने पर भारी पड़ रही हैं। मौजूदा बजट के मुताबिक सरकार की आमदनी 2.25 लाख करोड़ रुपए है और खर्च इससे 54 हजार करोड़ ज्यादा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 हजार करोड़ की नई घोषणाएं कर चुके हैं। अकेले लाड़ली बहना योजना पर ही सालाना 19 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी बीच वित्त विभाग ने घोषणाओं पर होने वाले खर्च का खाका भी तैयार किया है। इन आंकड़ों में चौकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आए हैं। वर्तमान में 3.30 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी सरकार चुनावी दौर में की गई घोषणाओं पर सालाना 21 हजार 864 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। सरकार का औसतन खर्च 22 हजार करोड़ प्रतिमाह से बढ़कर 23 हजार 822 करोड़ होगा। वहीं हर महीने का 1 हजार 822 करोड़ रुपए प्रतिमाह खर्च बढ़ेगा। सरकार की नई घोषणाओं के कारण प्रतिमाह 23 हजार 822 करोड़ खर्चा होगा। इसके साथ ही चुनावी माहौल में सालाना 21 हजार 864 करोड़ अतिरिक्त खर्च होंगे। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर सालाना 15 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे।

वहीं ग्राम रोजगार सहायकों के मानदेय पर 274.95 करोड़ प्रतिवर्ष रहेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय पर 371 करोड़ सालाना होगा। तो कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता पर 1520 करोड़ सालाना रहेगा। वहीं संविदा कर्मियों के समान वेतन पर 720 करोड़ सालाना और नई भर्तियों पर कुल 3600 करोड़ सालाना तय किया गया। लैपटॉप योजना पर 196 करोड़ सालाना खर्ज किया जाएगा। तो वहीं ई-स्कूटी योजना पर 135 करोड़ सालाना रहेगा। ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित मानदेय पर 56.38 करोड़ होंगे। प्रतिवर्ष खर्च वर्तमान में सरकार पर 3.30 लाख करोड़ का खर्च रहेगा। मप्र के वित्तीय हालात के अनुसार, प्रदेश के हर व्यक्ति पर 40 हजार रुपए से ज्यादा का कर्ज है। मप्र सरकार इस साल छह महीनों में अलग-अलग तारीखों पर 13 बार कर्ज ले चुकी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून और सितंबर में सरकार ने आरबीआई से लोन लिया है।

● **सुनील सिंह**

कर्ज पर कर्ज ले रही सरकार

प्रदेश की वित्तीय स्थिति फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रही है। सरकार लगातार नई-नई योजनाओं को पूरा करने के लिए कर्ज भी लेती जा रही है। फिलहाल सरकार ने सभी विभागों को नया फरमान जारी किया है। इस नए फरमान में लिखा गया है कोई भी विभाग 25 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। इससे ज्यादा खर्च करना है तो वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। यहां तक कि केंद्र सरकार के बजट और अनुदान के खर्च का भी विभाग इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वित्त की अनुमति के बाद ही फंड निकालने की इजाजत मिलेगी। आर्थिक तंगी से मप्र लगातार जूझ रहा है। शिवराज सरकार का खजाना खाली हो चुका है। राज्य सरकार आचार संहिता से पहले कर्ज पर कर्ज ले रही थी। 4 अक्टूबर को शिवराज सरकार ने एक बार फिर 3000 करोड़ का कर्ज लिया। एक ही दिन में दो बार अलग-अलग टेन्योर पर सरकार ने 3000 करोड़ का कर्ज लिया है। सरकार ने 15 साल के टेन्योर पर 1000 करोड़ का एक कर्ज लिया है। 12 साल के टेन्योर पर 2000 करोड़ का दूसरा कर्ज लिया गया। महज 9 दिन में 5 बार शिवराज सरकार कर्ज ले चुकी है। इसके पहले 26 सितंबर को एक ही दिन में तीन बार सरकार ने कर्ज लिया था। सितंबर महीने में ही सरकार ने पांच बार कर्ज लिया था। इसके पहले शिवराज सरकार 12 सितंबर को 1000 और 21 सितंबर को 500 करोड़ का कर्ज आरबीआई से ले चुकी है। सिर्फ सितंबर में ही 6.5 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया। चुनावी साल में सरकार जनता को लुभाने के लिए नई घोषणाएं कर रही है और कर्ज लेने का सिलसिला थम नहीं रहा है।

मप्र विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां एवं आक्रामकता बढ़ती जा रही है। भाजपा और कांग्रेस सत्ता के लिए जंग लड़ रही हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इस चुनाव में जनहित के मुद्दों पर गहरा सन्नाटा पसरा है। इसके बावजूद ओबीसी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लाड़ली बहना, नारी सम्मान, सनातन और जातीय गणना जैसे मुद्दे चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। इन मुद्दों को 2024 के लोकसभा के लिए अहम माना जा रहा है इसलिए मिशन 2023 में इन मुद्दों की अग्निपरीक्षा होनी है।

मुद्दों की अग्निपरीक्षा

मप्र के साथ 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इसलिए देश की दो प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने इन चुनावों में अपना पूरा दम-खम लगा दिया है। दोनों पार्टियों का सबसे अधिक फोकस मप्र पर है। इसकी वजह यह है कि मप्र की जीत-हार का असर पूरी हिंदी पट्टी पर पड़ता है। इसलिए इस बार भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव में कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जो भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। हर मंच पर इन्हीं मुद्दों को उठाया जा रहा है। जनता का ध्यान इन्हीं पर केंद्रित करने का प्रयास राजनीतिक दल कर रहे हैं। इनमें, ओबीसी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लाड़ली बहना, नारी सम्मान, सनातन और जातीय जनगणना शामिल हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा को मात देने के लिए विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसकी मुख्य पार्टी कांग्रेस के मुद्दे जनता की अदालत में परखे जाएंगे। हिंदी पट्टी में अगर कांग्रेस हार जाती है तो यह जातीय जनगणना के लिए विनाशकारी साबित होगा। हारने के बाद पार्टी को अपनी मांग जारी रखने के लिए फिर कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

एक तरफ राजनीति तेजी से करवट बदल रही है तो दूसरी तरफ जनता भी सजग हो रही है। चुनाव हमेशा मुद्दों पर लड़े जाते रहे हैं लेकिन विधानसभा चुनाव इस सदी का ऐसा पहला चुनाव होगा जिसमें कोई बड़ा मुद्दा नजर नहीं आ रहा। वर्ष 2003 के चुनाव में बिजली और सड़क दो बड़े मुद्दे जनता के सामने थे। भाजपा ने इन्हीं दो मुद्दों को नाव बनाकर 10 वर्ष के सत्ता के वनवास को खत्म किया था। पिछले 20 वर्षों में चुनाव धीरे-धीरे मुद्दाविहीन हो चले हैं। अब न सड़कें मुद्दा हैं, न बिजली कटौती की समस्या। फसलों का मुआवजा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों की परेशानी और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे चुनाव को प्रभावित नहीं कर रहे। इस बार का चुनाव न लहर के बीच लड़ा जा रहा है, न मुद्दों पर। वे मुद्दे जो किसी समय सत्ता बदलने का माद्दा रखते थे समय के साथ अब गुम हो चले हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में बिजली और सड़क मुख्य मुद्दे थे।

प्रदेशभर में जनता बिजली कटौत्री से त्रस्त थी। सड़कों की स्थिति को लेकर कहा जाता था कि महाराष्ट्र, गुजरात से मप्र में प्रवेश करेंगे तो सड़क की बदहाली खुद आपको बता देगी कि आप अब मप्र में हैं। विधानसभा चुनाव इन्हीं दो मुद्दों को लेकर लड़ा गया। मुद्दों को लेकर यह जनता का आक्रोश था कि दिग्विजय सिंह की 10 वर्ष की सत्ता उखड़ गई। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव आते-आते बिजली और सड़क के मुद्दे धीरे-धीरे अपना असर खोने लगे। केंद्र की अटल ज्योति योजना का प्रदेश सरकार को खासा लाभ मिला। इसके बाद वर्ष 2013 में चुनाव में रामलहर का असर विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में साफ नजर आया। सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दे बहुत पीछे छूट गए। किसानों की नाराजगी

ओबीसी एजेंडे पर असर पड़ेगा

कांग्रेस अगर इन चुनावों में बुरी हार हारती है और उसका ओबीसी एजेंडा फेल होता है कि तो इसके कई संभावित असर हो सकते हैं। कांग्रेस का पुराना पार्टी सांगठनिक ढांचा, जो अब भी बेहद शक्तिशाली है, फिर से प्रभावी होने की कोशिश करेगा। ये मुख्य रूप से सवर्ण हैं और सामाजिक नीतियों में यथास्थिति चाहते हैं। नई राजनीतिक स्थिति में यह समूह पार्टी को ओबीसी और सामाजिक न्याय के मुद्दे को छोड़ने या ठंडा करने के लिए दबाव बनाएगा। ये दबाव सफल भी हो सकता है क्योंकि कांग्रेस ने ये मुद्दे अपने आंतरिक विश्वास के कारण नहीं, राजनीतिक जरूरत के हिसाब से अपनाए हैं। कांग्रेस ने ओबीसीवाद इसलिए अपनाया है क्योंकि भाजपा की मौजूदा राजनीति और सामाजिक समीकरण की कोई और काट कांग्रेस को मिल नहीं रही है। इस साल की शुरुआत में रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी गति बदली है और पार्टी ने ढांचे में 50 प्रतिशत पद एससी, एसटी, ओबीसी को देने का ऐलान किया है। ओबीसी का मुद्दा विधानसभा चुनाव में नहीं चला तो ये नीति ठंडे बस्ते में जा सकती है। कांग्रेस की हार से जाति जनगणना का मुद्दा ठंडा पड़ सकता है। ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिसे कांग्रेस के बड़े नेता, खासकर राहुल और प्रियंका गांधी चुनावी रैलियों में जोरशोर से उठा रहे हैं। अगर कांग्रेस हारती है तो विश्लेषक ये विचार लेकर आएंगे कि जाति जनगणना को मुद्दा बनाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता।

और उपज का सही मूल्य भी मुद्दा नहीं रहा।

मप्र में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है वे हैं-ओबीसी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लाड़ली बहना, नारी सम्मान, सनातन और जातीय जनगणना आदि। इस बार के विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना एक बड़ा और प्रमुख मुद्दा है। जहां कांग्रेस यह ऐलान कर चुकी है कि सरकार आने पर वो प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएगी। वहीं भाजपा इसके जवाब में ओबीसी वर्ग से तीन मुख्यमंत्री दिए जाने, ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए जाने की बात को रखेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार अपने दौरों में ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल में भी ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण न दिए जाने की बात पर कांग्रेस नेता भाजपा को घेर रहे हैं। प्रदेश में ओबीसी की आबादी 52 प्रतिशत बताई जाती है। चुनाव में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक-दूसरे के कार्यकाल के भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। जहां कांग्रेस भाजपा सरकार में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस की 15 महीने की कमलनाथ सरकार में हुए भ्रष्टाचार की बात कर रही है। कांग्रेस 50 प्रतिशत के कमीशन का आरोप सरकार पर लगा रही है।

गौरतलब है कि प्रदेश में महिला वोटर बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में उन्हें लुभाने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रयासरत हैं। भाजपा सरकार की लाड़ली बहना और कांग्रेस की नारी सम्मान योजना दोनों ही इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दों में शामिल हैं। भाजपा ने लाड़ली बहना योजना शुरू कर महिलाओं के खाते में 1250 रुपए देना शुरू किया है जबकि कांग्रेस की ओर से कमलनाथ ने यह वादा किया है कि उनकी सरकार आने पर महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस ने फॉर्म भी भरवाए हैं। सनातन भी 2023 के चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा होगा। भाजपा जहां तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान को भुनाने का प्रयास करेगी, वहीं कांग्रेस रामपथ गमन, महाकाल लोक में मूर्तियों के टूटने जैसे विषयों से भाजपा को जवाब देगी। ओंकारेश्वर में स्थापित आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को भी भाजपा अपने प्रचार में शामिल करेगी। परिवारवाद का आरोप भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे के ऊपर लगाती आई हैं। विधानसभा चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा भी प्रमुखता से गूंजेगा। भाजपा का हमेशा से कांग्रेस पर ये आरोप रहा है कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा वंशवाद को समाप्त करने की बात जरूर करती है लेकिन इनकी पार्टी में वंशवाद फलफूल रहा है।

कांग्रेस इस समय लोहियावादी या सामाजिक न्यायवादी पार्टी होने का भ्रम पैदा कर रही है। कम से कम भाषणों में तो ऐसा ही है। पिछड़ी और वंचित जातियों को पार्टी संगठन में हिस्सा देने से लेकर जाति जनगणना की मांग करने और ओबीसी की राजकाज तथा नौकरशाही व मीडिया में हिस्सेदारी जैसे सवालों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुलकर बोल रहे हैं। कांग्रेस अभी जो कर रही है, वह अगर वह सचमुच कर पाई तो इसे पार्टी के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कायाकल्प में से एक माना जाएगा।

राजनीति में काम ही नहीं, बात भी बोलती है। खासकर तब जबकि वे बातें चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दौरान किसी महत्वपूर्ण पार्टी द्वारा बोली गई हों। कांग्रेस का नया ओबीसीवाद और सामाजिक न्याय 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आया है। इनमें तथाकथित हिंदी पट्टी के तीन राज्य राजस्थान, मप्र और छत्तीसगढ़ भी हैं। कांग्रेस का इस समय ओबीसी मुद्दे को अचानक से उठाना चिंतित भी करता है। ओबीसी एजेंडा कामयाब होने के लिए जरूरी हो गया है कि कांग्रेस इन चुनावों में अच्छा करे तथा राजस्थान, मप्र और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल करे। हालांकि तेलंगाना में सिर्फ भाजपा ओबीसी मुख्यमंत्री की बात कर रही है और गृहमंत्री अमित शाह ने ये बात कह दी है तो जनता चाहेगी कि भाजपा वहां बेहतर करे। इसकी सीधी वजह ये है कि अगर ओबीसी को लेकर इतना सारा हल्ला मचाने के बाद कांग्रेस हार गई तो ये कहा जाएगा कि ओबीसी की बात करके या सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। इस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी एजेंडा पीछे जा सकता है। यह तकलीफदेह होगा क्योंकि ओबीसी का सवाल, मंडल कमीशन के बाद, पहली बार इतनी मजबूती से राष्ट्रीय राजनीति में आया है।

● **कुमार राजेन्द्र**

मतदाताओं को रिझाने वाला बनेगा सरदार

विधानसभा स्तर के मुद्दों के अलावा प्रदेश व देश स्तर के एक नहीं बल्कि अनके मुद्दों की भरमार है। इन मुद्दों पर चुनाव लड़ प्रत्याशी मतदाताओं से बात नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, तो बस वोट दे दो और वोट दिला दो की। यह मतदाताओं को भी अचंभित कर रहा है, कि कैसे बड़े-बड़े मुद्दों पर उनके प्रत्याशी बात करने तक नहीं तैयार है, बस समीकरण ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने का बनने में सारी ताक झोंक रही है। प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, सड़कें, स्ट्रीट लाइटें, आवारा पशुओं जैसी अनेक समस्याएं व मुद्दे विकराल हैं। इन पर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसे में मतदाताओं को भी ऐसी पार्टियों व प्रत्याशियों की ओर गहराई से देखने की जरूरत है कि चुनाव लड़ रहे लोग उनके अहम मुद्दों व समस्याओं के निराकरण के लिए क्यों नहीं कुछ बोल रहे है। बोल रहे हैं तो बस लोक-लुभावन वादे व फ्री देने की बात कर रहे हैं, जिसमें लोगों व प्रदेश का ही नुकसान है, इससे पहले ही हजारों करोड़ रुपए कर्जे की समस्या से जूझ रहा प्रदेश और निचले पायदान पर खिसकेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पिछली बार की तरह इन चुनावों में भी हर बार की तरह इस बार भी जातिवादी जुनून, सांप्रदायिक कट्टरता और मतदाता को लुभाने-भरमाने की कोशिशें लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रही है। चुनाव का समय सिटीजन ग्रुप्स से मिलकर, उनकी समस्याओं को सुनकर, उनके समाधान के लिए तत्पर होने का है। राजनीतिक दल अपनी जनता की मूलभूत समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी लें फिर उन समस्याओं के समाधान का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए जनता से वोट मांगें।

करोड़ों के प्रोजेक्ट हुए बर्बाद

राजधानी में करोड़ों रुपए के विकास कार्य अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गए, लेकिन इसका फायदा जनता को नहीं मिल पाया। बीआरटीएस की तरह ही अन्य प्रोजेक्ट भी शुरू होने के कुछ दिन बाद ही बंद होने की कगार पर पहुंच गए। इधर करोड़ों रुपए की स्मार्ट सिटी योजना भी अधर में अटकी है। बदहाल बीआरटीएस और मल्टीलेवल पार्किंग और धूल खाती स्मार्ट पार्किंग, प्लेस मेकिंग प्रोजेक्ट के तहत मार्केट में बदरंग-उधड़े फ्लोर टाइल्स और टूटे हुए गमले। ऐसे ही तमाम नामों वाले प्रोजेक्ट्स के बूते एक से डेढ़ दशक में आम शहरी को बड़े और सुनहरे सपने दिखाए गए। इन सपनों के नाम पर करोड़ों-अरबों रुपए खर्च भी कर दिए, लेकिन हालातों में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट्स फेल हो चुके हैं। यानी करोड़ों रुपए खर्च के बावजूद नतीजा सिफर ही है। यानी मिसरोद से बैरागढ़ सिहोर नाका तक 24 किमी का सफर महज 45 मिनट में तय होगा।

स्मार्ट पार्किंग- स्मार्ट पार्किंग को लेकर दावा किया गया था कि शहर के पुराने और नए शहर में 58 स्मार्ट पार्किंग एरिया होंगे। पार्किंग हाईटेक होगी, यानी यहां बाहर लगे डिस्प्ले पर पता चल जाएगा कि पार्किंग में स्पेस है या नहीं। पार्किंग से बाहर निकलने के लिए पार्किंग पर्ची पर प्रिंट बारकोड या क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन कराना होगा, तभी बूम बैरियर खुलेगा। सबसे अहम मोबाइल से पार्किंग स्पेस बुक किया जा सकेगा। सबकुछ ऑनलाइन होगा। जबकि हकीकत यह है कि स्मार्ट पार्किंग का काम माइंडटेक कंपनी को दिया गया। कंपनी ने 58 में से महज 30 पार्किंग स्पेस डेवलप किए। न तो कंपनी ने यहां सीसीटीवी कैमरे लगाए और न ही अन्य आधुनिक उपकरण। इस कारण गाड़ियां चोरी होने और कर्मचारियों द्वारा मनमानी वसूली की शिकायतें मिलीं। नगर निगम ने कंपनी को नोटिस दिया तो कंपनी ने काम छोड़ दिया। लिहाजा अब पार्किंग स्पेस कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। यहां कंडम वाहनों को खड़ा किया जा रहा है। जिस एप से पार्किंग स्पेस बुक करने का दावा किया गया वह कभी बन ही नहीं सका।

स्मार्ट स्ट्रीट- स्मार्ट स्ट्रीट को लेकर भी दावा किया गया था कि ज्योति टॉकीज चौराहे से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा स्मार्ट स्ट्रीट बनाई जाएगी। यहां कैफेटेरिया के साथ ही बच्चों के लिए गेम जोन होंगे। सायकिलिंग करने के साथ ही यहां सांप-सीढ़ी व अन्य पजल गेम खेले जा सकेंगे। यहां मेले और चौपाटी जैसा माहौल बनाया जाएगा। जबकि हकीकत में करीब पांच करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने के बावजूद ये विकसित नहीं हो पाई। इसे निजी एजेंसी के सुपुर्द कर दिया गया। जिसके बाद कंपनी ने इसे हॉकर्स कॉर्नर बना दिया। यहां जिस चौपाटी गेम जोन और कैफेटेरिया बनाने का दावा किया था, कुछ नजर नहीं आता।

बीआरटीएस की कहानी

बीआरटीएस 2009 में बनना शुरू हुआ था। इससे पहले ही लालघाटी पर ओवरब्रिज पर प्रस्ताव (2004) और भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट पर चर्चा (2007) में शुरू हो गई थी। ये बात और है कि कुछ कारणों से ये दोनों ही प्रोजेक्ट बहुत देरी से शुरू हुए, लेकिन इन्हें तो बनना ही था। इसके बावजूद 2011 में लालघाटी चौराहा और वीर सावरकर सेतु से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक बीआरटीएस की डेडीकेट लेन बना दी गई। बीआरटीएस की शुरुआत 2011 में शहर में 247 करोड़ रुपए से हुई थी। इस प्रोजेक्ट में अब तक 450 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यानी 10 सालों में विभिन्न एजेंसियों ने 203 करोड़ के आसपास मेंटेनेंस पर खर्च कर दिया। बीआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण के समय लागत 1 किमी पर 12 करोड़ आई थी। इस हिसाब से लालघाटी ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 500 मीटर कॉरिडोर तोड़ा गया, जिसकी लागत 6 करोड़ और मेंटेनेंस पर 1 करोड़ खर्च हुए थे। इसी तरह वीर सावरकर सेतु से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक 3.6 किमी कॉरिडोर मेट्रो प्रोजेक्ट और पीडब्ल्यूडी के फ्लाईओवर ब्रिज प्रोजेक्ट के कारण खत्म ही हो गया। इसके निर्माण और मेंटेनेंस पर 67 करोड़ खर्च हुए थे। यह बात सही है कि बीआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण के समय ना तो लालघाटी के ओवरब्रिज और ना ही मेट्रो प्रोजेक्ट की कोई ड्रॉइंग डिजाइन सामने आई थी। लेकिन यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि इन प्रोजेक्ट पर चर्चा शुरू हो गई थी।

माय बाइक- माय बाइक प्रोजेक्ट लांच करने से पहले दावा किया गया था कि शहर में साइकिलिंग कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। इससे आम शहरी की सेहत में सुधार के साथ ही यह वातावरण संरक्षण में अच्छी पहल होगी। साथ ही इलेक्ट्रिक बाइक भी शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। लोग शहर में कहीं भी जा सकेंगे। जबकि हकीकत यह है कि पांच करोड़ से 500 साइकिलों से शुरू हुआ प्रोजेक्ट अब लगभग खत्म हो गया है। साइकिल स्टेशन (डाकिंग यार्ड) में खड़ी स्मार्ट साइकिलें धूल खाते-खाते अब कबाड़ हो चुकी हैं। प्रोजेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जुड़ सका और लोगों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। इलेक्ट्रिक बाइक भी लोगों को पसंद नहीं आई और प्रोजेक्ट फेल हो गया।

वहीं बीआरटीएस 40 फीसदी से ज्यादा टूट चुका है। 121 किमी तक बढ़ने की बजाय ये 24 किमी से 12 किमी तक सिमट गया है। आम शहरी की गाड़ियां मिक्स लेन के नाम में उलझी रहती हैं। डेडीकेटेड कॉरिडोर में दौड़ने वाली बसें भी चार से पांच मिनट प्रति किमी से दौड़ रही हैं। राजधानी का बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी बीआरटीएस बेकाम का साबित हो चुका है। प्रोजेक्ट पर करीब 450 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 10 साल में ही तोड़-फोड़ पर 74 करोड़ पानी में चले गए। सरकार जब विकास का रोडमैप तैयार करती है तो अफसर उसे अमलीजामा पहनाने से पहले कम से कम 20-25 साल का विजन तैयार करते हैं। यानी उस प्रोजेक्ट से 25 साल तक क्या फायदे होंगे। इन सालों में प्रोजेक्ट के संचालन में कहीं कोई अड़चन तो नहीं आएगी, लेकिन राजधानी में सरकार और तमाम आला अफसरों की नाक के नीचे एक गैर-जरूरी प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए फूंक दिए गए और अब उसी रूट पर दूसरे प्रोजेक्ट आने से करोड़ों का नुकसान हुआ।

● **रजनीकांत पारे**

राहुल तैयार कर रहे खास वोटबैंक

भाजपा के हिंदुत्व-राष्ट्रवाद को तगड़ा काउंटर

वैसे भी इस समय जब भाजपा राष्ट्रवाद से लेकर हिंदुत्व तक की पिच पर जोरदार बैटिंग कर रही है, उस बीच कांग्रेस को अपनी खुद की सियासी पिच तैयार करने की जरूरत पड़ने वाली है। कॉमन मैन वाली ये पिच देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए मुफीद साबित हो सकती है क्योंकि ये वोटबैंक किसी जाति-धर्म पर आधारित नहीं है, ये तो बस उसे वोट करने वाला है जो उनके हक की बात करेगा। इन्हें ना राष्ट्रवाद के मुद्दों से ज्यादा फर्क पड़ता है, ना ही ये मंदिर-मस्जिद वाले विवाद में फंसते हैं। ऐसे में बिना भाजपा के नेरेटिव में फंसे अगर इस कॉमन मैन को अपने पाले में कर लिया गया तो कांग्रेस के अच्छे दिन फिर आ सकते हैं। अब सही दिशा में राहुल गांधी ने कदम जरूर बढ़ा दिए हैं, लेकिन उनकी ये वाली राह भी उतनी आसान नहीं रहने वाली है। इसका कारण है वो सियासी कॉम्पटीशन जो उन्हें इस डिपार्टमेंट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मिलने वाला है। असल में जिस रणनीति पर राहुल इस समय चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो उसी के सहारे अपनी राजनीतिक यात्रा को संवारा है। जनता से सीधा कनेक्ट ही उनकी वो ताकत रही जिसके दम पर वे तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री, तो वहीं दो बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की है, उनका सियासी सफर कुछ अलग अंदाज में आगे बढ़ता दिखा है। किसानों के साथ किसान बनने वाले भी राहुल हैं, ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात के दौरान ड्राइवर की भूमिका निभाने वाले भी राहुल हैं और रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत के दौरान खुद कुली बनने वाले भी राहुल ही हैं। ये अंदाज, ये सियासत, काफी कुछ बता रही है। इसके पीछे की मंशा साफ समझी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बिना किसी रणनीति के कांग्रेस नेता समाज के इन वर्गों से यूं मुलाकात कर रहे हैं। मौसम चुनावी है, ऐसे में हर दांव में सियासत की पूरी छाप भी दिखाई पड़ रही है। बात सबसे पहले राहुल गांधी के कुली वाले अवतार की करनी चाहिए। गत दिनों अचानक से कांग्रेस नेता दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां पर उन्होंने सिर्फ कुलियों से मुलाकात नहीं की, बल्कि उनकी तरफ से खुद भी एक कुली की भूमिका निभाई गई। उन्होंने बकायदा कुली वाले लाल कपड़े पहने, सिर पर सामान उठाया और कुछ देर तक दूसरे कुली साथियों के साथ चलते भी रहे। इसके बाद राहुल गांधी उन कुलियों के बीच ही बैठ गए, उनसे लंबी बातचीत की, उनकी चुनौतियों के बारे में जाना और वहां से चल दिए।

बड़ी बात ये है कि बाद में जब उन कुलियों से उस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो सभी ने एक सुर में कहा कि जो गरीबों के बीच रहेगा, वही गरीबों के दर्द को समझ पाएगा। राहुल गांधी के लिए अगर कोई ये बात कह रहा है, ये अपने आप में कांग्रेस नेता की पहली बड़ी जीत मानी जाएगी। यहां ये समझना जरूरी हो जाता है कि 2014 और फिर 2019 का जो लोकसभा चुनाव रहा था, उसमें भाजपा ने राहुल के खिलाफ नेरेटिव सेट किया था- ये लड़ाई कामदार बनाम नामदार की है। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने राहुल को शहजादा कहकर संबोधित किया था।

उस समय आम जनता के बीच में भी ये नेरेटिव सेट हो गया था कि राहुल गांधी को बिना मेहनत के पद दे दिया गया है, वे तो एक अमीर नेता हैं जिनका सरनेम गांधी है और उसी वजह से उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं। लंबे समय तक ये नेरेटिव राहुल से चिपका रहा और कांग्रेस को इसका पॉलिटिकल लॉस समय-समय पर मिला। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने सबसे पहले उस नेरेटिव पर कड़ा प्रहार किया। जिन राहुल के लिए एसी रूम में बैठने वाले नेता जैसे बयानों का इस्तेमाल हुआ, उन्होंने पैदल ही हजारों किलोमीटर की यात्रा कर डाली। किसानों से लेकर व्यापारियों तक, नौजवानों से लेकर महिलाओं तक, बुजुर्गों से लेकर दलित-आदिवासी तक, राहुल ने सभी से मुलाकात की।

वो वायरल वीडियो भी सभी के जहन में ताजा है जिसमें राहुल गांधी ने पंजाब के ट्रक डाइवरों से मुलाकात की थी। दिल्ली से अंबाला तक उन्होंने एक ट्रक में सफर किया, अपनी अत्याधुनिक और वीआईपी गाड़ी की कुर्बानी दी। उस यात्रा के दौरान राहुल ने खुद भी ट्रक चलाया, काफी देर तक उन ड्राइवरों से बात की, उनकी समस्यों को जानने का प्रयास किया। अब ये सब मायने रखता है, राजनीति में नेरेटिव और परसेप्शन वो कमाल कर सकता है जो कई मौकों पर जातीय समीकरण भी नहीं कर पाते हैं। जब 2014 के बाद से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रत्याशित सफलता का विश्लेषण किया जाता है, उसमें उनकी उपलब्धियां तो मायने रखती ही हैं, उससे ज्यादा वो नेरेटिव जरूरी हो जाता है जिसके दम पर कई बार मुश्किल में फंसी भाजपा की डगर भी बीच मझधार से निकल जाती है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वो फंडा समझ लिया है, इसी वजह से वे सिर्फ रैलियां या फिर सोशल मीडिया के जरिए जनता से संवाद स्थापित नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से तो सीधे जमीन पर जाकर लोगों से मुलाकात की जा रही है।

यहां भी ये लोग कहने को किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। ये ओबीसी हो सकते हैं, अति पिछड़े हो सकते हैं, शहरी हो सकते हैं, ग्रामीण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये सभी लोग आम आदमी हैं। ये देश का वो वर्ग है जो रोज मेहनत कर पैसा कमा रहा है, अपने परिवार का पेट पाल रहा है। राजनीति में जब अंतिम पंक्ति तक सभी को फायदा पहुंचाने की बात होती है, तो वो अंतिम पंक्ति ये आम लोग ही हैं। राहुल ने अपनी कुछ मुलाकातों के जरिए इन्हें ही साधने का काम किया है। दिखाने का प्रयास हुआ है कि राहुल गांधी आम लोगों के बीच में कितने सहज हैं, वे किस तरह से उनकी मुश्किलों को समझते हैं, वे किस तरह से आगे बढ़कर उनकी बात को सुनना चाहते हैं। वे सिर्फ अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरों की मन की बात को सुन रहे हैं। कांग्रेस के लिए चुनावी मौसम में ये वाला नेरेटिव काफी मददगार साबित हो सकता है। जो छवि 2014 के बाद से बन गई है, उसे तोड़ने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन उस दिशा में राहुल के कदम तेज गति से बढ़ चले हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

कैसे साफ हो गंगा?

गंगा थक चुकी मैला ढोते-ढोते

गंगा की सफाई को लेकर किए जा रहे सारे दावे कागजी साबित हो रहे हैं। भले ही 2016 में जोर-शोर के साथ गंगा के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन को लेकर आदेश जारी किया गया था लेकिन राष्ट्रीय नदी अब भी 60 फीसदी मैला ढो रही है। प्रमुख पांच गंगा राज्यों- बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उप्र और पश्चिम बंगाल में 10139.3 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज पैदा होता है और महज 3959.16 एमएलडी (40 फीसदी) सीवेज का ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए उपचार हो रहा है, बाकी 6180.2 एमएलडी (60 फीसदी) को सीधे गंगा में गिराया जा रहा है। गंगा के प्रमुख पांच राज्यों में अब तक लगाए गए कुल 226 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) भी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं और गंगा में सीधे गिरने वाले सीवेज की मात्रा में लगातार बढोत्तरी कर रहे हैं। एनजीटी ने गौर किया कि गंगा के प्रमुख पांच राज्यों में कुल 10139.3 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज के उपचार के लिए 5822.38 एमएलडी क्षमता वाले कुल 245 एसटीपी मौजूद हैं। हालांकि यह सभी एसटीपी अपनी क्षमता का महज 68 फीसदी ही काम कर रहे हैं। एनजीटी ने गौर किया कि 245 में कुल 226 एसटीपी ही काम कर रहे हैं। वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) सिर्फ 136 एसटीपी की निगरानी करती है, जिसमें से 105 ऑपरेशनल एसटीपी में 96 एसटीपी नियम और मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। नियम और मानक से मुराद यह है कि इन एसटीपी से निकलने वाले पानी में बीओडी, फीकल कॉलिफोर्म, टीएसएस जैसे मानक संतुलित नहीं पाए जाते हैं।

गंगा में 60 फीसदी सीवेज की निकासी जारी है वह भी तब जब राष्ट्रीय नदी के बिगड़े रंग-रूप को बदलने के लिए 30 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का बजट बनाया गया था। स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद के गठन को करीब छह वर्ष बीतने वाले हैं और अभी तक सिर्फ एक बार ही बैठक की जा सकी है। केंद्र सरकार की ओर से 7 अक्टूबर, 2016 को गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश जारी किया गया था, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद को वर्ष में कम से कम एक बार या उससे ज्यादा बार बैठक कर गंगा की सफाई और परियोजनाओं के अमल का जायजा लेना था।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के मुताबिक गंगा से जुड़ी परियोजनाओं के बजट और क्रियान्वयन को लेकर कार्यकारी समिति (एग्जीक्यूटिव कमेटी) की बैठकें जारी हैं। 2017 से लेकर जुलाई, 2022 तक कुल 43 बैठकें संपन्न हुई हैं। हालांकि, तय आदेश के मुताबिक गंगा परिषद को इनकी समीक्षा करनी चाहिए थी। 2014 में सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने गंगा की स्वच्छता को अपनी उच्च प्राथमिकता वाला काम बताया था और इसके लिए नमामि गंगे योजना की घोषणा की गई थी, जिसका मकसद गंगा के बिगड़े रंग-रूप को बदलना और प्रदूषण पर रोकथाम था। हालांकि, इस पर काम 2016, अक्टूबर के आदेश के बाद से ही शुरू हुआ। वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर 2020-2021 तक इस नमामि गंगे योजना के तहत पहले 20 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का रोडमैप तैयार किया गया था जो कि बाद में बढ़ाकर 30 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया। हालांकि, अभी इस स्वीकृत बजट में से करीब 50 फीसदी बजट ही आवंटित हो पाया है।

नमामि गंगे के तहत बड़े बजट की घोषणा दरअसल गंगा एक्शन प्लान की विफलता के बाद लाया गया था, जिससे जनता में गंगा की सफाई की उम्मीद जगाई गई थी। विफल रहे गंगा एक्शन प्लान को 14 जनवरी, 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शुरू किया था। इसके दो चरण कई वर्षों तक चले और नतीजा कुछ नहीं निकला। इसके बाद 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण बनाया गया। गंगा एक्शन प्लान से लेकर 2017 तक इन तीनों कदमों के तहत 6788.78 करोड़ रुपए सरकार की ओर से जारी किए गए। हालांकि, सरकार के मुताबिक 30 जून, 2017 तक 4864.48 करोड़ रुपए खर्च हो पाए। इन खर्चों पर संदेह भी उठा। अदालतों को भी इन खर्चों की सही जानकारी नहीं मिल पाई। एसटीपी या सीवेज नेटवर्क में पब्लिक का पैसा बर्बाद करने के लिए गंगा मामले में पहली बार सीबीआई जांच का भी आदेश दिया गया। हालांकि, सीबीआई जांच से जुड़ी कोई रिपोर्ट आजतक नहीं आई है। 14 फरवरी, 2017 को गंगा सफाई मामले में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने उप्र जल निगम के अधिकारियों पर हापुड़ जिले में गढ़ स्थित एसटीपी के डिजाईन और कस्ट्रक्शन में खराबी को लेकर सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एमसी मेहता मामले में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से गंगा एक्शन प्लान के खर्च की जानकारी दी गई थी लेकिन वह संतुष्ट करने लायक नहीं थी। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में 13 जुलाई, 2017 में फैसला सुनाते हुए कहा था कि गंगा इस वक्त देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है... कई वर्षों के बाद भी सरकार ने कई घरेलू और औद्योगिक सीवेज उपचार के लिए परियोजनाओं को गंगा एक्शन प्लान के तहत शुरू किया। हालांकि, यह गौर करने लायक है कि एक बड़ी राशि एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) पर खर्च होने के बाद भी नदी प्रदूषित है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 और 2017 में 1985 से चल रहे गंगा मामले की सुनवाई और निगरानी के लिए पर्यावरण मामलों की अदालत एनजीटी को निर्देश भेज दिया था। एनजीटी तबसे इस मामले की निगरानी कर रही है। 22 जुलाई, 2022 को एनजीटी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की ताजा रिपोर्ट के आधार पर कहा कि इतनी घोषणाओं के होने के बाद भी जुलाई, 2022 तक पांच प्रमुख गंगा राज्यों- उत्तराखंड, उप्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में 60 फीसदी बिना उपचार वाले सीवेज की निकासी जारी है। एनजीटी ने रिपोर्ट में पाया कि गंगा राज्यों में एसटीपी और सीईटीपी न सिर्फ 60 फीसदी तक कम हैं बल्कि अपनी क्षमताओं से भी कम काम कर रहे हैं।

● **प्रवीण सक्सेना**

साइबर ठगों की चपेट में मप्र

मप्र में ऑनलाइन लोन और जॉब के नाम पर बेरोजगार युवा ठगे जा रहे हैं। जालसाज जरूरत के हिसाब से लोन या जॉब ऑफर लेटर देते हैं। किसी ने लोन लिया है तो किस्त जमा करने का दबाव बनाते हैं। जालसाजों ने जॉब ऑफर की है तो कमीशन या टैक्स के नाम पर रुपए मांगते हैं। रुपए नहीं देने पर जालसाज मॉर्फिंग कर अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं। चाइल्ड और वीमेन पॉर्नोग्राफी तक के मामलों में फंसाया जाता है। स्टेट साइबर सेल में हर साल ऐसी एक लाख से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। सबसे ज्यादा मामले जॉब के नाम पर ठगी के हैं। अकेले भोपाल में बीते 8 महीने में ऐसे 730 केस सामने आ चुके हैं।

मप्र में दर्ज सभी केसों को 180 लोगों की टीम हैंडल करती है। स्टेट साइबर सेल के एडीजी योगेश देशमुख कहते हैं कि जब तक हम जालसाजों के किसी एक तरीके को क्रैक करते हैं, वो ठगी का दूसरा तरीका इजाद कर लेते हैं। आइए, पूरे मामले को दो केस से समझते हैं। आईटी से इंजीनियरिंग कर चुके जबलपुर के विजय के पास फोन आया कि विदेश की एक कंपनी वर्क फ्रॉम होम जॉब दे रही है। एक इंटरव्यू के घंटेभर बाद 10 लाख रुपए सालाना का ऑफर लेटर भी विजय के पास आ गया। फिर कंपनी की ओर से एक महिला ने बताया कि उनके देश में कानून है कि हर एम्प्लाई को सरकार को सालाना पैकेज का 10 प्रतिशत टैक्स देना होता है। ये टैक्स एडवांस पे होता है। इसे किस्तों में भी दिया जा सकता है।

विजय झांसे में आ गए और दो किस्तों में 40 हजार रुपए कंपनी के अकाउंट में डाल दिए। वह तीसरी किस्त देते इससे पहले उनके दोस्त ने उन्हें सतर्क कर दिया। विजय ने पैसे नहीं डाले। कंपनी वाले कहने लगे कि आप जल्दी से टैक्स जमा कीजिए नहीं तो ये नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। विजय ने साइबर सेल में शिकायत की। जांच में पता चला कि ये खाता नॉर्थ-ईस्ट के किसी स्टेट का था। वहीं दूसरा केस भोपाल में जुलाई में एक फेमिली सुसाइड का केस सामने आया था। इसमें क्रिमिनल्स ने पहले युवक को लोन फ्रॉड में फंसाया, फिर पैसा नहीं लौटाने पर उसकी अश्लील तस्वीर बनाकर वायरल कर दी। उस युवक ने मानसिक तनाव में आकर दो बेटों को जहर देने और पत्नी समेत सुसाइड करने का फैसला किया। मामले में जांच हुई तो पता चला जालसाजों के तार चीन तक जुड़े हुए हैं।

मप्र में हर साल साइबर अपराधों में 33 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। क्या गृहमंत्री सदन को बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल मंदसौर से भाजपा विधायक यशपाल सिंह ने अपनी ही सरकार से किया था। जवाब में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि पिछले सालों में 10 लाख 71 हजार 994 लोगों को जागरूक किया है। इस सामान्य जवाब से विधायक संतुष्ट नहीं होते। वो अगला सवाल करते हैं क्या साइबर मुख्यालय भोपाल में तकनीकी तौर पर क्रिटिकल केस की जांच के लिए एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है? क्या क्षेत्रीय थानों में बेसिक फोरेंसिक लैब और एडवांस्ड डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जा रही है? मंत्री जी जवाब देते हैं, हां लैब की स्थापना की गई है। जहां नहीं हुई है वहां प्रक्रिया जारी है।

विधायक यशपाल सिंह फिर सवाल करते हैं- राज्य में एक भी साइबर एक्सपर्ट नहीं, मंत्री जी आप ये बताइए अपराध कम कैसे होंगे? विधायक सिंह आंकड़ों के साथ अपनी बात रखते हैं और बताते हैं कि राज्य के 60 थानों में अब तक कुल 1643 लोगों के साथ 71 करोड़ 7 लाख 17 हजार 498 रुपए की ठगी हो चुकी है। सबसे ज्यादा ठगी 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच यानी कोविड काल में की गई है। इस एक साल में 444 केस में 29 करोड़ 1 लाख 60 हजार 800 रुपयों की साइबर ठगी हुई है। इसके बाद डॉ. नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि अगले तीन महीने में **एक्सपर्ट** की नियुक्ति कर दी जाएगी। आप सोचेंगे कि हम विधानसभा की कार्यवाही आपको क्यों बता रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को सदन में ये बात कहे पांच महीने पूरे होने को है, लेकिन साइबर अपराध रोकने के लिए अभी तक कोई भी एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी है।

स्टेट साइबर सेल के एडीजी योगेश देशमुख का कहना है कि हर साल हमारे पास 2 लाख के करीब शिकायतें आ रही हैं। इनमें से एक लाख शिकायतें तो केवल चाइल्ड और विमन पोर्नोग्राफी से संबंधित हैं। एडीजी स्वीकार करते हैं कि हम तकनीक, संसाधनों और बल में पिछड़ रहे हैं। 750 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, जो तकनीकी कारणों से उलझ गया है। जल्द ही 27 स्पेशल कंसलटेंट टीम जुड़ने वाली है।

20 अगस्त को भोपाल के मिंटो हॉल में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच सरकारी कर्मचारी आशुतोष के फोन में वाट्सऐप पर वीडियो कॉल आया। वो हड़बड़ाकर सभा से बाहर निकलते हैं। इसके बाद कॉल एक्सेप्ट करते हैं। कॉल उठाते ही उनकी स्क्रीन पर एक लड़की दिखती है। वो एक-एक कर अपने सारे कपड़े उतार रही है। आशुतोष पहले तो कुछ समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। मामला जब तक उनकी समझ में आया वीडियो कॉल रिकॉर्ड हो चुका था।

● **राकेश ग्रोवर**

भोपाल में सबसे ज्यादा ठगी नौकरी देने के नाम पर

इस मामले में क्राइम ब्रांच डीसीपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी का कहना है कि भोपाल में हर महीने नौकरी के नाम पर साइबर फ्रॉड से जुड़ी 91 से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। पिछले 8 महीनों में राजधानी के 730 लोगों से जालसाजों ने 2 करोड़ से ज्यादा ठग लिए हैं। हालांकि, ये लेखा-जोखा केवल उन लोगों की ही शिकायतों का है जो जोन कार्यालय तक पहुंचे थे। कॉल पर मिली शिकायतों का ब्यौरा भी शामिल करें तो इस साल अब तक दो हजार से ज्यादा लोगों को जालसाज फांस चुके हैं। ठगी गई रकम 6 करोड़ से अधिक हो सकती है। हमारे पास इस साल सबसे ज्यादा शिकायतें जॉब के नाम पर धोखाधड़ी को लेकर दर्ज हुई हैं। हैरानी की बात है कि 730 में से केवल 5 शिकायतों में ही अपराध कायम किए गए हैं। इसका मतलब है कि साइबर के मामलों में 0.6 प्रतिशत शिकायतों पर ही एफआईआर की जा रही है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी इन दिनों लगभग हर सभा में नौकरशाही में जाति के वर्चस्व की बात करते हैं। उनका मानना है कि सरकारें उच्च जातियों के ब्यूरोक्रेट्स को उच्च पदों पर बिठाती है। इसके लिए वे आंकड़ें भी पेश करते हैं। हालांकि उनकी इस बात को अधिकांश अफसर नकारते भी हैं। अफसरों का कहना है कि योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर अफसरों को उच्च पद दिया जाता है। दरअसल, चुनावी साल में जाति का मुद्दा उठाकर राजनीतिक माहौल गर्माया जा रहा है।

जाति की फांस में नौकरशाही?

कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में बोलते हुए एक ऐसी समस्या के तार छेड़ दिए, जिसे जानते तो सभी हैं, पर जिसके बारे में बड़े मंचों पर चर्चा नहीं होती। महिला आरक्षण के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करते हुए राहुल गंधी ने कहा कि वर्तमान सरकार में नौकरशाही के शिखर पदों यानी सेक्रेटरी पोस्ट पर सिर्फ तीन ओबीसी अफसर हैं। यानी देश की आधी से ज्यादा आबादी होने के बावजूद, ओबीसी के अफसर केंद्र सरकार के सिर्फ 5 प्रतिशत बजट के निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। इस मुद्दे को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों में भी उठाया और नरेंद्र मोदी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।

इसके जवाब में भाजपा और केंद्र सरकार ने ये तो नहीं कहा कि ओबीसी अफसरों पर राहुल गांधी का बताया हुआ आंकड़ा गलत है, पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी, तो उसने ओबीसी अफसरों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया। कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट किया कि इस समय वही अफसर सेक्रेटरी बन रहे हैं जो 1992 के आसपास सर्विस में आए थे, इसलिए कांग्रेस को बताना चाहिए कि ओबीसी अफसरों को आगे लाने में कांग्रेस की सरकारों ने कैसी भूमिका निभाई थी।

आगामी विधानसभा और फिर लोकसभा चुनावों तक ऐसा लगता है कि ओबीसी के मुद्दे पर काफी चर्चा होगी और इन सबके बीच नौकरशाही के टॉप पर ओबीसी अफसरों के न होने या कम होने पर काफी बातचीत होगी। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। पर उनका ये कहना पूरी तरह सही नहीं है कि इसकी सारी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सरकार की है। ये नौकरशाही की संरचना, उसके काम करने के तरीके और उसके जातिवादी चरित्र से जुड़ा मामला है और इस या उस पार्टी की सरकार के आने या जाने से इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस समस्या का समाधान करना है तो वह संरचना और प्रक्रिया के स्तर पर ही होगा।

यह है रिपोर्ट में

रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि इन वर्गों के बेहद कम अफसर ही सेक्रेटरी पद के लिए उपलब्ध होते हैं। लोक प्रशासन पर बनी कोठारी कमेटी ने तो जनरल ही नहीं, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए भी सिर्फ दो बार परीक्षा में बैठने की व्यवस्था बनाने की सिफारिश की थी। कई आयोग और समितियां इस बात पर एकमत हैं कि अफसर ज्यादा उम्र में सेवा में नहीं लिए जाने चाहिए। ये बेहद उपयोगी सुझाव है। दूसरे प्रशासनिक सुधार ट्रिब्यूनल ने सिफारिश की है कि सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने के लिए अनरिजर्व कैंडिडेट की उम्र 21 से 25 साल होनी चाहिए। ओबीसी के लिए इसमें तीन साल और एससी-एसटी के लिए अधिकतम उम्र में चार साल छूट देने की बात ट्रिब्यूनल ने की है। इस उम्र तक अगर अफसर नौकरी में आ जाते हैं तो इस बात की पूरी संभावना होगी कि हर अफसर सेक्रेटरी के लिए एंपैनल होने के काबिल बन पाएगा। दूसरा सुझाव पहली नजर में अटपटा लग सकता है, लेकिन अगर जिद है कि अफसर 32, 35 और 37 साल तक के हो सकते हैं तो ऐसा नियम बनाया जा सकता है कि अफसर चाहे जिस भी उम्र में आए, सबको समान कार्यकाल मिलेगा।

जानकार इसके लिए तीन समाधान प्रस्तावित करते हैं। अफसरों के सर्विस में आने की अधिकतम उम्र 29 साल हो और इसी दायरे के अंदर विभिन्न कैटेगरी को उम्र में जो भी छूट देनी हो, दी जाए, या फिर सभी अफसरों के सर्विस के साल यानी कार्यकाल बराबर किए जाएं, ताकि सभी कैटेगरी के अफसरों को सेवा के इतने वर्ष मिलें कि टॉप तक पहुंच पाएं। सर्विस के अलग-अलग स्तरों पर जब अफसरों को चुनने के लिए पैनल बनाया जाए तो ये प्रकिया पारदर्शी हो और इसमें मनमाने तरीके से किसी को चुन लेने और किसी को खारिज कर देने का वर्तमान चलन बंद हो। अफसरों की सालाना गोपनीय रिपोर्ट बनाने के मामले में जातिवाद पर अंकुश लगे और भेदभाव को प्रक्रियागत तरीके से सीमित किया जाए।

इन उपायों पर चर्चा करने से पहले जरूरी है कि इस विवाद के तीन पहलुओं पर आम सहमति बनाई जाए। सबसे पहले तो सरकार और नीति निर्माताओं को सहमत होना होगा कि भारतीय नौकरशाही के उच्च पदों पर सामाजिक विविधता का अभाव है और एससी, एसटी और ओबीसी के अफसर उच्च पदों पर बेहद कम हैं। राज्यसभा में इस बारे में 15 दिसंबर 2022 को पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय कार्मिक मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरकार की तरफ से जानकारी दी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी स्तर पर केंद्र सरकार में 322 पद हैं, जिनमें से एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल (अनरिजर्व) कैटेगिरी के क्रमशः 16, 13, 39

और 254 अफसर हैं। 2022 में ही 31 मार्च को राज्यसभा में ही पूछे गए सवाल के जवाब में डॉ. सिंह ने सदन को जानकारी दी कि भारत सरकार के 91 एडिशनल सेक्रेटरी में से एससी-एसटी के 10 और ओबीसी के 4 अफसर ही हैं। वहीं 245 ज्वाइंट सेक्रेटरी में से एससी-एसटी के 26 और ओबीसी के 29 अफसर ही हैं। यानी समस्या तो है।

हमें दूसरी सहमति इस बात पर कायम करनी चाहिए कि ये समस्या 2014 में पैदा नहीं हुई है जब नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे। बेशक उन्होंने इसे ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, पर समस्या पहले से ही चली आ रही है। मिसाल के तौर पर, यूपीए शासन के तुरंत बाद 2015 के आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र सरकार के 70 सेक्रेटरी में कोई ओबीसी नहीं था और एससी और एसटी 3-3 ही थे। 278 ज्वाइंट सेक्रेटरी में सिर्फ 24 ओबीसी थे जबकि 10 एससी और 10 एसटी थे। तीसरी सहमति इस बारे में कायम करनी चाहिए कि राजकाज और खासकर नौकरशाही में तमाम सामाजिक समूहों, खासकर वंचित समूहों की हिस्सेदारी न सिर्फ अच्छी बात है, बल्कि लोकतंत्र के लिए ये जरूरी भी है। किसी भी संस्था का सार्वजनिक या सबके हित में होना इस बात से भी तय होता है कि इसमें विभिन्न समुदायों और वर्गों की व्यापक हिस्सेदारी है या नहीं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस सवाल को बेहतरीन तरीके से उठाया था। जब उन्होंने पाया कि पुणे सार्वजनिक सभा में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्होंने पूछा कि फिर ये सार्वजनिक सभा कैसे हुई।

इस विचार को भारतीय संविधान ने मान्यता दी और अनुच्छेद 16(4) के तहत व्यवस्था की गई है कि अगर राज्य की नजर में किसी पिछड़े वर्ग का सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो सरकार उस वर्ग या वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देने के उपाय कर सकती है। इन तीन स्थापनाओं पर सहमति के बाद हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं, जिनकी वजह से एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों की नौकरशाही के उच्च तथा महत्वपूर्ण पदों पर हिस्सेदारी नहीं है। नौकरी में अलग-अलग उम्र में आना और कार्यकाल में अंतर सिविल सर्विस परीक्षा के लिए यूपीएससी के मापदंडों के हिसाब से

अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगिरी के कैंडिडेट की अधिकतम उम्र 32 साल हो सकती है। ओबीसी के कैंडिडेट को उम्र में तीन साल और एससी और एसटी कैंडिडेट को पांच साल की छूट है। यानी ओबीसी कैंडिडेट 35 साल तक और एससी-एसटी कैंडिडेट 37 साल की उम्र तक केंद्रीय सिविल सर्विस में आ सकते हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि एससी, एसटी और ओबीसी के कई कैंडिडेट, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के मुकाबले, कम समय नौकरी कर पाएंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा समय तक नौकरी कर रहे कैंडिडेट के बीच से ही टॉप की पोजिशन के लिए अफसर चुने जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से देखें तो सिविल सेवा के दो अफसरों के कार्यकाल में 16 साल तक का अंतर हो सकता है क्योंकि एक अफसर 21 साल की उम्र में और दूसरा अफसर 37 साल की उम्र में सर्विस में आ सकता है।

दूसरी समस्या उच्च पदों के लिए एंपैनलमेंट में है। अभी व्यवस्था है कि भारत सरकार का कार्मिक विभाग नियत समय की सर्विस में पूरी कर चुके अफसरों से पूछता है कि क्या वे विभिन्न उच्च पदों के लिए एंपैनल होना चाहते हैं। जो अफसर सहमति जताते हैं उनमें से सरकार कुछ अफसरों को उन पदों के पैनल में चुन लेती है। इसी पैनल से अफसरों को निर्धारित प्रमोशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अभी पैनल में अफसरों को लेने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसमें विभाग के उच्चाधिकारियों का मंतव्य यानी उनकी राय महत्वपूर्ण होती है। चूंकि उच्च पदों पर एससी, एसटी, ओबीसी के अफसर कम हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के अफसरों के प्रति एक स्वाभाविक पक्षपात हो सकता है। कम-से-कम इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि इस प्रक्रिया में पक्षपात की आशंका को न्यूनतम किया जाए और विभिन्न मापदंडों को स्कोर के आधार पर निर्धारित किया जाए। अगर ऐसा कोई निष्पक्ष सिस्टम बना पाना संभव न हो तो फिर जिन अफसरों ने निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लिया है, उनमें सभी को पैनल में ले लिया जाए। दूसरे प्रशासनिक सुधार ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट ने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट औसतन 24.7 साल की उम्र में सेवा में आता है, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी के अफसर क्रमशः 27.6, 26.9 और 27.1 साल की उम्र में सेवा में आते हैं। यानी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट औसतन अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट से तीन साल कम नौकरी करते हैं। प्रशासनिक सुधार ट्रिब्यूनल के मुताबिक, रिजर्व कटेगरी के कई अफसर इस वजह से नीति निर्माता के स्तर पर नहीं पहुंच पाते।

● **कुमार विनोद**

पक्षपात को साबित करना संभव नहीं

एक और महत्वपूर्ण पहलू, किसी अफसर को काबिल और ईमानदार मानने या न मानने को लेकर है। हालांकि, प्रशासनिक सेवाओं में जाति आधारित पक्षपात को साबित करना हमेशा संभव नहीं है, लेकिन उच्च पदों पर उनकी लगभग अनुपस्थिति को देखते हुए इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जब 22.5 फीसदी एससी-एसटी तथा 27 फीसदी ओबीसी अफसर सर्विस में आ रहे हैं तो वे बीच में कहां अटक जा रहे हैं। दूसरे प्रशासनिक सुधार ट्रिब्यूनल ने सालाना रिपोर्ट लिखने के मामले में पक्षपात कम करने के लिए ये सिफारिश की थी कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ग्रेड किसी भी स्तर पर सिर्फ 5 से 10 फीसदी अफसरों को ही दिया जाए। साथ ही ये सिफारिश भी की गई थी कि सालाना गोपनीय रिपोर्ट की जगह एक नया सिस्टम लाया जाए, जिसमें कार्यभार पूरा करने जैसे स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले मानकों के आधार पर किसी अफसर का मूल्यांकन हो। सरकार अगर सचमुच नौकरशाही के उच्च पदों पर सामाजिक विविधता लाना चाहती है, तो उसे इन उपायों पर विचार करना चाहिए।

महामारी बन रहा डेंगू

एक दशक पहले तक डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां दिल्ली जैसे महानगरों में ही पाई जाती थीं और देश के अन्य क्षेत्रों के लोग टीवी, अखबार के मार्फत ही जानते थे कि राजधानी में डेंगू, चिकनगुनिया जैसी भी बीमारियां होती हैं। वहीं छोटे शहरों में मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड, जापानी बुखार (इंसेफेलाइटिस), चमकी बुखार आदि बीमारियां होती थीं। अब छोटे शहरों के साथ-साथ कस्बों और गांवों तक डेंगू भी तेजी से फैल रहा है। चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली जैसे महानगरों में इस साल भी डेंगू का प्रकोप दिखा है, पर इनसे ज्यादा भयावह स्थिति उत्तराखंड, उप्र और बिहार की है, जहां डेंगू महामारी बन चुका है। उप्र के कई शहरों में डेंगू का प्रकोप है। पिछले साल प्रयागराज डेंगू का केंद्र बना हुआ था, जहां दर्जनों लोगों की डेंगू से मौत हुई थी। तब एक कारण यह बताया गया था कि डेंगू गंगा-जमुना के किनारे वाले उन क्षेत्रों में फैला, जहां बाढ़ का पानी घुसा था। लेकिन इस साल तो सूखा पड़ा हुआ है। महानगरों की अपेक्षा छोटे-पिछड़े शहरों में डेंगू का संक्रमण दर भी बहुत ज्यादा है। डेंगू से हुई मौत की चपेट में भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग ज्यादा आ रहे हैं। उप्र की अगर बात करें, तो 18 अक्टूबर तक करीब दो दर्जन मौतें हो चुकी थीं। ज्यादातर गांव के लोगों का आरोप है कि एएनएम और आशा वर्कर्स द्वारा किसी भी तरह का जन जागरूकता कार्यक्रम या जानकारी, जरूरी दवाएं और ब्लीचिंग पाउडर आदि का वितरण नहीं किया गया है। न समय रहते कहीं छिड़काव करवाया गया।

बता दें कि डेंगू संक्रमित एडीज एजिप्टी नामक मादा मच्छर के काटने से होता है। आमतौर पर इसमें मरीज को कम-से-कम तीन दिन बुखार जरूर रहता है। डेंगू बुखार तीन तरीके का होता है- साधारण डेंगू, डेंगू हैमरेजिक बुखार (डीएचएफ) और शॉक सिंड्रोम डेंगू (डीएसएस)। अलग-अलग निजी पैथोलॉजी में डेंगू का टेस्ट आमतौर पर 1000-1600 रुपए में होता है। पैसे की कमी के चलते अधिकांश गरीब लोग बुखार आने पर इलाज के लिए झोलाछाप डॉक्टरों के पास जाते हैं। दरअसल क्षेत्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के दो प्रमुख बुनियादें- प्राथमिक स्वास्थ्य (पीएचसी) केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) खस्ताहाल हैं। यहां पर कभी जांच किट नहीं होती, तो कभी दवाइयां। घंटों लाइन में लगने के बाद नंबर लगाकर डॉक्टर तक पहुंचने पर वह मरीज को देखकर जांचें और दवाइयां लिख देते हैं।

4 एजेंसियों ने नहीं निभाई जिम्मेदारी

मप्र में डेंगू मरीजों की संख्या 4 हजार के पार पहुंच गई है। इसके पीछे सरकारी एजेंसियों की लापरवाही रही है। राजधानी भोपाल में जनवरी में डेंगू मरीजों की संख्या 20 थी। ये आंकड़ा बढ़ते-बढ़ते अब 674 के पार पहुंच गया है। इससे जाहिर है कि हमारा हेल्थ सिस्टम भी डेंगू पीड़ित है, जो अपनी नाकामी छिपाने के लिए बारिश को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। प्रदेश में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज भोपाल में ही मिले हैं। अफसरों का कहना है कि इस बार रुक-रुक कर देर तक बारिश हुई है। सुबह और शाम को मौसम ठंडा रहता है, लेकिन दोपहर में धूप रहती है। दिन में मौसम ठंडा नहीं होने की वजह से लार्वा पनपता है। डेंगू के मच्छर के लिए ये समय सबसे उपयुक्त होता है। हालांकि बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों की खामी पर अफसरों ने कोई बात नहीं की। जिला मलेरिया कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल में रोजाना औसतन 9 नए डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सितंबर में रोजाना मिल रहे औसतन मरीजों की संख्या 5 थी। शहर में डेंगू के बढ़ते संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। अब जिला मलेरिया कार्यालय से संबद्ध कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं।

सवाल है जब दवाइयां और जांच दोनों के लिए पैसा ही खर्च करना है, तो फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्यों जाना? दिहाड़ी पेशा लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, ऊपर से उनके तीमारदार के काम का नुकसान होता है। ज्यादातर मरीजों का इलाज उधार के पैसों से होता है। नीम-हकीम यानी झोलाछाप छोटी-मोटी मौसमी बीमारियों का इलाज तो कर देते हैं; लेकिन डेंगू जैसी बड़ी बीमारियों में जब मरीज की हालत गंभीर हो जाती है, तब ये लोग पल्ला झाड़कर जिला अस्पताल रेफर कर देते हैं। लेकिन कई बार देर होने के चलते रास्ते में ही मरीज की मौत हो जाती है। यह एक भयावह आंकड़ा है कि हर साल पांच करोड़ लोग महंगे इलाज के चलते गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। मौजूदा सरकार गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना का ढोल पीट रही है। पर 8 अगस्त 2023 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट ने आयुष्मान योजना के आंकड़ों में फर्जीवाड़े की पोल खोलकर रख दी कि कैसे एक फर्जी मोबाइल नंबर-9999999999 से 7.50 लाख आयुष्मान कार्ड जुड़े हुए हैं। 1.39 लाख आयुष्मान कार्ड एक अन्य फर्जी मोबाइल नंबर-8888888888 से और लगभग एक लाख आयुष्मान कार्ड एक अन्य फर्जी मोबाइल नंबर-9000000000 से जुड़े मिले। यानी आयुष्मान भारत योजना एक जीता जागता फर्जीवाड़ा है। आयुष्मान कार्ड बनाने का जिम्मा ग्रामीण स्तर पर आशाकर्मियों के जिम्मे है।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता डॉ. आशीष मित्तल कहते हैं कि डेंगू एक सामान्य संचारी बीमारी है और सामान्य चिकित्सा सुविधाओं से इसका पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने इसे लगातार नजरअंदाज किया है, जिससे स्थितियां दिन-ब-दिन विकट रूप लेती चली गई हैं। इस पर समुचित मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। कोरोना महामारी के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया जाना चाहिए था; लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को निजी क्षेत्र के भरोसे छोड़ दिया है। जो गलत इलाज करके मरीज से मोटा पैसा बनाते हैं। निजी क्षेत्र के अस्पतालों की प्राथमिकता में निजी स्वास्थ्य बीमा वाले ग्राहक मरीज होते हैं। वो इलाज करते नहीं, बेचते हैं; जिसे गरीब व्यक्ति नहीं खरीद सकता। उसके लिए सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को ही पुनर्जीवन देना होगा। साथ ही बारिश के मौसम में साफ-सफाई, पानी की निकासी और डेंगू से जुड़े जन जागरूकता के कार्यक्रमों को चलाने वाले निकायों को चुस्त-दुरुस्त करना होगा।

● **विकास दुबे**

तीन गुणा बढ़ जाएगी भूजल में गिरावट की दर

दुनियाभर में बढ़ता तापमान अपने साथ अनगिनत समस्याएं भी ला रहा है, जिनकी जद से भारत भी बाहर नहीं है। ऐसी ही एक समस्या देश में गहराता जल संकट है जो जलवायु में आते बदलावों के साथ और गंभीर रूप ले रहा है। इस बारे में अंतराष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा किए नए अध्ययन से पता चला है कि बढ़ते तापमान और गर्म जलवायु के चलते भारत आने वाले दशकों में अपने भूजल का कहीं ज्यादा तेजी से दोहन कर सकता है। अनुमान है कि इसके चलते 2040 से 2080 के बीच भूजल में आती गिरावट की दर तीन गुणा बढ़ सकती है। इस रिसर्च के नतीजे एक सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल साइंस एडवांसेज में प्रकाशित हुए हैं।

गौरतलब है कि भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में पहले ही कहीं ज्यादा तेजी से अपने भूजल का दोहन कर रहा है। आंकड़ों से पता चला है कि भारत में हर साल 230 क्यूबिक किलोमीटर भूजल का उपयोग किया जा रहा है, जो कि भूजल के वैश्विक उपयोग का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। देश में इसकी सबसे ज्यादा खपत कृषि के लिए की जा रही है। देश में गेहूं, चावल और मक्का जैसी प्रमुख फसलों की सिंचाई के लिए भारत बड़े पैमाने पर भूजल पर निर्भर है। लेकिन जैसे-जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, खेत तेजी से सूख रहे हैं। इसके साथ ही मिट्टी में नमी को सोखने की क्षमता भी घट रही है, जिसकी वजह से भारत में भूजल स्रोतों को रिचार्ज होने के लिए पर्याप्त जल नहीं मिल रहा है। नतीजन साल दर साल देश में भूजल का स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। अनुमान है कि बढ़ते तापमान के साथ जल उपलब्धता में आने वाली इस गिरावट के चलते एक तिहाई लोगों की जीविका पर खतरा मंडराने लगेगा। इसके न केवल भारत में बल्कि वैश्विक परिणाम भी सामने आएंगे। साथ ही इससे देश में खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। इस बारे में अध्ययन से जुड़ी वरिष्ठ लेखक और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के स्कूल फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में सहायक प्रोफेसर मेहा जैन का कहना है कि, भारत में किसान बढ़ते तापमान से निपटने के लिए अधिक सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जिस पर भूजल में आती गिरावट के पिछले अनुमानों के बारे में विचार नहीं किया गया है।

उनके मुताबिक यह चिंताजनक है क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल का उपयोग करने वाला देश है जो क्षेत्रीय और वैश्विक खाद्य उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बता दें कि अपने इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने भारत में भूजल को होने वाले नुकसान की दरों का अनुमान लगाने के लिए 10 जलवायु मॉडलों से प्राप्त बारिश और तापमान के अनुमानों का उपयोग किया है। अध्ययन में इस बात पर गौर किया गया है कि देश में बढ़ते तापमान के चलते फसलों पर पड़ने वाले दबाव से निपटने के लिए पानी की मांग बढ़ सकती है। इसकी वजह से किसानों को फसलों की सिंचाई में वृद्धि कर सकती है।

रिसर्च के अनुसार बढ़ते तापमान और सर्दियों में बारिश में आती गिरावट के चलते भूजल में गिरावट आ रही है, जिसकी भरपाई मानसून में होने वाली अतिरिक्त बारिश भी नहीं कर पा रही। इस बारे में अध्ययन और ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय से जुड़े निशान भट्टराई का कहना है कि यदि तापमान में होती वृद्धि इसी तरह जारी रहती है तो बढ़ते तापमान से भूजल में आती गिरावट की दर तीन गुणा बदतर हो सकती है, जो दक्षिण और मध्य भारत के क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगी। उनके मुताबिक जब तक हम भूजल को बचाने के उपाय नहीं करते, तब तक बढ़ते तापमान से भारत में भूजल से जुड़ी मौजूदा समस्याएं और बदतर हो जाएंगी। इससे देश में बदलती जलवायु के साथ खाद्य और जल सुरक्षा के लिए अतिरिक्त चुनौतियां पैदा हो जाएंगी। अपने इस हालिया अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने कई स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को एकत्र किया है और उनका एक डेटासेट तैयार किया है। इसमें देश के हजारों कुओं में भूजल के स्तर, फसलों पर बढ़ता जल तनाव और उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के साथ मौसम संबंधी रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है।

पिछले अध्ययनों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जलवायु में आते बदलावों के चलते 2050 तक देश की प्रमुख फसलों की उपज में 20 फीसदी तक की कमी आ सकती है। इसके साथ ही, देश में भूजल का स्तर चिंताजनक दर से कम हो रहा है, जिसका मुख्य कारण सिंचाई के लिए भूजल का बढ़ता दोहन है। बता दें कि दुनियाभर में भूमिगत जल, साफ पानी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला स्रोत हैं। आंकड़ों की मानें तो वैश्विक स्तर पर करीब 200 करोड़ लोग, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और सिंचाई के लिए भूजल पर ही निर्भर हैं। रिसर्च के अनुसार दुनिया की 20 फीसदी आबादी इन भूजल स्रोतों द्वारा सिंचित फसलों का उपभोग कर रही है। हालांकि बढ़ती आबादी और उनकी जरूरतों के साथ इन भूजल स्रोतों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

आज उठाए कदमों पर निर्भर है कल का भविष्य

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में जारी आंकड़ों से पता चला है कि 2050 तक शहरों में पानी की मांग 80 फीसदी तक बढ़ जाएगी। वहीं यदि मौजूदा आंकड़ों पर गौर करें तो दुनियाभर में शहरों में रहने वाले करीब 100 करोड़ लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। वहीं अनुमान है कि अगले 27 वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 240 करोड़ तक जा सकता है। इससे भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, जहां पानी को लेकर होने वाली खींचातानी कहीं ज्यादा गंभीर रूप ले लेगी। गौरतलब है कि भूजल के संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने मार्च 2018 में अटल भूजल योजना का प्रस्ताव रखा था। जिसे विश्व बैंक की सहायता से 2018-19 से 2022-23 की पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाना है। इस योजना का लक्ष्य गिरते भूजल का गंभीर संकट झेल रहे सात राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मप्र, राजस्थान और उप्र में संयुक्त भागीदारी से भूजल का उचित और बेहतर प्रबंधन करना है। भारत में गिरते भूजल की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जलदूत नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इसका मकसद भारत के गांवों में गिरते भूजल के जलस्तर का पता लगाना है, जिससे पानी की समस्या को दूर किया जा सके। जल जीवन है, लेकिन जिस तरह से देश में इसका दोहन और कुप्रबंधन किया जा रहा है, उसके आने वाले वक्त में गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

अर्थव्यवस्था के सामने बेरोजगारी की चुनौती

कृषि क्षेत्र में ज्यादातर रोजगार मौसमी

भारत में रोजगार मुहैया कराने के लिहाज से कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था का यह इकलौता क्षेत्र है, जो घाटे के बावजूद बंद नहीं होता। यहां श्रमशक्ति का लगभग 45-50 फीसदी हिस्सा रोजगार पाता है। कृषि क्षेत्र में ज्यादातर रोजगार मौसमी होते हैं। फिर भी इस क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाए तो भारत की बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है। सरकार के लिए यह प्राथमिकता का क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन स्थिति इसके उलट है। मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में कृषि क्षेत्र का आवंटन घटा कर कुल बजट का 2.7 फीसदी कर दिया गया, जबकि 2022-23 में यह आवंटन कुल बजट का 3.36 फीसदी था। धनराशि के मामले में हालांकि आवंटन पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले 4.7 फीसदी अधिक है। लेकिन पिछले वित्त वर्ष के बजटीय प्रस्ताव से सात फीसदी कम। दूसरी तरफ कुल श्रमशक्ति के लगभग 12 फीसदी हिस्से को रोजगार देने वाले विनिर्माण क्षेत्र के लिए सभी सुविधाएं सुलभ हैं। वर्ष 2016 में आईबीसी कानून लाया गया, सितंबर 2019 में कॉरपोरेट कर 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया गया और महामारी के बीच उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लाई गई।

कृषि अर्थव्यवस्था का इकलौता क्षेत्र है, जो घाटे के बावजूद बंद नहीं होता। यहां श्रमशक्ति का लगभग 45-50 फीसदी हिस्सा रोजगार पाता है। कृषि क्षेत्र में ज्यादातर रोजगार मौसमी होते हैं। फिर भी इस क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाए तो भारत की बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है। कोई अवस्था लंबी अवधि तक बनी रहे तो उसके प्रति सहज भावना पैदा होने लगती है। यह सहजता धीरे-धीरे स्थायी हो जाती है। एक सीमा के बाद दर्द का अहसास न होना इसी प्रक्रिया का परिणाम है। बेरोजगारी के साथ भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का स्थायी भाव अच्छा संकेत नहीं है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मासिक औसत बेरोजगारी दर 7.6 फीसदी के उच्चस्तर पर बनी रही। लेकिन कहीं से कोई खास विमर्श का स्वर सुनाई नहीं पड़ा। ऐसा लगता है कि शायद बेरोजगारी का अहसास जाता रहा! यह मानव मन में बेरोजगारी के सहज हो जाने का संकेत है। बेरोजगारी का स्थायी भाव अस्थिरता है। यानी बेरोजगारी जितनी स्थायी होगी, अस्थिरता उतनी ही बढ़ती जाएगी।

अस्थिरता क्या कुछ करती है, बताने की जरूरत नहीं। मनोभावों के बदलने से आंकड़े नहीं बदलते। अलबत्ता आंकड़े मनोभावों को बदल देते हैं। बेरोजगारी का सवाल आंकड़ों से आगे का है और मानव मन आज इसी सवाल में उलझकर रह गया है। बेरोजगारी के आंकड़े इतने भारी हो गए हैं कि अब इन्हें न तो मानव मन ढो पाने की स्थिति में है, और न अर्थव्यवस्था ही। सेंटर फॉर मानीटरिंग इंडियन इकोनामी (सीएमआईई) के अनुसार, बीते वित्त वर्ष में उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक की औसत मासिक वृद्धि दर 2.68 फीसदी रही। इस धीमी वृद्धि दर का परिणाम है कि उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक महामारी से पूर्व के स्तर पर आज तक नहीं पहुंच पाया। मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक भी उस स्तर पर पहुंचने की संभावना कम है। महामारी से ठीक पहले फरवरी 2020 में उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक 105.3 पर था, जो मार्च 2023 में 89.18 पर दर्ज किया गया। मानसून पर संभावित अल नीनो प्रभाव और निजी निवेश में अनवरत सुस्ती के मद्देनजर मौजूदा वित्त वर्ष में भी उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक का संभवत: यही हाल रहने वाला है।

उपभोक्ता मनोभाव का ऊपर उठना आमदनी पर निर्भर करता है और ऊंची बेरोजगारी दर इसकी संभावना को धूमिल कर देती है। जाहिर है, इसका असर अर्थव्यवस्था पर होगा और अर्थव्यवस्था का असर मानव जीवन पर, सामाजिक ताने-बाने पर। बीते वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में विकास दर घटकर 4.4 फीसदी रह गई और चौथी तिमाही में इसके और नीचे जाने की आशंका है। वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच मौजूदा वित्त वर्ष का परिदृश्य भी सुखद नहीं है। वैश्विक वित्तीय एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान घटा दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 6.1 फीसदी के अपने अनुमान को घटाकर 5.90 फीसदी कर दिया। विश्व बैंक ने 6.6 फीसदी के अनुमान को घटाकर 6.3 फीसदी और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने अपने अनुमान को 7.2 फीसदी से घटाकर 6.4 फीसदी कर दिया है। नोमुरा के अनुसार, भारत की वृद्धि दर मौजूदा वित्त वर्ष में 5.3 फीसदी रहनी है। बेशक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौजूदा वित्त वर्ष की अपनी पहली नीतिगत समीक्षा में विकास दर अनुमान को 6.4 फीसदी से बढ़ाकर 6.5 फीसदी किया, लेकिन विशेषज्ञों की नजर में यह अति आशावादी आंकड़ा है।

बेरोजगारी दर के आंकड़े दो प्रवृत्तियों से प्रभावित होते हैं- श्रमिक भागीदारी दर और रोजगार सृजन। श्रम बाजार में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ गई और उसके अनुसार रोजगार सृजन नहीं हुआ तो बेरोजगारी दर ऊंची दिखेगी। रोजगार सृजन नहीं भी हुआ, मगर श्रमिक भागीदारी घट गई तो बेरोजगारी दर नीचे दिखेगी। लेकिन यहां तो श्रमिक भागीदारी घटने के बाद भी बेरोजगारी दर बढ़ रही है। सीएमआईई के अनुसार, मार्च 2023 में श्रमिक भागीदारी दर घटकर 39.8 फीसदी रह गई, जो फरवरी 2023 में 39.9 फीसदी थी। लेकिन बेरोजगारी दर फरवरी के 7.5 फीसदी से बढ़कर मार्च में 7.8 फीसदी हो गई। अप्रैल 2023 में श्रमिक भागीदारी दर और बेरोजगारी दर दोनों में वृद्धि हुई। श्रमिक भागीदारी दर मार्च 2023 के 39.8 फीसदी से बढ़कर अप्रैल 2023 में 41.98 फीसदी दर्ज की गई और बेरोजगारी दर फरवरी 2023 के 7.8 फीसदी से बढ़कर मार्च 2023 में 8.11 फीसदी हो गई। अप्रैल 2023 की श्रमिक भागीदारी दर पिछले तीन सालों में सर्वाधिक है। महामारी की शुरुआत, यानी मार्च 2020 में श्रमिक भागीदारी दर 41.9 फीसदी थी और तब बेरोजगारी दर 8.74 फीसदी थी। उसके बाद से श्रमिक भागीदारी दर लगातार 41 फीसदी से नीचे रही है। अप्रैल 2023 का यह रुझान आगे टिका रहेगा, संभावना कम है। सवाल उठता है आखिर बेरोजगारी की समस्या स्थायी क्यों होती जा रही है और इसका समाधान क्या है? आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू होने के बाद से भारत का सार्वजनिक क्षेत्र लगातार सिमट रहा है। ऐसे में रोजगार पैदा करने का दारोमदार निजी क्षेत्र पर है। निजी क्षेत्र मुनाफे के लिए काम करता है। निवेश तभी करता है, जब मुनाफे के साथ लागत की वापसी का भरोसा हो।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

विद्यार्थियों की आत्महत्या के डराते आंकड़े

दुनियाभर में खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा काफी चिंताजनक है। लोगों में अवसाद निरंतर बढ़ रहा है, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसा हृदय विदारक कदम उठा बैठते हैं। जीवन से निराश होकर आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर चिंता का सबब बन रही है। देश के प्रमुख कोचिंग केंद्र बने राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर अत्यधिक मानसिक दबाव के कारण जब-तब विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अब आईआईटी जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थानों और कुछ अन्य प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में भी विद्यार्थियों की आत्महत्या के मामले समाज को झकझोरने लगे हैं।

कोटा में 8 से 25 मई के बीच ही चार छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें सामने आईं। पिछले दिनों सीबीएसई की बारहवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आने पर केवल दिल्ली में ही तीन छात्रों की आत्महत्या की खबर भी स्तब्ध करने वाली थी। ये तीन ऐसे मामले हैं, जो देश की राजधानी से मीडिया की सुर्खियों में आए। लेकिन ऐसे न जाने कितने ही मामले देश के दूरदराज के इलाकों में घटित होते रहते हैं, लेकिन वे मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पाने के कारण लोगों की नजरों में नहीं आ पाते।

चिंताजनक स्थिति यह बनती जा रही है कि परीक्षाओं के दौरान प्रश्नपत्र सही से हल नहीं कर पाने और कई बार परीक्षा की समुचित तैयारी नहीं होने पर भी कुछ मामलों में अब कुछ विद्यार्थी हताश होकर जान देने लगे हैं। दसवीं या बारहवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम हों या फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाएं, ऐसी परीक्षाओं में सफल नहीं होने के कारण कुछ छात्र अब आत्महत्या जैसा हृदय विदारक कदम उठाने लगे हैं। युवाओं में आत्महत्या की यह बढ़ती प्रवृत्ति अब सभी को गंभीर चिंतन-मनन के लिए विवश करने के लिए पर्याप्त है। विद्यार्थियों की आत्महत्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो बहुत चिंताजनक तस्वीर उभरकर सामने आती है। राज्यसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार 2018 से 2023 के बीच पांच वर्षों की अवधि में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम जैसे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में ही 61 छात्रों ने आत्महत्या की, जिनमें 33 छात्र आईआईटी के थे।

देश के युवा वर्ग और खासकर 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में आत्महत्या की बढ़ती यह प्रवृत्ति बेहद चिंताजनक है। शिक्षा और करियर में गलाकाट प्रतिस्पर्धा और माता-पिता और शिक्षकों की बढ़ती अपेक्षाओं के चलते विद्यार्थियों पर पढ़ाई का बढ़ता अनावश्यक दबाव इसका सबसे बड़ा कारण है, जिसने उनके समक्ष विकट स्थिति पैदा कर दी है। कई बच्चे इस दबाव को झेल नहीं पाते, जिसके चलते उनमें अवसाद पनपता है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि परीक्षाएं नजदीक आने के साथ ही विद्यार्थियों में चिंता और अवसाद बढ़ने लगता है और कुछ मामलों में यही बढ़ता अवसाद उनके आत्महत्या करने का कारण बन जाता है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में तो सीटें बहुत होने के कारण अब बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा होने लगी है, वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थानों में सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी अब जबरदस्त मारामारी होने लगी है। ऐसे में विद्यार्थी अपनी शिक्षा और भविष्य को लेकर गहरे असमंजस में रहते हैं। किसी को करियर या नौकरी की चिंता है तो कोई पारिवारिक वित्तीय संकट से जूझ रहा है। परीक्षा में अपेक्षा से कम या रैंक मिलने पर कुछ बच्चे आत्महत्या का मार्ग चुन लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंकों की दौड़ में पिछड़ जाने के कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें तो जहां 2020 में देशभर में कुल 12,526 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की, वहीं 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 13,089 हो गया। आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों में 56.54 फीसद लड़के और 43.49 फीसदी लड़कियां थीं। 18 साल से कम आयु के 10,732 किशोरों में से 864 ने तो परीक्षा में विफलता के कारण मौत को गले लगा लिया। 2021 के एनसीआरबी के आंकड़े समाज को झकझोरने के लिए पर्याप्त हैं। यों आत्महत्या की यह समस्या अब केवल विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में आत्महत्या के मामलों में जिस प्रकार साल दर साल उछाल आ रहा है, वह समूचे समाज के लिए गंभीर चिंता का कारण बन रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। यानी प्रतिवर्ष दुनियाभर में करीब 8 लाख लोग आत्महत्या के जरिए अपनी जीवनलीला खत्म कर डालते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में आत्महत्या के मामले 15 से 29 वर्ष के लोगों के बीच होते हैं, जबकि आत्महत्या का प्रयास करने वालों का आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा है। किसी राजनीतिक दल के लिए विद्यार्थियों की आत्महत्याएं भले ही कोई चुनावी मुद्दा न हों, लेकिन समाज के लिए ये आत्महत्याएं चिंतनीय और दुर्भाग्यपूर्ण अवश्य हैं।

● **लोकेंद्र शर्मा**

79 फीसदी आत्महत्या निम्न और मध्यवर्ग वाले देशों में

डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर में 79 फीसदी आत्महत्या निम्न और मध्यवर्ग वाले देशों के लोग करते हैं और इसमें बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की होती है, जिनके कंधों पर किसी भी देश का भविष्य टिका होता है। बीते वर्षों में दुनियाभर में खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा काफी चिंताजनक है। लोगों में अवसाद निरंतर बढ़ रहा है, जिसके चलते ऐसे कुछ लोग आत्महत्या जैसा हृदयविदारक कदम उठा बैठते हैं। जीवन से निराश होकर आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर चिंता का सबब बन रही है। मनोचिकित्सकों के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति या युवा गहरे मानसिक तनाव से जूझ रहा होता है तो उसके व्यवहार में पहले की अपेक्षा कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में आसपास मौजूद लोगों और परिजनों की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे ऐसे व्यक्ति या युवा को भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक, जैसी भी जरूरत हो, सहयोग करें, उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि वह खुद को अकेला महसूस न करे। मनोचिकित्सकों के अनुसार आत्महत्या करना काफी गंभीर समस्या है और आत्महत्या करने के पीछे अधिकांशतः अवसाद को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो ऐसे करीब 90 फीसदी मामलों का प्रमुख कारण है। आत्महत्या करने का विचार किसी इंसान के अंदर तब पनपता है, जब वह किसी मुश्किल से बाहर नहीं निकल पाता।

कटते पेड़, बढ़ता प्रदूषण

काफी कम अनुपात में लगाए जा रहे पेड़

विकास की अंधी दौड़ में हर साल जिस तरह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, उससे काफी कम अनुपात में पेड़ लगाए जा रहे हैं। जो पेड़ लगाए भी जा रहे हैं, वो देखभाल के अभाव में सूख जाते हैं। मेट्रो विस्तार के लिए हजारों पेड़ काटे गए और हजारों पेड़ों को प्रत्यारोपित किया गया, लेकिन उचित देखभाल न होने की वजह से मात्र एक-तिहाई पेड़ ही बचे हैं। सरकार ने लाल किले के सामने ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए पौधे लगाए, लेकिन पानी के अभाव में पौधे सूख गए। इसके बाद दोबारा पौधे लगाए गए। ऐसे में पौधों को जमीन या गमलों में लगा देना ही काफी नहीं, बल्कि उनकी देखभाल भी बहुत जरूरी है। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, दिल्ली का वनक्षेत्र सात प्रमुख बड़े शहरों में सबसे ज्यादा 194.02 वर्ग किलोमीटर है, जबकि प्रदूषण के मामले में यह नंबर वन है। वहीं 110.77 वर्ग किलोमीटर के साथ मुंबई दूसरे स्थान पर है और 89.02 वर्ग किलोमीटर के साथ-साथ बेंगलुरु तीसरे स्थान पर है। हालांकि सन् 1997 के बाद राजधानी दिल्ली के वन क्षेत्र में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। सन् 2021 में वन क्षेत्र बढ़कर 342 वर्ग किलोमीटर हो गया। इससे कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों का हिस्सा भले ही बढ़कर 23.07 फीसदी हो गया। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण छाया रहता है, उससे तो यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या फिर मप्र की राजधानी भोपाल हर जगह प्रदूषण बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, विश्व में वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष अनुमानित 35,00,000 लोगों की मौतें हो जाती हैं, जिसमें पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 2,37,000 से अधिक मौतें शामिल हैं। भारत में वायु प्रदूषण के कारण कुल 16.7 लाख लोगों की मौत हुई, जिसमें 9.8 लाख लोगों की मौतें पीएम-2.5 प्रदूषण की वजह से हुई हैं। दुनिया भर में 15 साल से कम उम्र के 93 फीसदी बच्चे प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं घेर रही हैं। वायु प्रदूषण से हर साल करीब 3.5 लाख बच्चे अस्थमा का शिकार बन रहे हैं। जिस तरह से विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, उससे धरती पर रहने वाले जीवों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। एक तरफ अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से घटते वन क्षेत्र, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व में चल रही सत्ता की लड़ाई में इस्तेमाल किए जा रहे गोले, बारूद सहित खतरनाक हथियारों से न सिर्फ मानवीय त्रासदी, अपितु इससे पर्यावरण को भी बहुत आघात पहुंच रहा है।

दुनियाभर में किए गए मिसाइल, परमाणु परीक्षणों और सैटेलाइट अभियानों से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है और यह क्रम लगातार जारी है। जल, जंगल, जमीन पर जिस तरह से तबाही का आलम उससे आने वाले समय में विनाश तय माना जा रहा है। विकास की होड़ हो या परंपरा के नाम पर चली आ रही कुप्रवृत्तियां अगर ऐसे ही चलती रहीं, तो देश और समाज को एक-न-एक दिन नष्ट कर ही डालेंगी। भारत जैसे देश में धार्मिक कर्मकांड से अतिरिक्त कचरे से भी पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। लोग भारी मात्रा में नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्र में कूड़ा-करकट और उपयोग किया गया खराब सामान डालते हैं। केमिकल बहाते हैं, जिससे और प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली जैसे शहर में पढ़े-लिखे लोग भी सरकार की चेतावनी को दरकिनार करते हुए पूजा सामग्रियों को यमुना में फेंकते हैं। इस प्रकार देखा जाए, तो पूरे भारत में सैकड़ों टन इस्तेमाल कचरा हर रोज निकलता है, जिसे जमीन पर डाल दिया जाता है और पानी में बहा दिया जाता है।

दुनिया में, विशेषतौर पर भारत में कई त्योहार भी प्रदूषण बढ़ाने का जरिया बन रहे हैं। नया साल, क्रिसमिस-डे, दीपावली, क्रिकेट में जीत के जश्न और खुशियों के दौरान लोग अनाप-शनाप पटाखे फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं। यह सब प्रदूषणजनित इन चीजों पर रोक के बावजूद होता है। जब लोग पटाखे फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं, तब हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यानी सिर्फ वाहनों, कल-कारखानों और पराली जलाने से ही प्रदूषण नहीं बढ़ रहा, बल्कि खुशियों के अवसर भी प्रदूषण की समस्या को और भी ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। किसने सोचा था कि एक दिन धार्मिक स्थलों में ताला लगाना पड़ेगा? लेकिन हमने कोरोनाकाल में यह सब देख लिया। प्रदूषण से हो रही मौतों से पता चलता है कि यह कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे के मुताबिक, विकास कार्यों के लिए 2019, 2020 और 2021 में 77,420 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी गई। राजधानी में करीब 77,420 पेड़ काटे गए यानी तीन साल में हर घंटे तीन पेड़ काटे गए। इन पेड़ों को काटने के लिए बाकायदा वन विभाग की मंजूरी ली गई थी। चोरी-छिपे कितने पेड़ काटे गए, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है।

सेंट्रल जियोलॉजिकल अथॉरिटी (सीजेडए) के मेंबर सेक्रेटरी रहे चिड़ियाघर के पूर्व डायरेक्टर डीएन सिंह ने दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ विभाग से 18 सितंबर को शिकायत की थी और दो दर्जन काटे गए पेड़ों की तस्वीरें भी भेजी थी। डीएन सिंह के मुताबिक, किले के अंदर नहर के किनारे मथुरा रोड की तरफ काफी घना जंगल था, जो अब खाली मैदान में तब्दील हो गया है। उन्होंने सन् 2018 की एक तस्वीर भी दिखाई, जिसमें काफी बड़ी संख्या में पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह भैरो मार्ग की तरफ भी पेड़ और टहनियां काटी गई। इस तरह पुराने किले जैसे भीड़भाड़ वाली जगह से पेड़ काट दिए गए; लेकिन किसी को कोई खबर तक नहीं लगी। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं और बाकी लोग चुप्पी साधे हुए हैं। वन विभाग के अधिकारी दफ्तरों में क्या काम करते हैं? यह समझ से परे है। जबकि दिल्ली में बढ़ते गंभीर प्रदूषण के बावजूद भारी संख्या में पेड़ काटे गए। गली-मोहल्लों में लोग पेड़ों को लगाने के बजाय पेड़ों को काटने में सबसे आगे रहते हैं। लोग गाड़ियों को पार्क करने के लिए पेड़ों को ही कटवा डालते हैं। हरि नगर आश्रम में रेलवे ट्रैक के किनारे लगे कई पेड़ों को लोगों ने इसलिए कटवा दिया, जिससे आंधी में पेड़ों की डालियां उनकी गाड़ी पर न गिरें। दिल्ली में इस तरह चोरी-छिपे हर साल केयर टेकर को पैसे देकर कटाई-छटाई के नाम पर हजारों पेड़ काट दिए जाते हैं, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है।

● **अरविंद नारद**

न्याय की लड़ाई

सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई

राहुल के सामाजिक न्याय और मोदी के आर्थिक न्याय में कौन भारी होगा। यही नहीं जब से आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस यात्रा महिलाओं को मासिक भत्ता जैसी कई योजनाओं की बरसात की और दिल्ली व पंजाब में उसे जबर्दस्त राजनीतिक सफलता मिली तब से सभी राजनीतिक दलों में लोकलुभावन घोषणाओं और योजनाओं की होड़ लग गई। कांग्रेस ने इसी रणनीति के तहत हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में शानदार जीत दर्ज की। इससे उत्साहित कांग्रेस अब मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इसी राह पर चल पड़ी है। राजस्थान में तो अशोक गहलोत अपनी लोकलुभावन योजनाओं के बल पर ही भाजपा के बदलाव के नारे का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी घोषणाओं को गारंटी के रूप में पेश करती है तो इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी घोषणाओं को मोदी की गारंटी का नाम दे दिया है और गरीबों को मुफ्त राशन बांटने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को समय विस्तार देकर उन्होंने कांग्रेसी गारंटी और विपक्ष की लोकलुभावन घोषणाओं पर इस उम्मीद से एक बड़ा वार किया है कि उनकी यह घोषणा 2023 और 2024 के चुनावों में भाजपा का बेड़ा पार लगा सकती है।

भाजपा जहां ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़ रही है तो कांग्रेस इसे जांच एजेंसियों का खुला दुरुपयोग बताकर भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर रही है। सवाल है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले पांच साल तक और बढ़ाए जाने तथा विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई का चुनावों पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रतिमाह पांच किलो मुफ्त राशन की योजना अगले पांच साल तक अभी और जारी रहेगी। प्रधानमंत्री की इस घोषणा ने चुनावी माहौल में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। विपक्ष इसे मौजूदा विधानसभा और अगले साल अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए वोट बटोरने की कोशिश बता रहा है तो भाजपा इसे भूख के विरुद्ध लड़ाई की प्रधानमंत्री और भाजपा की प्रतिबद्धता बता रही है।

उधर, जैसे-जैसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव जोर पकड़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी, सीबीआई आयकर विभाग के छापे और जांच में भी अभूतपूर्व तेजी आ गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत राज्य के कुछ अन्य सत्ताधारी नेता ईडी की जांच के लपेटे में हैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी ईडी ने महादेव एप घोटाले में 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा दिया है। गहलोत और बघेल दोनों ने ही इसे चुनावों में हार के डर से भाजपा की हताशा बताते हुए चुनौती दी है कि भाजपा ईडी के सहारे चुनाव लड़ने की बजाय खुद मैदान में मुकाबला करे। भाजपा जहां ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़ रही है तो कांग्रेस इसे जांच एजेंसियों का खुला दुरुपयोग बताकर भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर रही है। सवाल है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले पांच साल तक और बढ़ाए जाने तथा विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई का चुनावों पर कोई असर पड़ेगा या नहीं।

बात पहले गरीबों को मुफ्त राशन की योजना को पांच साल बढ़ाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर, गरीबों को मुफ्त राशन देने की यह योजना एनडीए सरकार द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कोविड काल में शुरू की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक कर दिया गया था। माना गया था कि सरकार ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इसे बढ़ाया है। उप्र और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में इसका फायदा भी भाजपा को मिला जब उसे इस योजना के लाभार्थियों का वोट खासी संख्या में मिला। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाने की घोषणा छत्तीसगढ़ की एक चुनावी सभा में की। इस घोषणा के आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ हैं। दरअसल, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनावों में हुई हार से भाजपा बेहद परेशान हो गई। उसके फौरन बाद विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के गठन ने भी उसकी परेशानी बढ़ाई। इससे निपटने के लिए भाजपा ने महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट डलवाई तो दूसरी तरफ इंडिया के 28 दलों के मुकाबले एनडीए के 38 दलों का जमावड़ा भी इकट्ठा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल की एक सभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का भी मुद्दा गरम किया। लेकिन इस पर हुई प्रतिक्रिया ने उन्हें अपने कदम वापस लेने को विवश किया।

फिर तमिलनाडु के सनातन विवाद ने भाजपा को एक नया मुद्दा दिया। भाजपा ने इसे अपने हिंदुत्व की धार तेज करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और विपक्षी इंडिया गठबंधन को दबाव में ला दिया। फिर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण के जरिए भाजपा ने नई राजनीतिक माहौलबंदी करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने इसे पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षण और लागू होने में होने वाली देरी से जोड़कर कमजोर कर दिया। इसके साथ ही गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जातीय जनगणना के आंकड़ों से देश में जातीय जनगणना कराने की मांग ने जोर पकड़ लिया। कांग्रेस खासकर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को अपनी हर सभा में जोरशोर से उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने इस मांग में पिछड़े आदिवासी और दलित वर्गों की हिस्सेदारी के सवाल से जोड़कर इसे बेहद धारदार बना दिया। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े भी जारी करके राज्य में पिछड़े दलित आदिवासियों के लिए 65 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने का फैसला करके सामाजिक न्याय के अपने मुद्दे को और धारदार बना दिया है। इसमें अगड़े गरीबों का 10 फीसदी आरक्षण जोड़ देने से यह प्रतिशत 75 फीसदी हो जाता है।

● **जितेंद्र तिवारी**

जनता मौन... वादे, दावे फेल

भाजपा-कांग्रेस में कांटे की टक्कर

मप्र में इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के मौन ने भाजपा और कांग्रेस के साथ ही सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि प्रदेश में हर बार की तरह इस बार भी भाजपा और कांग्रेस में ही टक्कर है, लेकिन काटेदार। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गढ़ बचाने के लिए भाजपा ने अपना सबकुछ दांव पर लगा दिया। वहीं कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मप्र में इस बार कमल खिलेगा या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से हटाकर कमलनाथ सरकार बनाने में सफल होंगे यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा।

● राजेंद्र आगाल

2018 की तरह इस बार भी मप्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की जंग है। करीब 37 दिनों तक चले चुनाव प्रचार में जनता के मौन ने राजनीतिक पार्टियों को पसोपेश में डाल दिया है। प्रदेश में यह पहला चुनाव है, जो स्थानीय और वास्तविक मुद्दों को दरकिनार कर मिशन 2024 के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। इसलिए इस चुनाव में मप्र की जनता की रूचि कम दिख रही है। फिर भी कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस जहां सत्ता हथियाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं भाजपा दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए जोर लगा रही है। सियासी और भौगोलिक तौर पर प्रदेश छह हिस्सों में बंटा है। यहां की राजनीति भी अलग-अलग है। प्रदेश की सत्ता में इन हिस्सों का भी अहम योगदान रहता है। 17 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। वर्तमान में दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है।

मप्र विधानसभा चुनाव के लिए 15 नवंबर की शाम प्रचार थम गया। राज्य की 230 सीटों पर 2533 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 17 नवंबर को मतदाता करेंगे। मप्र में 5,60,60,925 वोटर्स कैंडिडेट की किस्मत का फैसला तय करेंगे। इसमें 2,88,25,607 पुरुष, 2,72,33,945 महिलाएं और 1,373 थर्ड जेंडर हैं। भाजपा सत्ता बचाने की जंग लड़ रही है और कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेताब है जबकि सपा-बसपा जैसे दल तीसरी ताकत बनने की जुगत में हैं। ऐसे में मप्र के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग तरह का सियासी बदलाव दिख रहा है। विधानसभा की सभी 230 सीटों पर सियासत की नब्ज टटोलने के साथ प्रत्याशियों की हार-जीत की संभावनाओं की पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटेदार टक्कर है। छह रीजन में सीटों के बंटवारे के पिछले आंकड़ों की तुलना करें तो अबकी बार महाकौशल में भाजपा के आगे बढ़ने की संभावना है, वहीं मध्यभारत में वह पुराने नतीजे यथावत रखने में सफल होती दिख रही है। ग्वालियर-चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। इन सबके बीच सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले मालवा-निमाड़ में पुरानी स्थिति बरकरार रहने की संभावना है। यहीं दोनों दलों ने बड़ा जोर लगाया है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं तो भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ खुद शिवराज सिंह चौहान का फोकस इस क्षेत्र में रहा।

गौरतलब है कि मप्र सियासी और भौगोलिक तौर पर छह अलग-अलग हिस्सों में बंटा हुआ है। जिनमें बुंदेलखंड, चंबल-ग्वालियर, विंध्य, मालवा-निमाड़, महाकौशल और मध्य क्षेत्र शामिल है। सूबे की 230 सीटें इन्हीं छह इलाकों में बंटी हुई हैं। किसी इलाके में कांग्रेस तो किसी में भाजपा का दबदबा दिख रहा है, जबकि कहीं पर कांटे की टक्कर दिख रही है। किसी इलाके में बागियों ने खेल बिगाड़ रखा है तो कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है।

महाकौशल की स्थिति

मप्र के महाकौशल इलाके में 38 विधानसभा सीटें आती है, जिस पर 402 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। इस इलाके में जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले की सीटें शामिल हैं। ये भाजपा और कांग्रेस दोनों का गढ़ रहा है। पिछली बार कांग्रेस इस क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन करके ही भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सफल रही थी। 2018 में महाकौशल की 38 सीटों में से कांग्रेस 24 तो भाजपा 13 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि 2013 में भाजपा ने 24 सीटें जीती थीं और कांग्रेस 13 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन आदिवासी बहुल इलाके के चलते बसपा और गोंडवाना पार्टी के गठबंधन ने कुछ सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। महाकौशल क्षेत्र में कमलनाथ की असली सियासी कौशल की भी परीक्षा है, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र छिदवाड़ा आता है। इस क्षेत्र में पार्टी का पूरा प्रचार उन्हीं पर केंद्रित है और वह मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी हैं। भाजपा 2018 की हार का हिसाब बराबर करने के लिए इस बार अपने दो केंद्रीय मंत्रियों सहित चार सांसदों को इसी इलाके से उतार रखा है। महाकौशल क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए यहां की 13 सीटें आरक्षित हैं। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में इनमें से 11 सीटें जीती थीं जबकि शेष दो सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। यही वजह है कि इस बार सभी दलों का फोकस आदिवासी वोटों पर है।

भ्रष्टाचार, अपराध, किसान, बेरोजगारी

मप्र में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में दस मुद्दों के प्रचार परिदृश्य पर हावी होने की संभावना है और ये मुद्दे 230 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मप्र में 2018 में आखिरी चुनावों के बाद, राज्य में मार्च 2020 में तब सत्ता परिवर्तन देखने को मिला जब अनुभवी राजनेता कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई और भाजपा सिर्फ 15 महीने तक विपक्ष में रहने के बाद सत्ता में वापस आ गई। दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक की 15 महीने की अवधि को छोड़कर (जब कांग्रेस सत्ता में थी), भाजपा को लगभग चार कार्यकालों की सत्ता-विरोधी लहर से पार पाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, कांग्रेस कई मुद्दों पर शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ लोगों के बीच नाराजगी को भुनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस मौजूदा भाजपा शासन में कथित भ्रष्टाचार को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस ने भाजपा शासन के 18 साल के दौरान 250 से ज्यादा बड़े घोटाले भी गिनाए हैं। वित्तीय घोटालों की सूची में व्यापमं भर्ती और प्रवेश घोटाला सबसे ऊपर है। बढ़ता अपराध ग्राफ, विशेषकर महिलाओं, दलितों और आदिवासियों सहित कमजोर वर्गों के सदस्यों के खिलाफ घटनाएं, मतदाताओं के बीच एक प्रमुख मुद्दा है। सीधी जिले में एक व्यक्ति द्वारा एक आदिवासी व्यक्ति से अमानवीय व्यवहार की घटना में मुख्यमंत्री ने व्यक्ति के पैर धोए और उससे माफी मांगी। राज्य में कृषि संबंधी मुद्दे हमेशा राजनीतिक चर्चा में हावी रहे हैं और सभी दलों ने किसानों को लुभाने की कोशिश की है।

ग्वालियर-चंबल की स्थिति

मप्र के उत्तरी इलाके और उप्र से सटे हुए ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में 34 विधानसभा सीटें आती है, जहां करीब 350 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की साख दांव पर लगी है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह जैसे नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। 2018 में कांग्रेस ने भाजपा को इस क्षेत्र में करारी मात दी थी। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की 34 सीटों में से कांग्रेस 27, भाजपा 5 और अन्य को 2 सीटें मिली थीं। कमलनाथ के 15 महीने में सत्ता से बाहर होने का कारण भी यही इलाका बना था। 2020 में कांग्रेस के जिन दो दर्जन विधायकों ने पाला बदला था, उनमें 16 विधायक इसी इलाके से थे। ग्वालियर-चंबल का इलाका 2018 से पहले तक भाजपा का हुआ करता था, 2013 में इस इलाके की 34 में से 20 सीटें

भाजपा ने तय कर लिया 2024 का एजेंडा

मप्र विधानसभा चुनाव इस बार भाजपा की प्रयोगशाला के रूप में नजर आया है। ये प्रयोगशाला 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तभी तो मंत्रियों, सांसदों और बड़े नेताओं को टिकट देकर भाजपा ने चुनाव मैदान में उतार दिया। 3 दिसंबर तक सबको मालूम हो जाएगा कि भाजपा के कद्दावर नेता माने जाने वाले अभी कितने पानी में हैं? मप्र से पहले भाजपा ने ऐसे प्रयोग पश्चिम बंगाल और उप्र जैसे राज्यों में भी किए थे, और राजस्थान में भी करीब-करीब वैसा ही नजारा दिखा है, लेकिन ये सब यूं ही नहीं है। सुनने में आ रहा है कि ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो चुके और हो रहे हैं, जिनकी योजना अगले आम चुनाव के हिसाब से तैयार की गई है। चुनाव प्रचार के दौरान उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के भाषणों पर ध्यान दें, तो ये पक्का लगता है कि अगले आम चुनाव में भाजपा का मुख्य एजेंडा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ही होने जा रहा है। और जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तन्मयता से अयोध्या के राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी कर रहा है, उसके राजनीतिक निहितार्थ साफ-साफ देखे और समझे जा सकते हैं। जिस तरीके से संघ की तरफ से पूरे देश को अयोध्या में तब्दील करने की तैयारी चल रही है, सारी चीजें आसानी से समझी जा सकती हैं। 2019 के आम चुनाव से पहले वीएचपी और संघ की पहल पर भाजपा ने मंदिर का मुद्दा होल्ड कर लिया था, लेकिन इस बार सारी कसर पूरी करने की तैयारी लगती है। मतलब, ऐसा सोच समझकर 2024 को ध्यान में रखते हुए किया गया था। अभी पिछले ही महीने गुजरात के भुज में संघ की बैठक में तीन दिन तक व्यापक विचार विमर्श हुआ। बैठक में सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर बात हुई, वो अयोध्या के राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार रहा। बैठक के बाद आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर का कहना था, यह त्योहार का अवसर होगा। हर कोई अयोध्या नहीं जाएगा। लोग अपने नजदीकी मंदिरों में जाकर इस त्योहार को मनाएंगे। रात के समय सभी को अपने घरों पर दीए जलाना चाहिए। ऐसी अपील संघ की ओर से की गई है। बताते हैं कि 1 जनवरी से 15 जनवरी, 2023 तक घर-घर अक्षत वितरण कार्यक्रम चलेगा।

भाजपा, 12 सीटें कांगेस और 2 सीटें बसपा को मिली थीं। इसी तरह से 2008 में भी नतीजे रहे थे। इस बार सिंधिया की साख दांव पर लगी है, लेकिन दिग्विजय ने भाजपा की चुनौती बढ़ा रखी है। 34 सीटों में से 25 सीटों पर कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधी फाइट दिख रही है तो 9 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। ऐसे में देखना है कि ग्वालियर-चंबल बेल्ट में किसका दबदबा रहता है।

बुंदेलखंड-विंध्य की स्थिति

उप्र की सीमा से जुड़े हुए बुंदेलखंड में 30 सीटें तो विंध्य क्षेत्र में 26 सीटें आती हैं। इस तरह दोनों ही क्षेत्रों में कुल 56 सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें इसी दोनों इलाके से आईं थीं। विंध्य से कांग्रेस का सफाया हो गया था। भाजपा ने 38 और कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। विंध्य क्षेत्र ब्राह्मण प्रभाव वाला माना जाता है, तो बुंदेलखंड में दलित और ओबीसी जातियां खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। उप्र की सीमा लगने के वजह से सपा और बसपा भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं, जिसके चलते कांग्रेस और भाजपा की धड़कने बढ़ी हुई हैं। इन दोनों इलाों की 56 सीटों में से करीब एक दर्जन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है।

कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला

मप्र में भाजपा-कांग्रेस के बीच ही चुनावी मुकाबला होता रहा है। वर्ष 2018 के चुनाव में भाजपा सत्ता जरूर कायम नहीं रख पाई, लेकिन कांग्रेस भी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त नहीं कर सकी थी। अब 2023 के लिए चुनावी तस्वीर साफ हो रही है। हर दूसरे दिन एक सर्वे रिपोर्ट आ रही है, जिसमें कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस की सरकार बनाती दिख रही है। सट्टा बाजार में भी दोनों पार्टियों के भाव शेयर मार्केट की तरह उतार-चढ़ाव पर हैं। ऐसे में सभी की नजर मतदाताओं की ओर है। त्रिकोणीय संघर्ष वाली सीटों ने इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। कम से कम 24 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बागियों ने ही चुनौती पेश की है। इन सीटों पर चुनावी संघर्ष ऐसे संकेत दे रहा है कि बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी जैसे दलों के प्रत्याशी भी प्रमुख दलों को नुकसान पहुंचाएंगे। ये सभी सीटें बहुमत का आंकड़ा जुटाने में भी निर्णायक साबित होंगी। नर्मदापुरम जिले के होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने डॉ. सीतासरन शर्मा, तो कांग्रेस ने उनके बड़े भाई गिरिजाशंकर शर्मा को मैदान में उतारा है। भाजपा के असंतुष्टों ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भगवती चौरे को खड़ा किया है। एक ओर त्रिकोणीय मुकाबला गुना जिले की चाचौड़ा सीट पर है। यहां भाजपा से प्रियंका मीना को टिकट देने के बाद ममता मीना नाराज हो गईं। वह आप की टिकट पर मैदान में उतर गई हैं। वहीं, कांग्रेस से विधायक लक्ष्मण सिंह फिर मैदान में हैं। इंदौर जिले के डॉ. आंबेडकर नगर महू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की ओर से मंत्री ऊषा ठाकुर उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस से रामकिशोर शुक्ला। कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार निर्दलीय लड़ रहे हैं। बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को टिकट देने के विरोध में पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष स्व. नंदकमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान निर्दलीय चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को प्रत्याशी बनाया है। धार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों के बागी मैदान में हैं। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने विधायक नीना वर्मा पर ही भरोसा जताया है। कांग्रेस ने प्रभा गौतम को उम्मीदवार बनाया है, जिससे नाराज होकर प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह बुंदेला निर्दलीय खड़े हैं। उज्जैन जिले के बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह सोलंकी का टिकट बदलकर विधायक मुरली मोरवाल को प्रत्याशी बनाया तो नाराज सोलंकी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। विंध्य अंचल की सीधी सीट से विधायक केदारनाथ शुक्ला का भाजपा से टिकट कट जाने के कारण वह निर्दलीय मैदान में हैं। वह भाजपा की प्रत्याशी रीति पाठक और कांग्रेस के ज्ञान सिंह को चुनौती दे रहे हैं। इसी प्रकार कई सीटों पर बागी मैदान में हैं, जिससे त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन गई है।

मध्य क्षेत्र की स्थिति

प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसपास के जिलों वाले इलाके को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यहां 36 विधानसभा सीटें आती हैं। यह इलाका हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है। भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिले आते हैं। 2018 में मध्य क्षेत्र की 36 सीटों में से 23 सीटें भाजपा और 13 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इलाका माना जाता है और यहीं उनकी बुधनी सीट भी आती है। कांग्रेस और भाजपा के बीच इस बार सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की गारंटी ने भाजपा की चिंता बढ़ा रखी है।

मालवा-निमाड़ की स्थिति

मप्र की सत्ता की चाबी मालवा-निमाड़ इलाके के पास रही है। सूबे में जो भी पार्टी इस इलाके को जीतने में कामयाब रहती है, उसे ही सत्ता पर काबिज होने का मौका मिलता रहा है। इस इलाके में सबसे ज्यादा 66 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 में इन 66 सीटों में से कांग्रेस 35 और भाजपा 28 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार आदिवासी और ओबीसी बहुल इस इलाके में भाजपा को कई सीटों पर कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो कई सीटों पर सीटों पर बागियों ने टेंशन बढ़ा रखी है। कांग्रेस को सियासी तौर पर इस क्षेत्र में लाभ मिलने की उम्मीद दिख रही है, लेकिन जातीय समीकरण को साधना मुश्किल हो रहा है।

पिछली बार आदिवासी वोटर भाजपा से नाराज थे और जयस ने भी भाजपा को नुकसान पहुंचाकर कांग्रेस की बढ़त बनाई, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे वाला है। भाजपा और कांग्रेस को कुछ सीटों पर बसपा और सपा से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसकी वजह यह है कि भाजपा और कांग्रेस ने जिन नेताओं को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने इन पार्टियों का हाथ थामा है। इस कारण कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। ऐसे में देखना है कि मप्र की सत्ता का द्वार खोलने वाले मालवा-निमाड़ क्षेत्र में किसका दबदबा रहता है?

मप्र की राजधानी पहुंचते ही जो पहली बात सुनाई पड़ती है वह है इलेक्शन टाईट है। उस नाते मप्र में भी चुनावी माहौल छत्तीसगढ़ जैसा ही है। दोनों ही राज्यों में कुछ महीने पहले तक कांग्रेस की आसान जीत होती दिख रही थी, जो पिछले कुछ हफ्तों में कड़ी टक्कर में बदल गई है। क्या इसे भाजपा के लिए उपलब्धि मानें? पर वह भाजपा, जिसका भोपाल गढ़ माना जाता रहा है! कांग्रेस अति-आत्मविश्वास में डूबी हुई है जबकि लोगों की बातों में कांग्रेस टाईट इलेक्शन में फंसी हुई है।

पानी की तरह बहाया पैसा

विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी तन-मन के साथ धन भी खूब खर्च करते हैं। इस बार भी चुनाव में रैली-सभा, इंटरनेट, सोशल और प्रिंट मीडिया के अलावा स्टार प्रचारकों पर पैसे खर्च कर मतदाताओं को वोट के लिए रिझाया गया। आलम यह था कि कई प्रत्याशियों ने तो एक दिन में 10-10 लाख रुपए खर्च कर डाले। ऐसे में यह सहज ही अनुमान लगाया जा रहा है कि मप्र का विधानसभा चुनाव खर्च में अब तक के सबसे महंगे चुनाव में शामिल हो गया है। चुनाव आयोग से खर्च की सीमा तय की थी। विधानसभा चुनाव में 40 लाख तक खर्च किया जा सकता है। ज्यादा पर कार्रवाई हो सकती। 40 लाख में से नकद सिर्फ 10 हजार ही खर्च किए जा सकते हैं। बाकी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होगा। आयोग ने खर्च के लिए बैंक खाता खोलने का निर्देश दिया था। इसी खाते से चुनाव संबंधी खर्च हुए। आयोग से दिए रजिस्टर में खर्च से जुड़ी जानकारी व सभी रसीदें भी होनी जरूरी हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इस बार विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी की खर्च की सीमा 40 लाख रुपए तय कर रखी है। लेकिन प्रत्याशियों ने एक दिन में 10-10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर डाले। यानी, चुनाव आयोग से तय 40 लाख रुपए की सीमा तो चार दिन में ही पार कर ली। इस हिसाब से प्रदेश की 230 सीटों में हर सीट पर तीन गंभीर प्रत्याशी हैं, जिन्होंने मोटी रकम खर्च की है। इन प्रत्याशियों का एक दिन का ही खर्च 70 करोड़ से ज्यादा है, जबकि सप्ताहिक चुनाव खर्च के हिसाब में प्रत्याशी 15-20 हजार रुपए ही बता रहे हैं। आयोग के अनुसार एक दिन का इनका खर्च 11.50 करोड़ बैठता है। सबसे ज्यादा खर्च वाहन व ईंधन पर है।

सनातन से राम मंदिर तक का मुद्दा

मप्र में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब मतदान की घड़ी आ गई है। मप्र की 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता 17 नवंबर को अपना फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में कैद करेंगे। मतदान से पहले प्रचार का शोर थमने के बाद बात भाजपा से लेकर कांग्रेस और दूसरे दलों के बड़े नेताओं की रैलियों को लेकर भी हो रही है। दोनों ही राज्यों में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे नेता प्रचार के मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति में नजर आए। वहीं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को हटा दें तो कांग्रेस का जोर लोकल लीडरशिप पर रहा। मप्र में कमलनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां कीं तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार की कमान संभाले नजर आए।

मप्र के चुनाव में भाजपा का जोर जहां बार-बार दिग्विजय सिंह की 10 साल वाली सरकार पर रहा तो वहीं लाड़ली बहना योजना को भी पार्टी ने बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के लगभग हर बड़े नेता ने सनातन और राम मंदिर से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर रखा। भाजपा ने अपनी 18 साल की सरकार की उपलब्धियां गिनाईं ही, 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर मप्र को गांधी परिवार के लिए एटीएम बना देने का भी आरोप लगाया। वहीं, कांग्रेस का फोकस जातिगत जनगणना के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी नजर आया। प्रचार के शुरुआती चरण में पार्टी के बड़े नेताओं ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। हालांकि, प्रचार जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया,

कांग्रेस का फोकस स्थानीय समस्याओं, शिवराज सरकार की विफलताओं, पर्चा लीक-पटवारी भर्ती में कथित घोटाले के साथ ही 15 महीने की सरकार गिरने के घटनाक्रम की ओर शिफ्ट होता चला गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रियंका गांधी ने ग्वालियर-चंबल रीजन के दतिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी निशाने पर रखा। मप्र में कांग्रेस के प्रचार का आगाज करते हुए प्रियंका ने कहा था कि सिंधिया पर कई घंटे बोल सकती हूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी। शुरुआत में जिस मुद्दे पर बोलने से प्रियंका ने हंसकर इनकार कर दिया था, अंतिम दिन उसे लेकर ही बोलना चरण-दर-चरण बदलती रणनीति का अच्छा उदाहरण है।

मप्र में भ्रष्टाचार और कुशासन के मुद्दों को भाजपा ने जमकर उछाला लेकिन दोनों ही राज्यों की प्रचार रणनीति में कुछ कॉमन भी रहा। कॉमन ये कि पार्टी के प्रचार अभियान का शुरुआती चरण सनातन के मुद्दे पर केंद्रित नजर आया तो वहीं अंतिम चरण में राम मंदिर का मुद्दा भी खूब उछला। अब दोनों राज्यों में मतदान की घड़ी करीब है। दोनों ही प्रदेशों की जनता विधानसभा में अपना प्रतिनिधि, अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनने को 17 नवंबर के दिन मतदान करेगी। ऐसे में देखना होगा कि जनता किसके प्रचार पर भरोसा करती है।

दिग्गजों की साख दांव पर

इस बार के चुनाव में भाजपा ने दो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ ही 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। जिनमें तीन केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, लेकिन इन दिग्गजों की भी जान अपनी सीट की ओर अटकी नजर आ रही है। मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भाजपा ने चुनाव में उतारा है, उम्मीद थी कि वे आसानी से चुनाव जीत लेंगे क्योंकि वे इस क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं, उनके सामने कांग्रेस ने विधायक रवींद्र सिंह भिड़ोसा को टिकट दिया है। दोनों ही प्रत्याशियों के लिए यह चुनाव जीतना कांटे की टक्कर है। जहां केंद्रीय मंत्री के आगे कांग्रेस प्रत्याशी काफी कमजोर हैं, लेकिन दिमनी क्षेत्र में जनता नरेंद्र सिंह तोमर से नाराज दिखाई दे रही है। भाजपा की ओर से प्रत्याशी घोषित होने के काफी समय

तक तोमर जानता के बीच तक नहीं पहुंचे थे। उन्होंने नामांकन से पहले हुई मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पहली सभा की थी। यहां जनता इस बात से नाराज है कि सांसद होने के बावजूद उन्होंने इस क्षेत्र में विकास पर ध्यान नहीं दिया। उनके पैतृक गांव उरेठी में भी जनता में नाराजगी है। वहीं हाल ही में उनके बेटे रामू तोमर के करोड़ों के लेनदेन को लेकर बातचीत के एक के बाद एक तीन वीडियो वायरल हुए। जिन्होंने राजनीतिक छवि पर असर डाला है। इसका असर भी चुनाव के नतीजों पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में इस सीट पर अब केंद्रीय मंत्री की सांसे अटकी हुई है। वहीं हर हाल में जीत की उम्मीद के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भाजपा ने नरसिंहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाया है। यहां से कांग्रेस ने लाखन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। नरसिंहपुर विधानसभा सीट के वर्तमान समीकरण भाजपा के पक्ष में 70 प्रतिशत और कांग्रेस के लिए 30 प्रतिशत माने जा रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में भाजपा समर्थित जनसमुदाय अधिक है। लेकिन इस क्षेत्र में भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं में अंदरूनी विरोध देखा जा रहा है।

उधर, मंडला जिले की निवास सीट पर इस बार चुनाव कांटे की टक्कर का है। कांग्रेस के प्रभाव वाली इस सीट पर जहां कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ आदिवासी नेता चैन सिंह वरकड़े को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा इस सीट पर हर हाल में कब्जा करने की उम्मीद में केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में हैं। वैसे 2018 के पहले तीन बार से भाजपा का कब्जा था, लेकिन पीछे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट को हथिया लिया। फग्गन सिंह के छोटे भाई, जो इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी थे, कांग्रेस ने उन्हें 30 हजार वोटों से शिकस्त दी थी। हालांकि केंद्रीय मंत्री कुलस्ते इस सीट पर मजबूत हैं, क्योंकि अपने केंद्रीय मंत्री रहते उन्होंने उस क्षेत्र के उद्योगिक विकास पर काफी ध्यान दिया। जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलने की पूरी उम्मीद है।

वहीं गाडरवाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा ने भले ही सांसद उदय प्रताप सिंह को मैदान में उतार दिया हो, लेकिन इस विधानसभा सीट पर चुनाव में कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहां कांग्रेस ने सुनीता पटेल को टिकट दिया है। वहीं पूर्व विधायक गोविंद पटेल के बेटे गौतम सिंह पटेल भाजपा छोड़ कांग्रेस में गए थे, लेकिन टिकट नहीं मिला था। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन कर दिया। जिसकी वजह से कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। वहीं मप्र की सीधी विधानसभा में चुनाव इस बार सीधा नहीं है। विधानसभा चुनाव में इस बार सिटिंग विधायक की बजाय भाजपा ने सांसद रीति पाठक को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने ज्ञान सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन भाजपा का मुकाबला अपने ही निष्कासित विधायक केदारनाथ शुक्ला से है। जो निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं और भाजपा के लिए मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। हालांकि अब यह चुनाव विकास नहीं बल्कि जनता के बीच वर्चस्व का है।

उधर, जबलपुर पश्चिम सीट पर कांग्रेस के तरुण भनौट दो बार लगातार चुनाव जीतने के बाद खुद को मजबूत उम्मीदवार के रूप में स्थापित कर चुके हैं। ऐसे में भाजपा के पास इस सीट पर कोई बेहतर विकल्प नहीं होने से सांसद राकेश सिंह को मैदान में प्रत्याशी बनाकर उतारा गया है। 2004 में पहली बार राकेश सिंह जबलपुर लोकसभा से जीतकर सांसद बने। इसके बाद 2009, 2014 और 2018 में भी सांसद चुने गए, लेकिन विधानसभा का चुनाव वे पहली बार लड़ रहे हैं। हालांकि यह चुनाव जीतना उनके लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि 2018 के चुनाव के दौरान वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और पार्टी को उस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। शिवराज सिंह चौहान के हाथ से सत्ता फिसल गई थी। ये फैक्टर अब भी उन पर दाग लगाए हुए है ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के बीच यहां भी कांटे की टक्कर है। जीत-हार मतदाता ही तय करेगा।

तेल बढ़ाएगा महंगाई?

इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध का असर अब दुनिया भर में दिखने लगा है। इस जंग से भारत की भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं क्योंकि इजराइल-हमास युद्ध के कारण कच्चे तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल उत्पादन में कटौती के चलते तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर की ओर जा रही हैं, वहीं वैश्विक खाद्यान्न संकट के मद्देनजर खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका भी गहरा रही है। हालांकि केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक देश में थोक एवं खुदरा महंगाई के सूचकांक, महंगाई में कमी का संकेत दे रहे हैं लेकिन चुनौती पूर्ण वैश्विक भू-राजनीतिक एवं आर्थिक कठिनाइयों के दौर में महंगाई के बढ़ने की आशंका अधिक है।

मालूम हो कि युद्ध के चलते तेल उत्पादक देशों द्वारा की जा रही कटौती के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति घटने और उसकी कीमतों के ऊपर जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। कच्चे तेल की कीमतें इस साल लगभग 28 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड वायदा 94 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है, जिसके युद्ध न रुकने की स्थिति में जल्द ही 100 डॉलर प्रति बैरल होने की बात कही जा रही है। तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत की मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं।

सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022-23 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 10.02 प्रतिशत बढ़ी जिसके कारण पेट्रोल में 13.4 प्रतिशत, डीजल में 12 प्रतिशत और एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 में घरेलू उत्पादन में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आने से आयातित कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता बढ़कर 87.8 प्रतिशत हो गई है। रियायती रूसी आपूर्ति के बावजूद हमारा वार्षिक कच्चे तेल का आयात 158 बिलियन डॉलर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत ज्यादा है। मात्रा के लिहाज से कच्चे तेल का आयात 9.4 प्रतिशत बढ़कर 232.4 मिलियन मिट्रिक टन हो गया। पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उनके आयात में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन निर्यात में 4.1 प्रतिशत की गिरावट आई। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है क्योंकि युद्ध के चलते महंगाई बढ़ सकती है। भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। अगर युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में फैल गया तो कच्चे तेल की आपूर्ति अवश्य बाधित होगी, जिसके कारण तेल की कीमतों में और अधिक तेजी आएगी। भारत में पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने का सीधा मतलब है रोजमर्रा की चीजों में महंगाई का बढ़ना।

चूंकि महंगाई मध्यम वर्ग को अधिक प्रभावित करती है, इसलिए अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए महंगाई को बांधे रखना सरकार के लिए एक कठिन चुनौती की तरह है। पिछले दिनों विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी दुनिया के साथ-साथ भारत में भी महंगाई के बढ़ने की चुनौती प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में वर्ष 2023-24 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है। पूर्व में प्रस्तुत महंगाई के अनुमान से नया अनुमान अधिक बताया गया है। सितंबर महीने में रासायनिक उत्पादों, खनिज, तेल, कपड़ा, बुनियादी धातुओं और खाद्य उत्पादों की कीमतों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई थी।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जुलाई 2023 में जो खुदरा महंगाई दर 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, वह अगस्त 2023 में घटकर 6.8 प्रतिशत और सितंबर में 5.02 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह कमी अनाज, सब्जी, परिधान, फुटवियर, आवास एवं सेवाओं की कीमतों में आई गिरावट की वजह से हुई है। बीते 6 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार चौथी बार नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का निर्णय लिया है।

महंगाई को लेकर चुनौतियां लगातार बड़ी हो रही हैं। पिछले माह ज्यादातर समय कच्चे तेल का दाम 90 डॉलर प्रति बैरल से थोड़ा ऊपर रहा, अब यह और बढ़कर 94 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। दुनियाभर के बाजारों में गेहूं, दाल और चावल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। चीनी की कीमतें 12 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। अक्टूबर महीने में त्यौहारी मांग बढ़ने से दालों के दाम भी ऊंचे हुए हैं। 18 अक्टूबर 2023 को सरकार के द्वारा प्रकाशित खाद्यान्न उत्पादन आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022-23 में गेहूं का उत्पादन अनुमानित लक्ष्य से 20 लाख टन घटकर 11.5 करोड़ टन, दालों का उत्पादन 2.7 करोड़ टन घटकर 2.6 करोड़ टन और चावल का उत्पादन पिछले वर्ष के 13.94 करोड़ टन से घटकर 12.98 करोड़ टन होने का अनुमान है।

● राजेश बोरकर

शुल्क मुक्त आयात की अनुमति की जरूरत

केंद्र की सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सार्थक प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। खास तौर से गेहूं के दाम नियंत्रण के लिए खुले बाजार में मांग की पूर्ति के अनुरूप इसकी अधिक बिक्री जरूरी है। आटा मिलों को अधिक मात्रा में गेहूं दिया जाना चाहिए। साथ ही गेहूं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दिए जाने की भी जरूरत है। देश में जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में सरकार को और तेजी लानी होगी। अतिरिक्त नगदी की निकासी पर रिजर्व बैंक को खासा ध्यान देना होगा। सरकार द्वारा खुदरा महंगाई के नियंत्रण के लिए रणनीतिक रूप से एक ऐसी मूल्य नियंत्रण समिति का गठन करने पर विचार करना होगा जो बाजार में आने वाले उतार-चढ़ाव को देखते हुए कीमतों के अनियंत्रित होने से पहले ही मूल्य नियंत्रण के कारगर कदम उठाने के लिए सदैव तत्पर दिखे। रूस-यूक्रेन के बीच पिछले दो सालों से चल रहे युद्ध के दौरान ही इजराइल-हमास के बीच युद्ध के गहराने की आशंका के बीच महंगाई नियंत्रण के लिए कारगर रणनीतिक प्रयास बहुत जरूरी है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार देश के मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग को महंगाई की मार से बचाने के लिए ठोस कार्य नीति के साथ आगे आएगी।

इंडिया गठबंधन की चुनौतियां

केंद्र की एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन गठबंधन में कई तरह की दरारें नजर आ रही हैं।

सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के खिलाफ बने विपक्षी महागठबंधन इंडिया में दरार की चर्चा के बाद अखिलेश यादव ने खुलकर साफ कर दिया है कि कांग्रेस की विधानसभा में सीटों को न बांटने की स्थितियां लोकसभा में भी बनी रहेंगी। अखिलेश ने कहा है कि अगर अभी विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होगा, तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर का गठबंधन नहीं होगा। इंडिया से पहले पीडीए बन गया था। पीडीए ही एनडीए को हराएगा।

ऐसा लगता है कि यह अपने-अपने वर्चस्व को बचाए रखने की लड़ाई है; जो हर राज्य में सामने आनी ही है। और यह लड़ाई यूपीए से लेकर इंडिया गठबंधन तक ही नहीं, बल्कि एनडीए में भी शुरू से ही रही है। इसलिए मप्र में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनना कोई नई बात नहीं है और न ही इस पर भाजपा के नेताओं को बहुत खुश होने की जरूरत है। हालांकि जिस प्रकार से मप्र में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर नोकझोंक हुई, दोनों तरफ से बयानबाजी सामने आई और जिस प्रकार से दोनों पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवारों को अपनी मर्जी से मैदान में उतारते हुए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, उससे आगामी चुनावों में इंडिया गठबंधन की फूट के संकेत मिलते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि मप्र के अंदर कांग्रेस और सपा में पड़ी दरार यह साबित करती है कि गठबंधन में शामिल सभी 26 पार्टियों के बीच इस तरह की चुनौतियां आगे भी आड़े आएंगी-ही-आएंगी। इसकी वजह यह है कि जहां जिस पार्टी का वर्चस्व होगा, वो वहां की सीटों पर समझौता करने को राजी नहीं होगी और जहां जिस पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं होगा, वो वहां पर सीटों की मांग करेगी।

इस प्रकार से सभी पार्टियों की हर चुनाव में अपनी अलग राह होगी और इससे नुकसान भी इंडिया गठबंधन को ही होगा, जो कि भाजपा के नेता भी चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस को अभी से यह मान लेने की बजाय कि उसकी जीत के रास्ते खुल चुके हैं और उसे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, यह समझना चाहिए कि उसे अपने साथ इंडिया गठबंधन में आई सभी पार्टियों को एकजुटता के धागे में बांधे रखना है और किसी भी तरह से केंद्र की सत्ता में वापसी करना है। दरअसल कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में उसे लगता है कि उसके पीछे कोई भी पार्टी मजबूरन लगी रहेगी, चाहे वो जिस प्रकार भी सीटों का बंटवारा करे।

मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कहीं-न-कहीं मिजोरम में भी सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस में इस प्रकार का विश्वास, जिसे खुशफहमी कहना ज्यादा बेहतर होगा, बढ़ा है। लेकिन उसे समझना होगा कि क्षेत्रीय पार्टियां, जहां उनका वर्चस्व होगा, वो भी फिर कांग्रेस के साथ अपने-अपने राज्यों में यही बर्ताव करेंगी। और अगर इसी प्रकार से मप्र की तरह सब कुछ चलता रहा, तो हर राज्य के चुनावों में तो यह दिक्कत आने ही वाली है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सीटों के बंटवारे को लेकर यह दिक्कत इंडिया गठबंधन के सामने आएगी। क्योंकि जिस राज्य में कोई राज्य स्तरीय पार्टी मजबूत होगी, वो वहां विधानसभा सीटों को लेकर तो कांग्रेस पर अपनी मर्जी थोपेगी ही, साथ ही लोकसभा की सीटें भी अपनी मर्जी से ही देने पर राजी होगी। अखिलेश इसका इशारा कर चुके हैं। जाहिर है कि कांग्रेस को इससे अपना कद घटने का एहसास होगा और वो फिर वहां अपनी मर्जी चलाने के लिए मैदान में अपनी मनचाही सीटों पर अलग से टिकट देने की कोशिश करेगी। क्योंकि उसे हर जगह अपने बड़े होने का रुतबा भी कायम रखना है।

कांग्रेस की दावेदारी मप्र से भी ज्यादा राजस्थान में है। राजस्थान में कांग्रेस को वापसी की पूरी उम्मीद है, क्योंकि वहां मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मजबूती और वसुंधरा राजे की भाजपा शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी, पार्टी में स्थानीय उम्मीदवारों के टिकट काटकर नए चेहरों और सांसदों को मैदान में उतारना भाजपा को भारी पड़ सकता है। मप्र में भी भाजपा की यही स्थिति बनी हुई है। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो वहां भी कांग्रेस को जीत का पक्का भरोसा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक मजबूत नेता हैं और सरकार को वहां भी वापसी का विश्वास है, जिसकी पुष्टि सर्वे ने भी कर दी है। जाहिर है कि कांग्रेस वहां भी अपने किसी सहयोगी दल को ज्यादा सीटें देने से

विपक्ष के पास मुद्दे अनेक

चाहे बढ़ती हुई महंगाई हो या भयंकर बेरोजगारी या फिर खेती किसानी का संकट हो या देश में फैलाई जा रही नफरत की आग, इन सब मुद्दों पर देश को खुलकर अपनी राय रखने का मौका मिलेगा। गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक जैसे देश के तमाम हाशिया ग्रस्त समूह को उम्मीद बनी है कि इस चुनाव के बहाने उनकी सुध ली जाएगी। इतनी संभावना तो बनी है कि सत्ता के अहंकार और उसके फलस्वरूप बढ़ती हुई निरंकुश प्रवृत्तियों पर रोक लगेगी। लेकिन यह तभी हो पाएगा जब विपक्षी दल रोजमर्रा की चिंताओं से ऊपर उठकर बड़ी चुनौती को स्वीकार करेंगे। यह जरूर मानना पड़ेगा कि एक साल पहले की तुलना में विपक्षी महागठबंधन काफी बेहतर स्थिति में दिखाई देता है लेकिन अब भी इंडिया गठबंधन की मुख्य ऊर्जा छोटे सवालों पर लग रही है।

हिंदी भाषी राज्यों में अब भी भाजपा का एकछत्र दबदबा

उत्तर-पश्चिम के हिंदी भाषी राज्यों में अब भी भाजपा का लगभग एकछत्र दबदबा कायम है। राजस्थान, मप्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप्र, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में 2019 के चुनाव में भाजपा ने लगभग झाड़ू फेरी थी। इन दोनों सर्वे के मुताबिक फिलहाल इन इलाकों में भाजपा की भारी बढ़त बरकरार दिखाई देती है। इस इलाके में भाजपा के वर्चस्व को चुनौती देना इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है। यहां विपक्षी दलों के गठजोड़ भर से कोई जादू होने वाला नहीं है। उप्र को छोड़कर इन राज्यों में सीधा भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला है और गठबंधन करने लायक कोई तीसरी बड़ी ताकत नहीं है। उप्र में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस सभी का प्रभावी और ईमानदार गठबंधन फिलहाल तो असंभव प्रायः दिखता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की असली चुनौती केवल वोट बांधने और सीटें जोड़ने की नहीं, बल्कि जनता के दुख दर्द से जुड़ने और उन मुद्दों को सड़क पर उठाकर एक भरोसेमंद विकल्प पेश करने की है।

बचेगी। इसी प्रकार से मिजोरम में भी कांग्रेस को जीत का भरोसा है। क्योंकि उसके पड़ोसी राज्य मणिपुर में जिस प्रकार से हिंसा का माहौल है, उससे पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी हुई है और लोगों में उसके प्रति जिस प्रकार से गुस्सा देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि मिजोरम में कांग्रेस मजबूत हो सकती है। सर्वे के आंकड़े भी कुछ इसी प्रकार का इशारा कर रहे हैं। रही तेलंगाना की बात, तो वहां की सबसे मजबूत पार्टी भारत राष्ट्र समिति है, जिसके मुखिया के चंद्रशेखर राव वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हैं। के चंद्रशेखर राव की ग्रामीण क्षेत्रों में तो इतनी पकड़ है कि उन्हें कोई भी पार्टी वहां आसानी से मात नहीं दे सकती। क्योंकि तेलंगाना को बनाने में के चंद्रशेखर राव का जो योगदान है, वो किसी का नहीं है। शहरों में कांग्रेस को थोड़ा समर्थन मिल सकता है, जिसके बूते वो कुछ सीटें वहां जीत सकती है; लेकिन अगली सरकार भी के चंद्रशेखर राव की ही बनने की उम्मीद ज्यादा है। हालांकि के चंद्रशेखर राव की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है; लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस पहले से मजबूत बताई जा रही है, जिससे उसे लगता है कि वो वहां भी बहुमत से अगर नहीं भी जीती, तो भी मजबूत विपक्ष के रूप में उभरेगी। लेकिन वहां दिक्कत यह हो सकती है कि अगर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, जिसकी संभावनाएं काफी हैं, तो उसके विधायक टूटकर के चंद्रशेखर की पार्टी में जाने का डर रहेगा, जैसा कि पहले भी हो चुका है। ऐसे में वहां इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर शायद ही किसी दूसरी सहयोगी पार्टी को वह सीटें दे।

बहरहाल ये तो रही उन राज्यों की बात, जिनके चुनाव इसी नवंबर के महीने में ही होने हैं। इसके अलावा अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों की बात करें, तो देखेंगे कि कई राज्य ऐसे हैं, जहां क्षेत्रीय पार्टियां बहुत मजबूत हैं। मसलन उप्र में सपा, बसपा और पश्चिमी उप्र में रालोद है। ऐसे में अगर गठबंधन की बात करें, तो वहां कांग्रेस को सीटें देने में अखिलेश और जयंत मुसीबत खड़ी करेंगे, क्योंकि वे फिर उसी राह पर चलेंगे, जिस राह पर मप्र और राजस्थान में कांग्रेस चल रही है। इसी प्रकार से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी किसी भी हाल में किसी भी पार्टी को सीटें देने से बचना चाहेगी। पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी है। जाहिर है कि वहां तृणमूल की मुखिया और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो एक राष्ट्रीय छवि की मजबूत नेता हैं; अपनी वर्चस्व वाली सीटें छोड़ने पर शायद ही राजी हों। इसी प्रकार से बिहार में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सबसे मजबूत पार्टी है और उसके बाद नीतीश की जनता दल (यूनाइटेड) यानी जद(यू) बिहार की दूसरी सबसे मजबूत पार्टी है। इसके अलावा वहां क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी संख्या में हैं, जिनका अपने-अपने क्षेत्रों में भरपूर वर्चस्व है। कांग्रेस को वहां भी थोड़े में सब्र करना पड़ेगा। झारखंड में भी शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आगे कांग्रेस वहां उतनी मजबूत नहीं है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में शिवसेना और नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत हैं, और वो वहां कांग्रेस को अपनी मर्जी से ही सीटें देंगी। लेकिन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अगर तीन से चार राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो कांग्रेस का हौसला बढ़ेगा और कांग्रेस इन प्रदेशों में बहुत ज्यादा समझौता न करते हुए, अकेले चुनाव के मैदान में जाने का फैसला भी ले सकती है। जैसे कि उप्र की बात करें, तो उप्र में मुस्लिम और दलित समाज कहीं-न-कहीं कांग्रेस की तरफ आकर्षित होता नजर आ रहा है। दरअसल, पिछले दिनों आजम खान की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का घर से न निकलना कहीं-न-कहीं मुस्लिम समाज में नाराजगी का एक कारण है। मुस्लिम समाज को लगता है कि कांग्रेस ही उसके लिए बेहतर विकल्प है। दूसरी ओर दलितों के लिए मायावती का कोई निर्णय न लेना भी कांग्रेस की राह खोलता नजर आ रहा है। तो इससे लगता है कि आने वाले समय में उप्र में कांग्रेस का जनाधार तेजी से बढ़ सकता है। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दिन ही राहुल गांधी की पैदल यात्रा भी अयोध्या पहुंचेगी; क्योंकि अब कांग्रेस भी अयोध्या मंदिर की बात कर रही है। उसका कहना है कि इसकी शुरुआत राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खोलकर की थी, जिसका लाभ उसको भी मिलना चाहिए। अब कांग्रेस को इसका कितना लाभ मिलता है? यह तो समय ही तय करेगा। बहरहाल, कांग्रेस अपने मजबूती वाले राज्यों में अपने सहयोगी दलों को सीटें देने से कतरा रही है, जिससे राज्यों में मजबूत अन्य पार्टियां भी कांग्रेस को सीटें देने से कतराएंगी।

वर्तमान में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के अलावा सपा, राजद, जद(यू), आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव गुट), एनसीपी (शरद पवार गुट), सीपीआई, सीपीआईएम और डीएमके के अलावा छोटे क्षेत्रीय दल शामिल हैं। जाहिर है जो पार्टियां क्षेत्रों में सिमटी हैं, वो अपने वर्चस्व वाले राज्यों में सीटें देने के बदले राष्ट्रीय स्तर पर उभरने की कोशिश करेंगी, जिससे उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान मिले। कांग्रेस इसमें रोड़ा बनेगी। क्योंकि उसे पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा उसी का वर्चस्व है, जिसे वो किसी भी हाल में कम नहीं करना चाहेगी। इससे इंडिया गठबंधन में दरार पड़ सकती है।

● **विपिन कंधारी**

लंबे समय तक ऐसा लगता रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं सचिन पायलट के बीच अंदरूनी कलह का फायदा उठाकर भाजपा राजस्थान में भी वही कहानी दोहराने वाली है। पर लगता है कि गांधी परिवार और केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व, दोनों ने अपनी पिछली गलतियों से कड़वा सबक सीखा है। मिलनसार एवं राजनीतिक रूप से चतुर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे पुराने योद्धा को पार्टी अध्यक्ष बनाने से बड़ा फर्क आया है।

कौन लगाएगा जीत का सिक्सर

इस महीने से शुरू हुए देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों ने लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा और हाल ही कांग्रेस के नेतृत्व में गठित विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच एक प्रकार से सेमीफाइनल का महत्व हासिल कर लिया है। तीन राज्यों– छत्तीसगढ़, मप्र और राजस्थान में तो दो राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस को सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दलों का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करती है, तो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा पर दबाव बढ़ेगा। लिहाजा ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए परीक्षा है कि वह कांग्रेस मुक्त भारत का अपना वादा पूरा कर पाने में सक्षम हो पाते हैं या नहीं।

पांच साल पहले हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस तेलंगाना और मिजोरम में बुरी तरह हार गई थी, जबकि छत्तीसगढ़ में उसे जबर्दस्त जीत मिली थी, और मप्र एवं राजस्थान में उसने कुछ सीटों के अंतर से जीत हासिल कर तीन राज्यों में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया था। मगर मुश्किल से एक साल बाद ही बड़ी संख्या में विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के दलबदल के कारण भाजपा मप्र में सत्ता वापस हासिल करने में कामयाब रही।

लंबे समय तक ऐसा लगता रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं सचिन पायलट के बीच अंदरूनी कलह का फायदा उठाकर भाजपा राजस्थान में भी वही कहानी दोहराने वाली है। पर लगता है कि गांधी परिवार और केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व, दोनों ने अपनी पिछली गलतियों से कड़वा सबक सीखा है। मिलनसार एवं राजनीतिक रूप से चतुर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे पुराने योद्धा को पार्टी अध्यक्ष बनाने से बड़ा फर्क आया है। कांग्रेस के दोनों क्षेत्रीय क्षत्रपों एवं अन्य विपक्षी नेताओं से निपटने में बेहद प्रभावी खड़गे अब तक बिना किसी रुकावट के विधानसभा चुनावों के मौजूदा दौर में राजनीतिक सफर तय करने में कामयाब रहे हैं। गांधी परिवार ने उन्हें ऐसा करने का अधिकार दिया है।

भाजपा की अपनी समस्याएं हैं, जिन्हें उसे हल करना है। ये समस्याएं मुख्यत: केंद्रीय नेतृत्व द्वारा छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, मप्र में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे क्षेत्रीय क्षत्रपों को चुनाव अभियान का नेतृत्व देने के प्रति अनिच्छा से उपजी हैं। गौर करना चाहिए कि ऐसी ही रणनीति के कारण कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश में भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ी थी। इसलिए संकेत हैं कि अंतिम समय में केंद्रीय नेतृत्व ने इन तीनों नेताओं की नाराजगी दूर करने के प्रयास किए।

दरअसल, 2018 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा हाईकमान ने तीन बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह को न सिर्फ हाशिये पर डाल दिया था, बल्कि इस बार अंतिम क्षण तक यह निश्चित नहीं था कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। लेकिन अंतत: उन्हें टिकट दे दिया गया। इसके बावजूद भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री पद

राज्यों में क्या है लीडरशिप फैक्टर

लोकल लीडरशिप की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों ही नेता खुद भी ओबीसी हैं। दोनों राज्यों में कांग्रेस ओबीसी की पार्टी बनी हुई है। मप्र की बात करें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही सामान्य वर्ग से आते हैं। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी नेता हैं। राजस्थान से लेकर मप्र और छत्तीसगढ़ तक भाजपा का लोकल लीडरशिप की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर मैदान में उतरने की रणनीति ने भी कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला। प्रधानमंत्री मोदी खुद को ओबीसी नेता, वंचित वर्ग से आने वाला नेता बताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे में कांग्रेस की अधिक मुखरता का उल्टा पड़ने का खतरा भी था।

के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं कर रही, जबकि कांग्रेस भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रही है। इसी तरह, मप्र में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान भाजपा की जीत होने पर भी मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। एक बार फिर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस दुविधा में फंसा है कि चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाए बिना चौहान का कद कैसे छोटा किया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घटते प्रभाव ने इसे और जटिल बना दिया है, जिनके पूर्व वफादार अब फिर से कांग्रेस में लौट रहे हैं। राजस्थान में भाजपा के लिए राह तुलनात्मक रूप से आसान होनी चाहिए, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सत्ता विरोधी रुझान और नाराज प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट, दोनों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भाजपा यहां भी दुविधा में है कि राजनीतिक नुकसान उठाए बिना प्रभावी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को कैसे कमजोर किया जाए। पिछले महीने एक समय ऐसा लगा था कि भाजपा नेतृत्व वसुंधरा राजे के वफादारों को टिकट नहीं देने जा रहा। लेकिन राजे के तेवर को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने अपना रुख बदला और अंतिम क्षण में उनके वफादारों को इस उम्मीद में टिकट दिया कि इससे वह आश्वस्त होंगी।

इन तीनों चुनावी राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि भाजपा ने किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश नहीं किया है और वह प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पहले से ही तय कर रखे हैं। अब देखना यह है कि इसका चुनावों में क्या असर पड़ता है। हिमाचल एवं कर्नाटक के नतीजों को देखते हुए भाजपा के लिए यह चिंताजनक होना चाहिए।

तेलंगाना और मिजोरम का उभरता चुनावी परिदृश्य भी केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। वहां हाल के महीनों में कांग्रेस ने उल्लेखनीय राजनीतिक बढ़त हासिल की है। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि भाजपा समेत विभिन्न दलों के नेता बड़ी संख्या में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मिजोरम में आदिवासी आबादी है, जिनमें से अधिकतर ईसाई हैं, जो पड़ोसी राज्य मणिपुर के कुकी समुदाय से जातीय संबंध साझा करते हैं। वे मणिपुर में कुकियों और देश के अन्य हिस्सों में ईसाईयों को निशाना बनाए जाने से क्षुब्ध हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले राजग से संबद्ध होने के बावजूद केंद्र सरकार का पर्याप्त विरोध न करने के कारण सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के प्रति राज्य में असंतोष है। इसका लाभ अगर कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट को चुनाव में मिले, तो आश्चर्य नहीं।

फिर भी यह देखना बाकी है कि क्या कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हुए अपने विरोधियों की कमजोरियों का फायदा उठा पाएगी? यह काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले हफ्तों में वह गति खोए बिना अपनी पकड़ बनाए रख सकती है या नहीं, क्योंकि अनुमान यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी रथ जब रफ्तार पकड़ेगा, तब शक्ति और संसाधनों के मामले में प्रभावी भाजपा को उसका फायदा मिलेगा। करीब एक महीने पहले 2 अक्टूबर को जब बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए, ऐसा लगा जैसे देश की सियासत में उबाल आ जाएगा। कोई इसे मंडल पार्ट-2 बता रहा था तो कोई इसे नई ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) क्रांति। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होने लगी थी। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के इस कदम में भाजपा को हराने का मंत्र देखने लगे थे।

कांग्रेस ने तो राजस्थान से लेकर मप्र तक सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने का वादा तक कर दिया। चुनावी राज्यों में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया लेकिन अब ये शोर मद्धिम पड़ता नजर आ रहा है। चुनावी राज्यों में जातिगत जनगणना का मुद्दा कहीं गुम सा होता दिख रहा है। चुनावी राज्यों में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत में पूरी शिद्दत से उठाने वाली कांग्रेस के सुर भी इसे लेकर अब नरम पड़ गए हैं। कांग्रेस ने भी राज्यों के विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना के मुद्दे को छोड़ सा दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस को जिस मुद्दे के सहारे ये लग रहा था कि वह भाजपा को हरा देगी, आखिर पार्टी ने उस जातिगत जनगणना के मुद्दे को छोड़ क्यों दिया?

राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी ने इसे लेकर कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर बज बनाने में विफल रही है। कांग्रेस के नेताओं ने चुनावी रैलियों में जातिगत जनगणना कराने के वादे तो किए लेकिन ये बताने से गुरेज करते रहे कि जातिगत जनगणना के बाद आखिर क्या? जातिगत जनगणना से ओबीसी को क्या लाभ है? पार्टी ये समझाने में फेल रही है। उन्होंने कांग्रेस के इस मुद्दे को छोड़ देने को लेकर कहा कि इसके तीन अहम कारण हैं। एक कारण ये है कि ओबीसी कोई होमोजीनियस वोट बैंक नहीं है। इसमें भी अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई रही है। इसकी वजह से लोवर ओबीसी उदासीन है। अब खतरा ये है कि ओबीसी एकमुश्त आने से रहे, जो सवर्ण साथ हैं कहीं वह भी ना छिटक जाएं। लोकल लीडरशिप और प्रतिनिधित्व में ओबीसी का अभाव और कई सीटों पर सवर्ण मतदाताओं की निर्णायक भूमिका भी कांग्रेस के इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने की वजह हो सकती है।

● इन्द्र कुमार

लोवर ओबीसी की उदासीनता

कहा तो ये जा रहा है कि बिहार सरकार ने जब जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए, तब विपक्ष को उम्मीद थी कि अब ये मुद्दा दूसरे राज्यों में भी बड़ा रूप ले लेगा। जगह-जगह आंदोलन होंगे, ओबीसी समाज के लोग जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद कर सड़कों पर उतर आएंगे, जनांदोलन के दबाव में केंद्र सरकार बैकफुट पर आ जाएगी और विपक्ष को नतीजे में मिल जाएगा पॉलिटिकल गेन। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता केंद्रीय कैबिनेट सचिव रैंक के अधिकारियों में ओबीसी जाति की भागीदारी का जिक्र कर सरकार पर हमलावर भी हुए। लेकिन वैसा नतीजा नहीं मिला जैसे नतीजे की विपक्षी पार्टियों को उम्मीद थी। ये मुद्दा जनता को कनेक्ट नहीं कर पाया। इसके पीछे वजह को लेकर कहा जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण का लाभ हर राज्य में कुछ गिनी-चुनी जातियों तक ही सीमित रह गया। बहुत सी जातियों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाया और ये एक बड़ी वजह है कि लोवर ओबीसी इसे लेकर उदासीन है।

चुनावी मैदान में खड़ी धान

छत्तीसगढ़ में मतदान ऐसे समय में होने जा रहा है जब खरीफ के धान की कटाई हो रही होगी। पहली नवंबर से धान खरीद का सीजन लग गया है। करीब 70 प्रतिशत धान उपजाने वाले किसानों के इस सूबे में इसी वजह से चुनाव हर बार की तरह इस बार भी धान केंद्रित हो गया है। आलम यह है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों, सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भाजपा ने अपना-अपना घोषणापत्र धान के चलते रोका हुआ है। धान का कटोरा कहे जाने वाले इस राज्य में दो चरण में 7 और 17 नवंबर को मतदान होना है। पहले मतदान से महज 10 दिन पहले एक ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने का वादा कर डाला है, तो दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 20 और 21 अक्टूबर को चावल की कस्टम मिलिंग में कथित घोटाले के सिलसिले में चार जिलों में छापेमारी की है। कांग्रेस का आरोप है कि हर बार की तरह इस बार भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ भाजपा धान खरीदी को बाधित करने का षड्यंत्र रच रही है। दूसरी ओर राज्य में धान खरीदी से किसानों को सीधा फायदा पहुंचने के कांग्रेस के दावों पर भाजपा अलग से सवाल उठा रही है।

फिलहाल, स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार धान किसानों को केंद्र द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से करीब चार सौ रुपए ज्यादा (कुल 2500 रुपए क्विंटल) भुगतान करती है। इस अंतर को राज्य सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के नाम से सीधे वितरित करती है। अब 1 नवंबर से शुरू हुए खरीद सीजन के लिए राज्य सरकार ने खरीद रकम और खरीद की मात्रा (15 क्विंटल से 20 क्विंटल प्रति एकड़) को बढ़ाने की घोषणा की है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि बगल के राज्य मप्र में उसने 2500 रुपए क्विंटल पर धान खरीद की घोषणा की हुई है, ऐसे में एक ही पार्टी द्वारा दो राज्यों में दो अलग-अलग पैमाने उसके गले की फांस बन सकते हैं। दूसरी ओर भाजपा को इस वादे की कोई काट नहीं मिल रही है, क्योंकि अपनी पिछली सरकारों में उसने धान खरीद पर किए वादे पूरे नहीं किए। किसान नेता डॉ. राजाराम त्रिपाठी का कहना है कि रमन सिंह सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में धान के एमएसपी पर 270 रुपए का बोनस घोषित किया था, लेकिन दोबारा सत्ता में आने पर उसे लागू नहीं किया। दूसरी बार रमन सिंह सरकार ने बोनस को बढ़ाकर 300 रुपए करने का वादा किया, लेकिन साढ़े चार साल तक इस पर अमल नहीं किया। वे बताते हैं कि 2018 के चुनाव से ठीक पहले कुछ फंड रिलीज किया गया। भाजपा सरकार की यह वादाखिलाफी ही उसे ले डूबी। त्रिपाठी का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता गांव-गांव गंगाजल लेकर घूमे और उन्होंने कसम खाई थी कि वे भाजपा की तरह वादाखिलाफी नहीं करेंगे। किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत ठीकठाक बोनस मिला, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने केंद्रीय पूल में राज्य से चावल खरीदी का कोटा कम कर दिया और राज्य के पास सरप्लस चावल बच गया।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसी मसले पर 25 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि केंद्र ने 86 मीट्रिक टन के बजाय केवल 61 मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ से खरीदा है। राजाराम त्रिपाठी के मुताबिक अतिरिक्त चावल से इथेनॉल बनाने की योजना भूपेश बघेल ने प्रस्तावित की थी। केंद्र ने इसका भी लाइसेंस नहीं दिया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मणि वैष्णव का कहना है कि भाजपा की केंद्र सरकार चाहती है कि भूपेश सरकार धान खरीदी को लेकर अपने कदम पीछे हटा ले।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर भाजपा पर हमलावर हैं। राज्य के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत की मौजूदगी में राजनांदगांव जिले में कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में बघेल ने कहा कि पहले किसान आत्महत्या करते थे, चाउर वाले बाबा चाउर भी खा जाते थे। घोटालों पर घोटाले हो रहे थे। पहले नान घोटाला, फिर खदान घोटाला, धान घोटाला। इन्हीं सब के खिलाफ जनता 2018 में कांग्रेस के साथ आई और कांग्रेस की सरकार बनी।

लंबे समय से भूपेश सरकार दावा कर रही है कि उसने कर्ज माफी के वादे को पूरा किया है और इससे करीब 18 लाख किसानों को कर्ज से मुक्ति मिली है। किसान नेता त्रिपाठी सवाल उठाते हैं कि मोदी सरकार की कर्ज माफी या उद्योगपतियों को दी गई कर्ज माफी से तुलना करें, तो यह कुछ नहीं है। वे कहते हैं, एक कहावत है कि धान और गरीबी का चोली-दामन का साथ है। छत्तीसगढ़ में जितना ज्यादा धान पैदा होता है, उतनी ही ज्यादा गरीबी है। कर्ज माफी या बोनस से किसानों को बहुत मामूली राहत मिली है, लेकिन सरकार के लिए दावे के लिहाज से यही बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भाजपा ने इतना भी नहीं किया था।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

भाजपा ने धान और किसान को बनाया मुद्दा

छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद पिछले विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर सिमटी भाजपा पुरजोर वापसी की कोशिश में धान और किसान को लेकर ही सबसे ज्यादा परेशान है। जानकारों का कहना है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही धान के खरीद मूल्य को लेकर बड़ी घोषणा करने की तैयारी में है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि पार्टी चुनाव घोषणापत्र समिति की बैठक में इस पर गंभीरता से विचार भी कर चुकी है। चुनावी दांव के रूप में भाजपा धान खरीदी की 3000 रुपए की दर की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस की निगाह इसी घोषणा पर टिकी हुई है। इसी चक्कर में दोनों दलों के घोषणापत्र अटके पड़े हैं। बाकी मुद्दों पर हालांकि दोनों दलों के बीच ज्यादा फर्क नहीं है। मसलन, सांप्रदायिकता के मसले पर तक दोनों दल अलग-अलग चाल से एक ही पाले से खेल रहे हैं। भूपेश बघेल ने बीते 5 साल में नरम ढंग से जो हिंदुत्व की राजनीति की है, उसे कांग्रेस के बांटे टिकटों में देखा जा सकता है। इसलिए धान पर घोषणा ही दोनों दलों के बीच का मार्जिन तय करेगी, जो इस बार काफी कम रह सकता है। राज्य की 90 सीटों में से कांग्रेस के पास 71 सीटे हैं जबकि भाजपा के पास 14, जोगी कांग्रेस के पास तीन और बसपा के दो विधायक हैं। पहले चरण में 7 नवंबर को प्रदेश की कुल 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुके हैं।

महाराष्ट्र में कलह

नए सियासी समीकरण की चर्चा

महाराष्ट्र की सरकार में जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार की एंट्री हुई है, तब से महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण की चर्चा होने लगी है। सरकार में शामिल भाजपा के साथ तो उनके संबंध सहज दिख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के साथ उनके संबंध तल्ख हो रहे हैं। गत दिनों कैबिनेट की बैठक में इसकी बानगी देखने को मिली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सत्तारूढ़ गठबंधन में विभिन्न दलों के मंत्रियों के बीच अंदरूनी कलह पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे अधिक समन्वय के साथ और एक टीम के रूप में काम करें। एक महीना पहले शिंदे सेना, भाजपा और एनसीपी (अजित पवार) का प्रतिनिधित्व करने विधायकों और सांसदों की एक संयुक्त बैठक में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के लिए समन्वय समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया था। इसमें प्रत्येक समिति में सभी का एक प्रतिनिधि होगा। लेकिन, पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के बीच मतभेद एक वास्तविकता बनी हुई है।

महाराष्ट्र की तीन पैरों वाली सरकार में अंदरूनी कलह चरम पर हैं। इस कलह को मराठा आरक्षण आंदोलन ने और बढ़ा दिया है। भाजपा और एनसीपी (अजित) के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके दल के विधायक-मंत्री अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अजित पवार इस संकट में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो शिंदे अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में देखे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के विभिन्न दलों के बीच आपसी समन्वय नहीं होने पर टकराव की स्थिति बन गई है।

गत दिनों महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सत्तारूढ़ गठबंधन में विभिन्न दलों के मंत्रियों के बीच अंदरूनी कलह पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एक सख्त संदेश में मंत्रियों से कहा कि वे अधिक समन्वय के साथ और एकजुट चेहरा दिखाते हुए टीम के रूप में काम करें। शिंदे का निर्देश शिव सेना (एकनाथ शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) के मंत्रियों के बीच खुले असंतोष के बाद आया। ठीक एक महीने पहले शिंदे सेना, भाजपा और एनसीपी (अजित पवार) का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों और सांसदों की एक संयुक्त बैठक में प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के लिए समन्वय समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया था। तय हुआ था कि प्रत्येक समिति में तीनों सत्तारूढ़ दल का एक प्रतिनिधि होगा। ऐसा माना जा रहा था कि इससे उनके जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में मदद मिलेगी। हालांकि, पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के बीच मतभेद साफतौर पर दिख रहा है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बार-बार दिल्ली जाने को शांति-प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। अक्टूबर में शिंदे ने 48 घंटे के भीतर दो बार दिल्ली के लिए उड़ान भरी। गत दिनों अजित पवार ने गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली आने का समय मांगा था। इस बीच, जब तीनों पार्टियां मराठा आरक्षण आंदोलन की आग से लड़ने में व्यस्त थीं, अजित के सहयोगी छगन भुजबल ने ओबीसी कैटेगरी के भीतर मराठों को आरक्षण देने के खिलाफ अपनी ही सरकार को चेतावनी जारी की।

भुजबल ने कहा, मराठों के लिए कुनबी प्रमाण पत्र को सरकार की मंजूरी उन्हें ओबीसी कोटा के भीतर पिछले दरवाजे से प्रवेश देने की एक चाल है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस पर आगे बढ़ने की कोई भी कोशिश का नतीजा अच्छा नहीं होगा। ओबीसी समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आएंगे। शिंदे सेना के मंत्री संभुराज देसाई ने पलटवार करते हुए कहा कि भुजबल की भड़काऊ टिप्पणी गठबंधन सरकार के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। चाहे जानबूझकर या संयोग से भुजबल का ओबीसी दावा मुख्यमंत्री द्वारा संकेत दिए जाने के तुरंत बाद आया कि वह दो महीने के भीतर मराठा आरक्षण मुद्दे का समाधान खोजने के प्रति आश्वस्त हैं। सरकार में भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना है कि चुनावों को देखते हुए, प्रत्येक पार्टी और उसके नेता-मंत्री ऐसा रुख अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके लिए सुविधाजनक हो। सरकार के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राज्य प्रशासन और राजनीतिक क्षेत्र दोनों में शिंदे की बढ़ती दावेदारी एनसीपी (अजित) को रास नहीं आ रही है। सभी पार्टियों के स्थापित मराठा नेता ओबीसी कोटा के भीतर मराठों के लिए आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। बल्कि वे मराठों के लिए अलग कोटा चाहते हैं।

विगत दिनों जब अजित पवार ने अमित शाह से मुलाकात की तो जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें मराठा कोटा भी शामिल था। पता चला है कि उपमुख्यमंत्री चाहते हैं कि केंद्र हस्तक्षेप करे और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाए। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के तीन घटक दलों में से एनसीपी गुट के नेता अजित पवार सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं। 40 विधायकों के साथ शिंदे सेना-भाजपा सरकार में शामिल होने के चार महीने बाद, वह कथित तौर पर मुख्यमंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। शुरू में ऐसा नहीं था। सरकार में शामिल होने के एक महीने के भीतर, अजित ने इतने उत्साह के साथ प्रशासनिक कार्य करना शुरू कर दिया कि कई लोग उन्हें सुपर सीएम कहने लगे। लेकिन फिर सरकार (मतलब मुख्यमंत्री शिंदे) ने एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी फाइलों को सीएमओ के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य कर दिया गया। अपने गुट के विधायकों को शामिल करने के लिए कैबिनेट विस्तार की अजित की बार-बार की गई मांग को भी रोक दिया गया है। अब, जब शिंदे वास्तविक मराठा नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो वह गठबंधन में तीसरे स्थान पर खिसके हुए महसूस कर रहे हैं।

विपक्षी कांग्रेस नेता विजय वड्डेतिवार का कहना है कि क्या अजित पवार सरकार में खुश हैं? महाविकास अघाड़ी सरकार में उन्हें खुली छूट थी। उनकी क्षमता और गतिशीलता की सराहना की गई। लेकिन भाजपा को अपने सहयोगियों की क्षमता को कम करने की आदत है। एनसीपी (अजित) के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने मतभेदों को कम महत्व देते हुए कहा कि अजित पवार दो सप्ताह से डेंगू से पीड़ित हैं। उन्हें पूर्ण आराम की सलाह दी गई है। आग में घी डालते हुए एनसीपी मंत्री धरमराव आत्राम ने कहा कि अजित पवार जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे। शिंदे सरकार के पास संख्या बल है। लेकिन आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए सीटों का बंटवारा होने के बाद सत्ता संघर्ष और उग्र होने की संभावना है।

● **बिन्दु माथुर**

बागी बिगाड़ेंगे गणित

राजस्थान में नाम वापसी के बाद अब उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस और भाजपा के तमाम प्रयासों के बावजूद ज्यादातर जगहों पर बागी उम्मीदवारों को मनाने में सफलता नहीं मिली। अभी भी कांग्रेस और भाजपा के लगभग 45 से ज्यादा बागी चुनावी मैदान में हैं। इनमें से ज्यादातर निर्दलीय हैं, कुछ को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) गठबंधन ने टिकट दिए हैं। 25 सीटों पर भाजपा के बागी तो 20 सीटों पर कांग्रेस के बागी चुनाव लड़ रहे हैं। बागियों के हिसाब से बाड़मेर की शिव सीट सबसे हॉट सीट है, जहां कांग्रेस का एक और भाजपा के दो बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां भाजपा के बागी जालम सिंह रावलोत और रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष फतेह खान भी मैदान में हैं।

जननायक जनता पार्टी ने भी कुछ बागियों को टिकट दिए हैं। बागियों ने कांग्रेस और भाजपा के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। बाड़मेर की ही सिवाना सीट से मुख्यमंत्री के नजदीकी नेता सुनील परिहार भी बागी हो गए हैं। राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के मौजूदा विधायक जौहरीलाल मीणा टिकट कटने के बाद बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़गढ़ से बागी होकर मैदान में हैं। कांग्रेस के बागी और लंबे समय तक जिलाध्यक्ष रहे फतेह खान बागी चुनावी मैदान में है। इस सीट पर भाजपा के भी दो बागी हैं। फतेह खान को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। पायलट समर्थक खिलाड़ीलाल बैरवा टिकट कटने के बाद बागी होकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस के दलित वोटों में बिखराव से मुकाबला रोचक हो गया है। एससी के लिए रिजर्व इस सीट पर अन्य जातियां हार-जीत का आधार तय करेंगी। बाड़मेर की सिवाना सीट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी सुनील परिहार बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। परिहार को मनाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माने। परिहार के बागी होने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।

कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा टिकट कटने के बाद बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। जौहरीलाल के बागी होकर लड़ने से वोटों का बंटवारा हो गया है। इस सीट पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। जौहरीलाल के बेटे पर रेप केस लगने की वजह से उनका टिकट कटना बताया जा रहा है। नागौर सीट पर पूर्व विधायक हबीबुर्रहमान टिकट कटने के बाद बागी होकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने हरेंद्र मिर्धा और भाजपा ने ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। वे अब तक चुनाव में डटे हैं। लूणकरणसर में पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बेनीवाल की बगावत के कारण यहां कांग्रेस के वोट बैंक में बिखराव होना तय हो गया है। टिकट कटने की सहानुभूति भी बेनीवाल के साथ हो सकती है जिसका कांग्रेस को नुकसान हो सकता है।

शिव सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। भाजपा के तीन-तीन नेता यहां से बागी होकर लड़ रहे हैं, इस वजह से भाजपा के वोट बैंक में बिखराव तय है। ऐसे हालात में जीत-हार का फैसला बहुत कम अंतराल में होता है। चित्तौड़गढ़ सीट पर टिकट कटने से नाराज होकर भाजपा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या बागी होकर लड़ रहे हैं। दिल्ली बुलाकर समझाइश करने के बावजूद आक्या अपने रुख पर कायम हैं। आक्या की बगावत से भाजपा को नुकसान हो रहा है। आक्या की जगह नरपत सिंह राजवी को यहां से टिकट दिया है, पहले राजवी का विद्याधरनगर से टिकट काटा गया तो राजवी बगावत पर उतारू हो गए थे। राजवी को यहां से टिकट दिया तो आक्या ने बगावत कर दी। बाड़मेर सीट पर प्रियंका चौधरी की बगावत से भाजपा को नुकसान हुआ है। इस सीट पर भाजपा लगातार हार रही है। अब बगावत ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं, आरएलपी ने भी उन्हें समर्थन दे दिया है जिसके बाद पूरा सियासी सीन ही बदल गया है।

वसुंधरा राजे के नजदीकी और दो बार मंत्री रहे युनूस खान बगावत करके डीडवाना से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। युनूस खान की बगावत से भाजपा को नुकसान हुआ है। इस वजह से यहां का चुनाव कांटे की टक्कर वाला बन रहा है। भीलवाड़ा की शाहपुरा सीट से पूर्व विधानसभा स्पीकर कैलाश मेघवाल भाजपा उम्मीदवार को चुनौती दे रहे हैं। मेघवाल ने चुनावों से पहले ही बगावत करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल पर कई आरोप लगाए थे। उस वक्त से मेघवाल पार्टी से सस्पेंड हैं। कैलाश मेघवाल के मैदान में डटे रहने से भाजपा को नुकसान हुआ है। ऐसे कई और नेता भी हैं, जिन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

कांग्रेस के बागी

शिव से फतेह खान, बसेड़ी से खिलाड़ीलाल बैरवा, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ से जौहरीलाल मीणा, शाहपुरा से आलोक बेनीवाल, सिवाना से सुनील परिहार, जालोर से रामलाल मेघवाल, नागौर से हबीबुर्रहमान, लूणकरणसर से वीरेंद्र बेनीवाल, चौरासी से महेंद्र बारजोड़, सादुलशहर से ओम बिश्नोई, मनोहरथाना से कैलाश मीणा, खींवसर से दुर्ग सिंह खींवसर, देवाराम रोत, राजकरण चौधरी, अजीजुद्दीन आजाद, राकेश बोयत, रामनिवास गोयल, नरेश मीणा, करुणा चांडक, गोपाल गुर्जर और मनोज चौहान कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं।

भाजपा के बागी

भाजपा में कांग्रेस से ज्यादा बागी मैदान में हैं। शिव से रवींद्र भाटी, चित्तौड़गढ से चंद्रभान आक्या, डीडवाना से युनूस खान, बाड़मेर से प्रियंका चौधरी, झुंझूनू से राजेंद्र भांबू, सूरतगढ़ से राजेंद्र भादू, शाहपुरा से कैलाश मेघवाल, लाडपुरा से भवानी सिंह राजावत, खंडेला से बंशीधर बाजिया, झोटवाड़ा से आशुसिंह सूरपुरा, सुजानगढ़ से राजेंद्र नायक, सीकर से ताराचंद धायल, सवाईमाधोपुर से आशा मीणा, संगरिया से गुलाब सिंवर, सांचौर से जीवाराम चौधरी, मसूदा से जसवीर सिंह खरवा, ब्यावर से इंद्र सिंह, मकराना से हिम्मत सिंह राजपुरोहित, लूणकरणसर से प्रभुदयाल सारस्वत, कोटपूतली से मुकेश गोयल, जालोर से पवनी मेघवाल, बस्सी से जितेंद्र मीणा, फतेहपुर से मधुसूदन भिंडा, पिलानी से कैलाश मेघवाल, डग से रामचंद्र सुनेरीवाल मैदान में हैं। रितु बनावत, अशोक कोठारी, ज्ञानचंद सारस्वत, रुपेश शर्मा और योगी लक्ष्मण नाथ भी भाजपा के बागी हैं।

लोकसभा चुनाव की बिसात

उप्र में लोकसभा चुनाव की तैयारी तमाम राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य और सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश उप्र में विपक्षी दल अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक यह तैयारी कागजों पर ही होती दिखी है। विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की एकता की बात अब तक सामने नहीं आ पाई है। राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भाजपा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है, लेकिन विपक्षी गठबंधन का स्वरूप चुनावी राज्यों में क्या होगा? यह अभी तक सामने नहीं आ पाया है। दरअसल, इस साल नवंबर- दिसंबर में पांच राज्यों मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मेघालय में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां भाजपा और विपक्षी गठबंधन के बीच मुकाबला होता दिख रहा है।

विधानसभा चुनाव वाले अधिकांश राज्यों में सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस से चुनावी राज्यों में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। कांग्रेस इन जगहों पर सहयोगियों को सीट देने को तैयार होती अब तक नहीं दिख रही है। ऐसे में उप्र में होने वाला लोकसभा चुनाव का मसला गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था कि उप्र में हम विपक्षी गठबंधन के तहत सीट सहयोगियों को देंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान उप्र की राजनीतिक तस्वीर बदली हुई थी। माय (मुस्लिम+यादव) समीकरण की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी और दलित राजनीति को धार देकर सत्ता में आने वाली बहुजन समाज पार्टी करीब 26 साल बाद एकसाथ चुनावी मैदान में थी। इससे पहले वर्ष 1993 में मुलायम सिंह यादव और कांशीराम साथ आए थे तो उप्र की राजनीति में एक नारा खूब प्रचलित हुआ था। 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भाजपा हिंदुत्व के घोड़े पर सवार होकर उप्र जीतने के इरादे से चुनावी मैदान में थी। लेकिन, मिले मुलायम- कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम नारे के साथ आए दोनों दलों ने भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि, यह समीकरण 2019 में काम नहीं कर पाया।

अखिलेश यादव को इस स्थिति में झटका मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की रणनीति में लग सकता है। इन राज्यों में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में उप्र में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सपा बड़ा झटका दे सकती है। इस प्रकार की राजनीतिक स्थिति ने प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव और गठबंधनों के भविष्य पर चर्चा छेड़ दी है। सवाल यह है कि उप्र के प्रमुख राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है? वे किसके साथ हैं, किसके खिलाफ? कांग्रेस भी इंडिया के भाग के रूप में अब तक दिख रही है। हालांकि, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सभी 80 लोकसभा सीटों पर पार्टी की चुनावी तैयारी की बात कर एक अगल ही बहस शुरू कर दी है। पार्टी 25 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। साथ ही, विधानसभा वाले राज्यों में भी पार्टी सहयोगियों को सीट देने के मूड में नहीं दिख रही है। ऐसे में इंडिया के सहयोगियों को साधकर चलना पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की टीम भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर बसपा सुप्रीमो मायावती के भी संपर्क में है। राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी खीर किसे अच्छी नहीं लगती है, जैसे बयान देकर राजनीति गरमाते रहते हैं। हालांकि, वे खुद को इंडिया के सहयोगी के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन के तहत 12 से 15 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करना चाहते हैं। ऐसे में रालोद की उम्मीदों को अखिलेश किस हद तक पूरा सकते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे रालोद कांग्रेस के भी आसपास जाती दिखती रही है। मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी अब तक चुनावी मैदान में अकेले दम पर उतरती दिख रही है। पार्टी की ओर से अपनी रणनीति को साफ नहीं किया गया है। पर्दे के पीछे बसपा और कांग्रेस के बीच खिचड़ी पकने की चर्चा है। लेकिन, केंद्र की मोदी सरकार के प्रति बसपा सुप्रीमो का नरम रुख भी चर्चा में है। ऐसे में मायावती दलित वोट बैंक को जोड़कर रखने और चुनावी मैदान में उनकी सफलता को लेकर अभी से कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

उप्र में ऐसी है दलीय स्थिति

भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी सभी 80 सीटों पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी में है। वर्ष 2019 में पार्टी ने दो सीटों पर सहयोगी अपना दल एस को लड़ाया था। दोनों सीटें पार्टी के खाते में आई थीं। भाजपा ने 62 सीटें जीतीं। इस बार पार्टी की ओर से मिशन 80 बनाया गया है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। अपना दल एस एनडीए के सहयोगी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरती रही है। इस बार भी अनुप्रिया पटेल के रुख में कोई भी बदलाव होता नहीं दिख रहा है। वे एक बार फिर भाजपा के सहयोगी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरती दिखेंगी। निषाद पार्टी ने अब तक लोकसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी के तौर पर किस्मत नहीं आजमाई है। उप्र की योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद अब तक एनडीए के सहयोगी के तौर पर दिख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पिछले दिनों एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले सुभासपा भाजपा के साथ आई थी। लेकिन, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन से बाहर हो गई। अब एक बार फिर पार्टी साथ है। माना जा रहा है कि भाजपा सुभासपा को भी गठबंधन के तहत सीट दे सकती है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी। इंडिया गठबंधन में सपा बड़े भाई की भूमिका में दिख रही है। ऐसे में पार्टी अपने सहयोगियों को किस प्रकार मनाकर रखेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फ्रंट के जरिए पार्टी खुद को लोकसभा चुनाव के मैदान में बड़ी भूमिका में पेश करने की कोशिश करती दिख रही है। पार्टी ने सामाजिक समीकरण को साधकर 55 से 60 फीसदी वोट शेयर पर अपनी दावेदारी शुरू कर दी है।

सुशासन बाबू की स्त्री शिक्षा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में महिलाओं को लेकर दिए अपने आपत्तिजनक बयान पर चाहे माफी मांग ली हो और स्वयं की निंदा कर ली हो पर सच यही है कि स्त्री अस्मिता और विधानसभा व विधान परिषद की गरिमा को जो क्षति उन्होंने पहुंचा दी है वह अपूरणीय है। विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते-बोलते नीतीश बाबू अपनी भाषा, सोच और मर्यादा से नियंत्रण खो बैठे। वायरल होते उनके वीडियो को देखकर प्रथम दृष्टया तो लगा शायद वीडियो मोर्फड किया गया है, क्योंकि किसी भी प्रदेश के मुखिया से सभा के पटल पर ऐसी निंदित भाषा और भाव भंगिमा की अपेक्षा तो अकल्पनीय ही है। परंतु जब पुष्ट माध्यमों से खबरें और विचार-विमर्श आने लगे तो सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी।

सियासी गलियारे में हाय-तौबा मचता देख नीतीश कुमार ने माफी तो मांग ली है पर माफी मांगते समय भी जो तेवर और भंगिमा थी वह किसी भी तरीके से स्वीकृत नहीं है। उनका माफीनामा इस तरह का है जैसे उन्होंने माफी मांगकर आपत्ति करने वालों को चिढ़ाया है। उनको इस बात का इल्म अभी तक नहीं है कि विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने कितनी घटिया और फूहड़ भाषा का प्रयोग किया है। भाजपा ने तो मुख्यमंत्री के मानसिक स्वास्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और जांच के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात पर अड़ गई है। भाजपा ने यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को डिम्नेशिया हो सकता है जिसमें वो बातें भूलने लगे हैं। साथ में उन पर अश्लीलता को एंजॉय करने का भी आरोप भाजपा ने लगाया है। सोशल मीडिया पर उनके डोप टेस्ट की भी मांग उठने लगी है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्त्री शिक्षा की महत्ता और जनसंख्या नियंत्रण में उनकी भागीदारी को ऐसे समझाने की कोशिश की जिसे सुनकर उनके पीछे बैठी उनकी ही पार्टी महिला विधायक ने शर्म से अपना मुंह छिपा लिया। उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में खड़े होकर जिस प्रकार की निहायत सड़कछाप भाषा में पति-पत्नी के बीच बनने वाले शारीरिक संबंध में डालने और बाहर पानी निकालने जैसे असभ्य और सांकेतिक पोर्न शब्दावली का इस्तेमाल किया है, वैसी भाषा बिहार के बदनाम भोजपुरी गायक भी अपने गीतों में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार यह बताना चाह रहे थे कि विवाह के बाद शारीरिक संबंध बनाते समय पढ़ी-लिखी लड़कियां इस बात का ख्याल रखती हैं ताकि वह अनचाहे गर्भ की चिंता से मुक्त रहे। मगर इसी बात तो बिहारी अंदाज में नीतीश कुमार ने सदन में कुछ ऐसे रखा कि आज कोई भी उसको दोहरा तक नहीं सकता। इस तरीके का संवाद आने पर सेंसर बोर्ड 'ए' सर्टिफिकेट दे देता है। मगर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिना किसी एडिटिंग के निर्लज्जता से हंसते हुए इस बात को कह डाला जिसे दोहराते हुए किसी भी संतुलित इंसान की जिव्हा थरथरा जाए।

नीतीश कुमार के बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस फूहड़ बयान को एक बार को स्लिप ऑफ टंग मान भी लिया जाता, परंतु विधान परिषद में अपने बयान के ठीक बाद इसकी पुनरावृत्ति भी कर दी। तब इसे सोचा समझा बयान ही माना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके इस बयान की निंदा की परंतु ऐसे बयान के कुप्रभाव को क्या दोषी की निंदा कर लेने भर से या उसके माफी मांग लेने से कम किया जा सकता है? जिस देश में अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के गलत तरीके अपनाने से हर रोज 8 महिलाओं की मृत्यु हो रही हो, वहां ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर मसखरी करना जनता का दुर्भाग्य ही है। 25.5/1000 शिशु जन्म दर के साथ बिहार भारत का अग्रणी राज्य है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जन्म दर ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में जनसंख्या दर 4.3 से 2.9 हुई है। इस दर को 2 तक करने के तरीके और महत्ता को बताने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री ने अश्लील भाषा और असंसदीय शब्द का प्रयोग किया। इस मुद्दे की गंभीरता को सिरे से नकारते मुख्यमंत्री ने बायोलॉजिकल प्रक्रिया का सड़कछाप बखान कर दिया। महिला की सुरक्षा और अस्मिता पर आंसू बहाने वाला इंडी एलायंस चुप्पी साधे है। नीतीश सरकार में शामिल घटक दल राजद नेता कवर फायर करते दिख रहे हैं।

स्त्री के सम्मान को तार-तार करने वाले नीतीश कुमार के बयान को जस्टिफाइड करने वालों का अपराध भी कम नहीं है। सदन के गरिमा की बात की जाए तो यह पहली बार नहीं है जब किसी भी सदन में महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी की गई हो। नेता सदन के भीतर और बाहर महिलाओं का अपमान करते आए हैं। परकटी, टंच माल, टनाटन, जर्सी गाय, करोड़ की गर्ल फ्रेंड... जैसे शब्द और भाषा ने पहले भी महिला की गरिमा के परखच्चे उड़ाए हैं पर ऐसे बयान अधिकांश व्यक्तिगत टिप्पणी होती थी। शरीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया को वर्णित करके संपूर्ण महिला जगत को अपमानित करने का जैसा निकृष्ट कार्य बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है, वैसा किसी ने नहीं किया।

● **विनोद बक्सरी**

नीतीश ने अपने राजनीतिक पतन की इबारत लिख दी

भाषायी मर्यादा और सदन की गरिमा को चोटिल करने वाले नीतीश कुमार ने स्त्री शिक्षा जैसे आवश्यक मुद्दे को भी हल्का कर दिया है। जातीय जनगणना सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में सिर्फ 7 प्रतिशत लोग ग्रेजुएट हैं। यह डिग्री भी यहां 3 साल की बजाय 5 साढ़े 5 साल में मिलती है। स्त्री की साक्षरता देश के स्तर पर 71.5 प्रतिशत है तो बिहार में यह मात्र 55 प्रतिशत है। ऐसे में सदन में खड़े होकर सड़कछाप भाषा में बिहार की किन पढ़ी-लिखी महिलाओं का हवाला दे रहे थे? दरअसल नीतीश कुमार की भाषा पिछले साढ़े तीन दशकों में बिहार के चरमरायी शिक्षा व्यवस्था का स्तर और सामाजिक व्यवस्था की दरकती सोच का परिणाम है। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो शुचिता, सभ्यता, संवेदनशीलता की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। जनता का गुस्सा देख लगता है नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक पतन की इबारत लिख दी है। बिहार की जिन महिलाओं ने उन्हें सर माथे बैठाया था वो जानती हैं कि एक बयान की वजह से वो अब गली मोहल्ले में भी ऐसे अभद्र टिप्पणियों की शिकार होंगी। इस मामले में अमेरिकी महिला गायक मैरी मिलबेन के बयान पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मिलबेन ने कहा है कि अगर वो भारत की नागरिक होती तो नीतीश कुमार के इस बयान के विरोध में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दावेदारी पेश करतीं। उनके इस बयान पर भाजपा को ध्यान देना चाहिए कि क्या वो बिहार में कोई महिला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सकती है?

ANU SALES
CORPORATION
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology
& Medical Equipment
BS200
BioSystems
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530
Email : ascbhopal@gmail.com

पाक में कठपुतली सरकार की तैयारी

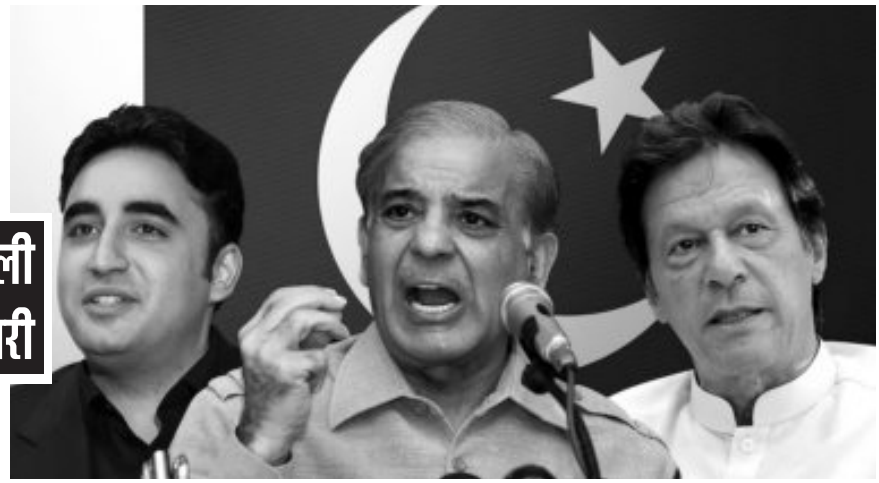

कई विरोधाभासों एवं उथल-पुथल के बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वहां के चुनाव आयोग को 8 फरवरी, 2024 को आम चुनाव कराने की अंतिम तारीख तय करने के लिए मजबूर करने में अहम भूमिका निभाई, जिसे किसी न किसी बहाने से टाला जा रहा था और अनिश्चितता चरम पर थी। विश्लेषकों का मानना है कि इससे दो उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। पहला, इससे पाकिस्तान के नाजुक लोकतंत्र के बारे में उम्मीदें जगेंगी, जिस पर हमेशा वहां की ताकतवर सेना द्वारा कब्जा किए जाने का खतरा रहता है। दूसरा, इससे स्थिरता की भावना पैदा होगी और कार्यवाहक सरकार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज के लिए बातचीत करने में मदद मिलेगी।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम रहता है, तो यह भारत के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि पड़ोस में शांति रहने से सकारात्मक माहौल बनता है। आज जैसी स्थिति है, उसमें सेना की मदद से नवाज शरीफ के अगले प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं प्रबल हैं, जिससे भारत के प्रति शत्रुता थोड़ी कम हो सकती है। नवाज शरीफ ने पहले भी शांति की पहल की कोशिश की थी, हालांकि सैन्य जनरलों ने उसे विफल कर दिया था। कूटनीतिक सिद्धांत के अनुसार, भले ही दोनों देशों के रिश्तों को शत्रुता नियंत्रित करती हो, लेकिन बातचीत जारी रहनी चाहिए। यदि पाकिस्तान गंभीरता दिखाए और कश्मीर का मोह छोड़ दे, तो भारत फिर से बातचीत शुरू कर सकता है।

शहबाज शरीफ की सरकार ने वित्तीय संकट को प्रमुख कारण बताकर चुनाव में देरी करने की कोशिश की थी और शीर्ष अदालत के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, जिसे सेना का भी समर्थन था। विगत 9 अगस्त को पाकिस्तान की संसद भंग हो गई थी, जिससे अराजक शासन का अंत हुआ और आम चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रधानमंत्री अनवार उल हक के नेतृत्व में कार्यवाहक सरकार ने चुनाव कराने की प्रक्रिया तेज कर दी। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदि का हवाला देकर संसद भंग करने के बाद निर्धारित 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने में असमर्थता जताई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तथा अन्य ने चुनाव आयोग को समय पर चुनाव कराने का निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को राष्ट्रपति अल्वी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने का निर्देश दिया। इस तरह आम चुनाव कराने की अंतिम तारीख 8 फरवरी तय की गई।

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की वतन वापसी का समय कोई संयोग नहीं है, बल्कि असीम मुनीर के सेना प्रमुख बनने के बाद सेना ने सावधानीपूर्वक इसकी योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की सियासत में सेना की सर्वोच्चता को चुनौती देने वाले इमरान खान को ठिकाने लगाना है। जिस सैन्य व्यवस्था ने कभी नवाज शरीफ को देश से बाहर जाने पर मजबूर किया था, वहीं आज उन्हें गले लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा उथल-पुथल भरे दौर में उनसे बेहतर विकल्प उपलब्ध नहीं है। सेना ने तीन बार नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल किया और अब चुनाव से ठीक पहले नवाज की वापसी ने सेना का काम आसान कर दिया। नवाज शरीफ इमरान खान के प्रति कटुता से भरे हुए हैं, इसलिए सुलह की कोई संभावना नहीं है और प्रमुख विपक्षी दल पीटीआई को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी पीटीआई की स्थिति खराब हो गई है और एक अदालत ने उनके खिलाफ मुल्क के गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने का आरोप लगाया है, जिसमें उन्हें मौत की सजा भी हो सकती है। चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित कर दिए जाने के बाद जब तक उन्हें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल जाती, तब तक वह चुनाव नहीं लड़ सकते।

विश्लेषकों का कहना है कि पिछले एक साल के दौरान चार घटनाओं ने पूरे पाकिस्तान के सियासी माहौल को बदलकर रख दिया है। पहली घटना, मई, 2023 में नेशनल एसेंबली में एक विधेयक पारित किया गया, जिसमें आजीवन अयोग्यता की अवधि को घटाकर पांच साल कर दिया गया, जिसका उद्देश्य नवाज शरीफ की वापसी सुनिश्चित करना था। दूसरी घटना, 9 मई को इमरान समर्थकों द्वारा सेना मुख्यालय में तोड़फोड़ की है, जब सेना प्रमुख मुनीर को अपनी स्थिति मजबूत करने का सुनहरा मौका मिला। मुनीर ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त करके अपने अधिकार को प्रदर्शित किया, जो देश की घरेलू राजनीति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। तीसरी घटना इमरान समर्थक सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की जगह नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में काजी फैज ईसा की नियुक्ति है, जिसने नवाज की पार्टी को बड़ी राहत दी, जो उनसे निष्पक्ष फैसले की उम्मीद करती है। चौथी घटना नवाज की पाकिस्तान वापसी है, अगर वह पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम हो सकता है। नवाज ने संकेत दिया है कि वह पड़ोसियों के साथ शांति चाहते हैं और बदले की राजनीति से बचना चाहते हैं।

● **कुमार विनोद**

चुनावी प्रक्रिया समय पर

नवाज उम्मीद करते हैं कि चुनाव कराने के लिए परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाएगी। नवाज शरीफ ने अपने परिवार के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में लोगों को बताया और अपने भ्रष्टाचारों पर पर्दा डालने के लिए इमरान सरकार के बदले की राजनीति का जिक्र किया। इस्लामाबाद में विशेषज्ञ यह संभावना भी जताते हैं कि शरीफ बंधु भारत कार्ड भी खेल सकते हैं और इमरान खान को भारतीय एजेंट बता सकते हैं। उनका मानना है कि ऐसा लगता है कि सेना ने इमरान खान की पार्टी की जीत की किसी भी संभावना को कम करने के लिए नवाज शरीफ पर भरोसा करने का आखिरी विकल्प चुना है। अगले साल की शुरुआत में आम चुनाव होने वाले हैं, जिसका मतलब होगा कि पाकिस्तान में छद्म ही सही, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहेगी। इमरान खान के अमेरिका विरोधी और भारत विरोधी रुख को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि नवाज शरीफ थोड़े बेहतर साबित हो सकते हैं, पर हमें रुककर आगे की घटनाओं को देखना होगा।

महिलाओं को टिकट नहीं, रेवड़ियां बांट रही हैं पार्टियां

नए संसद भवन में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि यह सपना अधूरा था जिसे पूरा करने के लिए ईश्वर ने मुझे चुना। इस विधेयक के कानून बनने के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर में होने वाले मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव में भाजपा महिला उम्मीदवारों की संख्या 33 प्रतिशत के आसपास रख सकती है। ऐसा करके वह यह संदेश दे सकती है कि महिला आरक्षण कानून भले ही 2029 में लागू हो, भाजपा ने उसे 2023 के विधानसभा चुनावों से ही लागू करने का तय कर लिया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा मप्र की सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है जिसमें मात्र 28 महिलाओं को ही टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने 29 महिलाओं को टिकट दिया है।

टिकट बंटवारे में भाजपा ने भले ही महिलाओं को 33 प्रतिशत हिस्सा न दिया हो लेकिन मप्र में भाजपा इस बार महिला वोटरों को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ पिछले चार महीनों में ही महिलाओं के लिए 21 हजार करोड़ से अधिक की घोषणाएं की हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री रहे और फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने भी महिलाओं के लिए 30 हजार करोड़ के वादे कर डाले हैं। इन वादों को देखें तो यह सरकार की कुल कमाई के 30 प्रतिशत के आसपास बैठता है। भाजपा ने तय किया है कि वह मप्र में शिवराज सरकार और मोदी के किए गए कामों को लेकर महिला मतदाताओं के बीच जाएगी। भाजपा महिलाओं को यह बताना चाहती है कि डबल इंजन की सरकार होने का मतलब महिलाओं को डबल बोनस। मोदी के रक्षा बंधन के दिन गैस सिलेडर में 200 रुपए की कटौती और 2016 में शुरू की गई उज्ज्वला योजना को 75 लाख घरों तक बढ़ाने के साथ ही महिलाओं के लिए स्वच्छ जल मिशन, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं महिलाओं को समर्पित हैं।

मप्र की तरह राजस्थान में भी महिला मतदाताओं का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। पिछले चार विधानसभा चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरूषों के मुकाबले लगभग दो गुना तेजी से बढ़ा है। 2018 के चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरूषों के लगभग बराबर पहुंच गया है। ऐसे में आधी आबादी पर राजनीतिक दलों का फोकस भी पूरा है। अशोक गहलोत सरकार ने चुनावी साल में अपनी तीन बड़ी योजनाएं महिलाओं पर ही केंद्रित रखी। बचत-राहत-बढ़त और स्मार्ट फोन वितरण। यही नहीं, सरकारी योजनाओं के प्रचार पोस्टरों का रंग भी महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए गुलाबी रखा गया है। इससे पहले वसुंधरा सरकार ने भी आधी आबादी के लिए भामाशाह योजना, पंचायत राज में 50 प्रतिशत आरक्षण जैसे बड़े कदम उठाए थे। राजस्थान के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2013 के मुकाबले 2018 में पुरूष वोटिंग 4.85 प्रतिशत व महिला वोटिंग 10.46 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है। लोकतंत्र के उत्सव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने का ही नतीजा है कि इस बार विधानसभा चुनावों में महिलाएं सियासी दलों के केंद्र में है। हालांकि मतदान में महिलाओं की भागीदारी भले ही लगातार बढ़ रही हो लेकिन पार्टी में पद, चुनाव में टिकट और उसके बाद मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल सरकार ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए महिला कोष ऋण योजना में महिलाओं को ऋण देने की सीमा चार लाख से बढ़ाकर छह लाख कर दी है। इसके अलावा भूपेश बघेल ने कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत दूसरी बेटी के जन्म होने पर महिलाओं को 5 हजार की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महिला वोटर्स पर फोकस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ गठन के बाद पहली बार महिला मतदाताओं की संख्या पुरूष मतदाताओं से ज्यादा हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के कुल 33 जिलों में से 18 में महिला मतदाताओं की संख्या पुरूषों से अधिक हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी महिलाओं को लुभाने में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने राज्य तेलंगाना में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाएं लागू की हैं। इसके अंतर्गत दुल्हनों को शादी के समय एक लाख रुपए की एक बार वित्तीय सहायता दी जाती है। कांग्रेस ने तेलंगाना में सरकार आने पर महालक्ष्मी गारंटी योजना के तहत बेटियों को एक लाख रुपए और एक तोला सोना देने का वादा किया है।

● **ज्योत्सना**

आखिर कब मिलेगा पूरा हक?

टिकट बंटवारे में भले ही 33 प्रतिशत हिस्सेदारी देने की बाध्यता 2029 में आए लेकिन उससे पहले ताजा विधानसभा चुनावों में सभी राजनीतिक दल महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रहे हैं और सत्ता में आने पर महिलाओं के लिए नई योजनाए लागू करने का वादा कर रहे हैं। महिला आरक्षण विधेयक को संसद से पारित करवाने वाली भाजपा यह बताना चाहती है कि मोदी के कारण महिलाओं को जीवनयापन में आसानी तथा आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। भाजपा विधानसभा चुनाव में इस बात को फोकस में रखना चाहती है कि मोदी सरकार की योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी महिलाएं रही हैं और मोदी सरकार ने साढ़े नौ साल के कार्यकाल में नारी शक्ति पर विशेष ध्यान दिया है इसलिए यह बात अधिक से अधिक महिला वोटरों तक पहुंचाई जाए। असल में भाजपा महिला आरक्षण के असर को इस चुनाव में महिला वोटर्स के माध्यम से देखना चाहती है। यदि महिलाएं भाजपा के पक्ष में एकतरफा वोटिंग करती हैं तो तय है कि मोदी और भाजपा की राज्य सरकारें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महिलाओं के लिए और नई योजनाएं लाकर आधी आबादी के वोट को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगी। कांग्रेस महिला वोटरों को साधने के साथ-साथ ओबीसी आरक्षण की मांग और जातिगत सर्वेक्षण कराने का वादा करके भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। अब महिला वोटर्स ओबीसी के नाम पर बंटती है या एकमुश्त वोट करती हैं यह चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा।

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

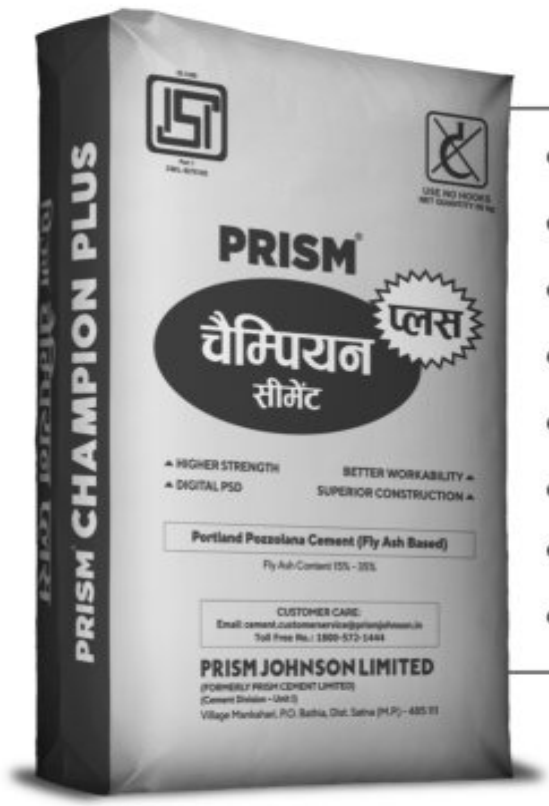

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

ट्यूशन उद्योग

ट्यूशन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मास्टर छेदीलाल से एक पत्रकार ने साक्षात्कार के दौरान पूछा- 'सर, आप अपनी सफलता का राज, हमारे पाठकों को बताने का कष्ट करेंगे।'

'इसमें कोई राज की बात नहीं है। बस त्रैमासिक परीक्षा में जानबूझकर अधिकाधिक छात्रों को, खासकर उच्च तथा मध्यमवर्गीय परिवार के छात्रों को फेल कर दिया जाए तो वे सभी आपके यहां ट्यूशन पढ़ने आने लगेंगे।' मास्टर छेदीलाल जी ने एकदम व्यावसायिक अंदाज में जवाब दिया।

- डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा

हवन

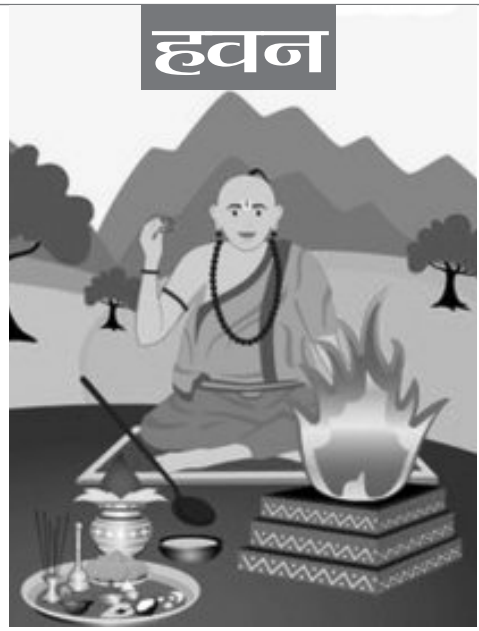

हमारे मोहल्ले में एक अंकल जी गायत्री परिवार से जुड़े हैं। पिछले कई सालों से प्रत्येक रविवार को वे गायत्री मंदिर में हवन करने जाते हैं। उनका प्रयास हमेशा यही रहता है कि वे अपने साथ मोहल्ले और अपने परिचितों में से कम से कम एक-दो-तीन ऐसे लोगों को जरूर लेकर जाते थे, जिनमें कुछ ऐसी बुराइयां होतीं, जिसका कुप्रभाव उनके जीवन में पड़ता था, लेकिन उन्हें किसी के समझाने का फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा भी नहीं था, कि हर कोई अंकल की बात मानकर उनके साथ चल ही देता था, लेकिन अंकल जी नियम से अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहे।

ऐसा भी नहीं था कि हर कोई एक बार में उनके साथ हवन में जाने भर से अपनी बुराई का त्याग कर ही देता था। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे, जो उनके साथ पहली बार उनकी बात मान कर जाते थे, लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे भी होते थे, जो अगली बार स्वयं ही वहां पहुंच जाते। जिसका परिणाम यह है कि आज बहुत से लोग अपनी बुराइयां जैसे, नशा करना, छोटी-मोटी चोरी करना, छोटी-छोटी बात विवाद, मारपीट करने, छोटे बड़े का अपमान करना, घर में क्लेश और मारपीट करना, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना आदि हवन कुंड में स्वाहा कर चुके हैं। कुछ लोग समय की विवशता वंश अपने घर पर ही गायत्री माता का हवन अनुष्ठान करने लगे हैं। अंकल जी के निस्वार्थ प्रयासों का परिणाम आज दिख रहा है कि मोहल्ले के अधिकांश लोगों की बुराइयां तिरोहित हो गई हैं और अब मोहल्ले का माहोल एकदम बदला-बदला सा दिखने लगा। कुछ युवाओं की पहल पर अंकल जी की सहमति और बुजुर्गों के संरक्षण में तीज त्योहारों पर मोहल्ले के रामलीला मैदान में सार्वजनिक हवन का आयोजन भी होने लगा है। और लोग खुशी-खुशी उसमें शामिल होकर अपनी बुराइयां स्वयं ही अपनी आहुति के साथ हवन कुंड के हवाले कर रहे हैं। अब तो अंकल जी की नई पहचान हवन वाले अंकल की हो गई है।

- सुधीर श्रीवास्तव

गीत

अम्बर के सिरताज परिंदे।
भरते जब परवाज परिंदे।
डुबकी में संगीतक लोरी।
विहम लगाते चोरी-चोरी।
दरिया भीतर साज परिंदे।
अम्बर के सिरताज परिंदे।
इक-दूजे से कोई ना रूठे।
सब धर्मों से सच्चे ऊंचे।
रब्ब जैसी आवाज परिंदे।
अम्बर के सिरताज परिंदे।
इंद्रधनुष पंखों में भर के।
रंग अस्तित्व स्थापित कर के।
सिर पर पहने ताज परिंदे।
अम्बर के सिरताज परिंदे।
घर निर्माण में उत्तम शिल्पी।
बंदे से सर्वोतम शिल्पी।
कर्मठता के काज परिंदे।
अम्बर के सिरताज परिंदे।
इन्हों में भी आदत होती।
मोह ममता के बाबत होती।
हो जाते नाराज परिंदे।
अम्बर के सिरताज परिंदे।
ना सीमा ना धर्म ना जाति।
रात दोपहर या प्रभाती।
धरती के स्वराज परिंदे।
अम्बर के सिरताज परिंदे।
मुश्किल होती इनकी भाषा।
समझें दुख-सुख आस निराशा।
देते जन आवाज परिंदे।
अम्बर के सिरताज परिंदे।
बंदे से अधिक स्याने।
देते नहीं है ग्लानि ताने।
लेते नहीं है दाज परिंदे।
अम्बर के सिरताज परिंदे।
आजादी के भीतर रहते।
मिलजुल कर सब दुख-सुख सहते।
होते नहीं मोहताज परिंदे।
अम्बर के सिरताज परिंदे।
इन से उत्पन्न उड़न खटोले।
लाखों मील परों से तोले।
यात्रा के समराज परिंदे।
अम्बर के सिरताज परिंदे।
इन से ही सुर संगीत बना।
इन्हों ने सभ्याचार जना।
संस्कृति का आगाज परिंदे।
अम्बर के सिरताज परिंदे।
बालम सुख को बांटते जाते।
मुश्किल में भी नहीं घबराते।
दुख का रखते राज परिंदे।
अम्बर के सिरताज परिंदे।

- बलविंदर बालम

मैक्सवेल जैसा कोई नहीं!

अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 नवंबर को वर्ल्ड कप मैच में जो कुछ हुआ उसे तमाम क्रिकेट फैन्स ताउम्र याद रखेंगे। एक समय अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिरा लिए थे, लगा था कि अफगानिस्तान एक और उलटफेर करेगा, पर ग्लेन मैक्सवेल तो अलग ही इरादे से आए थे। कोई भी शख्स जो 7 नवंबर को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमों के मुकाबले को देख रहा था, वो एक समय मान चुका था कि अफगानी टीम वर्ल्ड कप में एक और उलटफेर करेगी। पर, यहीं से इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल की एंट्री हुई और उन्होंने इस मैच को पूरी तरह से पलटकर रख दिया। मैच की हाइलाइट्स की बात की जाए तो टॉस अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद टीम ने 5 विकेट गंवाकर 291 रनों का स्कोर बनाया। जवाब में खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 91 रनों पर अपने सात विकेट खो चुकी थी, लगा था कंगारू टीम की मैच में फुस्स हो जाएगी, पर ग्लेन मैक्सवेल को पैट कमिंस का साथ मिला। मैक्सवेल ने लंगड़ाते हुए, गिरते हुए, उठते हुए, अपनी टीम को 19 गेंद शेष रहते हुए 3 विकेट से जिता दिया।

बहरहाल, इस मैच को वनडे इतिहास के सर्वश्रेष्ठ मैचों में से एक कहा जा रहा है। वहीं मैक्सवेल की इस पारी को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। इस मैच में अफगानिस्तान की टीम के लिए इब्राहिम जादरान ने 143 गेंदों पर 129 रनों की शानदार नाबाद शतकीय पारी खेली, 21 साल के जादरान वर्ल्डकप में शतक लगाने वाले पहले अफगानी बल्लेबाज बन गए। इस मैच में अफगानी बल्लेबाजों ने भले ही 291 रनों का स्कोर बनाया हो, पर वह बीच के ओवर्स में काफी स्लो हो गए थे। वो तो गनीमत रही कि राशिद खान (35), अजमतुल्ला उमरजई (22) ने आखिरी के ओवर्स में हाथ खेले, जिस वजह से वो 291 रन के स्कोर पर पहुंच पाए। वहीं मैक्सवेल उन बल्लेबाजों में शुमार हो गए, जिन्होंने वर्ल्ड कप शतक नंबर 4 या उससे नीचे आकर जड़े हों। महेला जयवर्धने (4) के अलावा एबी डिविलियर्स, महमूदुल्लाह, ग्लेन मैक्सवेल ने तीन शतक जड़ें हैं। वहीं मैक्सवेल के तीन वर्ल्ड कप शतक नंबर 5 या उससे नीचे से आए हैं, कोई दूसरा बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सका है।

अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले तक वानखेड़े में वनडे मैचों में सबसे बड़ा चेज लक्ष्य 281 रन था, जो न्यूजीलैंड ने 2017 में भारत के खिलाफ किया था। ऐसे में यह पुराना रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ दिया। वर्ल्ड कप मैचों में ऑस्ट्रेलिया द्वारा सफलतापूर्वक पीछा किया गया सबसे बड़ा रनचेज 287 रन है, जो 1996 में चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ था। यह ऐतिहासिक कारनामा भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। किसी वर्ल्ड कप में पारी के आखिरी 10 ओवरों में अफगानिस्तान ने सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। 7 नवंबर को अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 96/2 का स्कोर बनाया। इससे पहले अफगानी टीम का आखिरी के 10 ओवर्स में हाइएस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड 68/4 था, जो इसी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ दिल्ली में आया था। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बना 291/5 का स्कोर सर्वश्रेष्ठ है। इससे पहले अफगानी टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लीड्स में 2019 वर्ल्ड कप में 288 रन बनाए थे। इस मैच में अफगानिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप के दौरान एक पारी में सर्वाधिक छक्के (9) लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। अफगानिस्तान के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल का स्कोर 201 नॉट आउट रन रहा। इस तरह वो वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया के लिए दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। 2011 में मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ शेन वॉटसन का 185* रन ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछला सर्वोच्च स्कोर था।

मैक्सवेल वनडे मैचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए पिछला सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 193 रन था जो फखर जमां ने 2021 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। मैक्सवेल ने अपना दोहरा शतक 128 गेंदों में बनाया, उनसे तेज दोहरा शतक पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन ने 126 गेंदों में बनाया है। जो सबसे फास्टेस्ट है। मैक्सवेल नंबर 3 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। 2009 में बांग्लादेश के खिलाफ चार्ल्स कोवेंट्री का 194* रन किसी गैर-सलामी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया पिछला सर्वोच्च वनडे स्कोर था। मैक्सवेल से पहले किसी भी खिलाड़ी ने लिस्ट ए क्रिकेट में भी टॉप-4 से बाहर बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक नहीं लगाया था। मैक्सवेल छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। वनडे वर्ल्ड कप में दोहरा शतक लगाने वाले वह तीसरे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले क्रिस गेल (2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 219) और मार्टिन गुप्टिल (2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 237*) ऐसा कर चुके हैं।

● आशीष नेमा

मैक्सवेल और कमिंस की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड

202 रन नॉट आउट ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस के बीच पार्टनरशिप हुई। वनडे में सातवें विकेट या उससे कम के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले सबसे बड़ी साझेदारी 2015 में बर्मिंघम में न्यूजीलैंड के खिलाफ सातवें विकेट के लिए जोस बटलर और आदिल राशिद की 177 रनों की थी। वहीं कंगारू टीम ने सातवां विकेट गिरने के बाद 202 रन जोड़े, जो वनडे पारी में किसी भी टीम द्वारा सबसे अधिक रन हैं। सातवां विकेट गिरने के बाद इससे पहले सबसे ज्यादा 196 रन अफ्रीका वर्ल्ड कप ने 2007 में एशिया 11 के खिलाफ बनाए थे। इस पार्टनरशिप की एक और खास बात रही कि आठवें विकेट के लिए कमिंस के साथ मैक्सवेल की 202 रनों की नॉट आउट पार्टनरशिप के दौरान मैक्सवेल ने 179 रनों का योगदान दिया। इस दौरान कमिंस ने 68 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन बनाए, इस दौरान 11 रन अतिरिक्त के जरिए आए। मैक्सवेल का 88.61 प्रतिशत रनों का योगदान वनडे मैचों (जहां तक डेटा उपलब्ध है) में एक शतक में किसी बल्लेबाज द्वारा सबसे अधिक है। मैक्सवेल ने दिल्ली में नीदरलैंड के खिलाफ कमिंस के साथ अपनी 103 रन की साझेदारी के दौरान 88.35 प्रतिशत के अपने योगदान से बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने तब 91 रन बनाए थे।

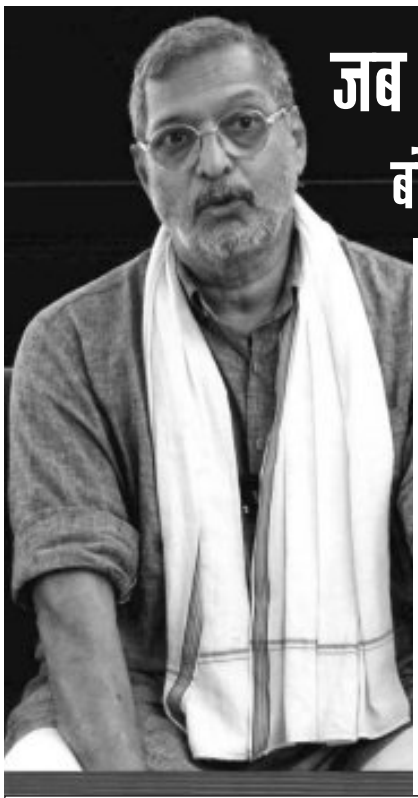

जब एक्टर ने दोस्त के लिए गिरवी रख दिया घर

बोले- मूवी पूरी कर लो... फिल्म ने रच दिया इतिहास

कई फिल्मों को बड़े बजट में बनाया जाता है, तो कुछ फिल्में छोटे बजट में भी करोड़ों कमा जाती हैं। फिल्म के पूरी करने के लिए कभी बजट अड़ंगा मार गया तो कभी कोई और वजह। 37 साल पहले सिर्फ 12 लाख में बनी एक फिल्म बनते-बनते रुख गई तो एक्टर ने इस दर्द को समझा और अपनी ख्वाहिशों को छोड़ मदद के लिए खड़े हो गए।

ये किस्सा है साल 1986 में आई फिल्म अंकुश का। निर्देशक एन चंद्रा की ये पहली फिल्म थी। 37 साल पहले बनी इस फिल्म का बजट था सिर्फ 12 लाख। एन चंद्रा ने लगभग सभी ऐसे कलाकारों को फिल्म के लिए चयन किया जो फिल्मों में काम करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने नाना पाटेकर को भी ऐसे ही इस फिल्म के लिए साइन किया, जो फिल्म की तलाश में थे। नाना को तब उन्होंने 10 हजार रुपए में साइन किया, जिसके 3 हजार फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले दे दिए और बाकी 7 हजार फिल्म की शूटिंग के बाद देने की बात हुई। वो भी तब अगर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खरीद ली।

नाना पाटेकर जी-जान लगाकर फिल्म की शूटिंग करने लगे, लेकिन कुछ दिन बाद फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। क्योंकि, निर्माता के पास सब पैसे खत्म हो गए थे। फिल्म को पूरा करने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत थी। उस वक्त नाना पाटेकर की एक चाहत थी की जब फिल्म पूरी हो जाए तो उनके जो 7 हजार रुपए मिलेंगे वो उन पैसों का एक स्कूटर खरीदेंगे। ये बात उन्होंने निर्देशक एन चंद्रा को भी बता रखी थी।

रिलीज होते ही हिट हुई फिल्म... बहुत कोशिश की, लेकिन जब कहीं से फिल्म को पूरा करने के लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो नाना पाटेकर ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना घर गिरवी रखकर 2 लाख रुपए फिल्म निर्माता को दे दिए। फिल्म बनकर तैयार हुई और रिलीज भी हुई। फिल्म रिलीज होते ही हिट साबित हुई और मेकर्स मालामाल हो गए। निर्देशक एन चंद्रा ने नाना पाटेकर का ये एहसान माना और 2 लाख रुपए देकर एक्टर का न सिर्फ घर छुड़वाया बल्कि उनके 7 हजार रुपए भी दिए और साथ में दिया एक चमचमाता हुआ नया स्कूटर तोहफे के रूप में भी दिया।

अमिताभ बच्चन से जब झगड़ गए विधु विनोद चोपड़ा, डायरेक्टर को सताने लगा डर, गिफ्ट की करोड़ों की रोल्स रॉयस

12वीं फेल की कामयाबी के बीच विधु विनोद चोपड़ा और उनकी फिल्मों के किस्से खूब सुनने को मिल रहे हैं। विधु विनोद चोपड़ा का बर्ताव बतौर निर्देशक काफी कलाकारों को असहनीय लगता है। उन्हें झेलना अपने-आप में एक मशक्कत होती है। अमिताभ बच्चन को जब विधु के साथ एकलव्य में काम करने का मौका मिला, तो जया बच्चन ने उन्हें डायरेक्टर के मिजाज के बारे में बताया। एक्ट्रेस ने कहा कि वे विधु को हफ्तेभर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसा सोचा था, वैसा हुआ भी। शूटिंग को 10 दिन ही गुजरे थे कि अमिताभ और विधु के बीच मतभेद होने लगे।

अमिताभ के रवैये से खुश हुए डायरेक्टर... विधु ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें डर सताने लगा कि कहीं अमिताभ बच्चन बीच में ही एकलव्य की शूटिंग छोड़कर न चले जाएं, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उनकी आशंका के विपरीत बर्ताव किया। वे रोजाना की तरह सेट पर पहुंचे और फिल्म की शूटिंग पूरी की। डायरेक्टर अमिताभ बच्चन के पेशेवर रवैये से इतना खुश हुए कि उन्हें रोल्स रॉयस कार उपहार में दे दी, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए थी।

ब्लॉकबस्टर देकर रातोंरात बने स्टार, 15 फिल्मों के बाद भी खाने पड़े धक्के, अब हीरो से विलेन बना ये लवर ब्वॉय

फिल्म अभिनेता डिनो मोरिया ने अपनी रोमांटिक इमेज से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई। करियर की शुरुआत में ब्लॉकबस्टर फिल्म भी दी। इसके बावजूद इंडस्ट्री में काम पाने के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिस के चक्कर काटे। फिर जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया कि एक्टर एक फिल्म के लिए तरस गए। अब मलयालम इंडस्ट्री में विलेन बनने को है मजबूर। साल 2002 में राज डिनो मोरिया और बिपाशा बसु दोनों के ही करियर के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुई थी। लेकिन इस फिल्म के बाद भी डिनो का करियर उस मुकाम तक नहीं पहुंच सका जैसा कि उन्होंने सोचा होगा।

जब चक्कर काटने पड़े... इंडस्ट्री में फिल्म राज से सफलता पाने के बाद भी डिनो के करियर में एक वक्त ऐसा भी आया जब 15 फिल्में करने के बाद भी उन्हें काम पाने के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिस के चक्कर काटने पड़े थे। बीते दिनों वह तेलुगू फिल्मों में बतौर विलेन एंट्री कर चुके हैं। कभी हीरो बनकर दिल जीतने वाला एक्टर काम की वजह से अब विलेन बनने को मजबूर है। काफी समय से वह किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर नहीं आए हैं।

बातें बना : बात बना

आज तो बात की बात करनी है। बात अपने बहुविध रूपों में हमें और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। बात की मधुवात, घात किंवा लात से बच नहीं सकते। बात की जाती है, बात सुनी जाती है, बात गुनी जाती है। और तो और बात चुपड़ी भी जाती है। बात गिरती है। बात उठती है। बात मानी जाती है। कभी-कभी नहीं भी मानी जाती। बात क्या कुछ नहीं करती! बात चलाई भी जाती है। बात नहीं भी चलाई जाती। बेबात की बात भी होती है। बात की अपनी कीमत भी होती है। बात ऊल-जलूल भी होती है। कभी फिजूल भी होती है। कभी अनुकूल भी होती है। बात को तूल दिया जाता है। तूल नहीं भी दिया जाता। बात भूली भी जाती है। बात छूती भी है। कोई-कोई बात लेश मात्र नहीं छूती। बात का आदि भी होता है, अंत भी होता है। बात की गर्मी भी होती है, वसंत भी होता है।

बात करने में और बात बनाने में अंतर होता है। बहुत बड़ा अंतर होता है। बात तो सब करते हैं। दुनिया करती है। किंतु बातें बनाना सबको नहीं आता है। बातें बनाने वाला बातों का कलाकार होता है। यह तो अभी शोध का विषय है कि बातें बनाना कला है अथवा विज्ञान? परंतु जो बातें बनाता है, वह जन सामान्य से कुछ अलग ही तरह का होता है। कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे देश और समाज में कौन-कौन बातें बनाना जानता है। जैसे:- वकील, शिक्षक, प्रोफेसर, धर्म गुरु, कथा वाचक, राजनेता, राजनेताओं के चमचे, गुर्गे और अंधानुगामी, ठग, मजमेबाज (बंदर-बंदरिया, भालू, सांप या जादूगर के खेल दिखाने वाले), विज्ञापन कर्ता, ट्रेन, बस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि में सामान बेचने वाले, दलाल, एजेंट आदि कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं, जिनसे इनके जॉब, व्यवसाय या रोजी-रोटी चलती है। अगर ये सब बातें बनाना न जानें तो उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाती है।

बात में से बात और उसमें से पुन: नई बात निकाल पाना कोई सहज बात नहीं है। इसके लिए भी अक्ल चाहिए कि सामने वाले को अपनी बातों से प्रभावित कर सके। उसे सम्मोहित करके अपनी इच्छानुसार चला सके। वकील अपनी तर्क रूपी बातों की बरसात से अदालत को हिला डालता है। तो शिक्षक या प्रोफेसर अपने विषय-ज्ञान की गहनता से अपने शिष्यों को अभिभूत ही कर लेता है। बात में से नई बात का उद्भव करते हुए ज्ञान-गंगा बहाता है। धर्म गुरु या कथावाचक रस संचार के लिए नए-नए दृष्टांत और कथाओं की विविधता से जनता जनार्दन की बुद्धि का परिमार्जन करता है। उनमें सरसता लाकर हृदयंगम बनाता है। जनता को मंत्रमुग्ध कर अधिकाधिक दान-दक्षिणा पाता है।

राजनेता की तो बात ही निराली है। बातों के बिना उसकी नहीं चलने वाली रेलगाड़ी है। आश्वासन, भाषण, वायदे, नारेबाजी सब कुछ उसकी बातों की ही खूबी है। राजनेता का ही अनुसरण उसके चमचों और गुर्गों के द्वारा किया जाना अटल सिद्धांत है। वहां बातों से ही भैंस समेत खोया खाया जाता है। जनता को मिथ्या आश्वासन का जूस पिलाया जाता है। किसी भी प्रकार के ठग के पास बातों के ही बतासे हैं। इन्हीं से तो वह फेंकता अपनी ठगाई के पासे भी। बंदर-बंदरिया, भालू या हाथ की सफाई के खेल दिखाने वालों के पास भीड़ इकट्ठी करने के लिए बड़ी-बड़ी बातें हैं। उनकी डुगडुगी या बांसुरी भी उनकी संगाती हैं। बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों, बस, ट्रेन आदि के फेरुए बेची जा रही सामग्री की ऐसी-ऐसी खूबियां गिनाते हैं कि गंजा आदमी भी कंघी खरीद लेता है। किसी भी वस्तु, बीमा या विक्रीत वस्तु या स्थान का एजेंट या दलाल बातें बनाने का उस्ताद न हो, तो बेचारे की रोजी-रोटी कैसे चले?

नहीं जानते हैं क्या आप! बातों का लबालब सागर। हर उम्र में नौजवां अपना नटनागर। जो भर सकता नहीं, भरता ही है अपनी नन्हीं-सी कुलिया में गागर। किया करता है अपने भाव उजागर। वही कवि, रचनाकार, कथाकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार कलाकार। जिसकी बातों से पटा पड़ा है क्या गगन, क्या भूमंडल, क्या सागर! उसे अपने भावों और विचारों को बातों-बातों में व्यक्त करने का मां सरस्वती ने विविध ज्ञान दिया है। कला दी है। अक्षर, शब्द, वाक्य, रस, छंद, लय, गति, रीति, वृत्ति, ताल दिया है। है कोई इतना बड़ा बातूनी। जो एक-एक की करे दूनी, चौगुनी, आठ गुनी। क्या किसी ने भी साहित्यकार की ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसा बात का धनी न कोई था, न ही हुआ है। अपनी बात बनाने के लिए वही सर्व अग्रणी है, अगुआ है। ये न समझें कोई कि वह खेलता बातों का जुआ है! उसके मानस से हर क्षण भावित भावों का अमृत चुआ है। जो एक रचनाकार है, वहां कोई नहीं पहुंचा हुआ है।

बातों की स्वचालित मशीन (दिमाग) सबके ही पास है। परंतु बात करने और बातें बनाने में बड़ा ही भेद है। कर तो सभी लेते हैं अपने-अपने मतलब की बात, दिन-रात। किंतु बना नहीं सकते बातों-बातों में बात। बातें करना जितनी महान कला है, उतना महान विज्ञान भी है। वह मन से समन्वय करके जिव्हा और स्वर के उच्चारण के माध्यम से बातें बाहर लाता है अथवा लेखनी किंवा कुंजी पटल की कुंजियों से लिख कर बतलाता है। बात-बात का मतलब समझाता है। बात के मूल में छिपे रहस्य को जतलाता है। बातों में लुभाकर बातों में आकर गंजा अनावश्यक होने के बावजूद कंघी ले आता है। बाद में विचार करता है तो उसे बातों का राज समझ में आता है। किंतु अब क्या? कंघी विक्रेता तो अपनी बात बनाकर चला जाता है। बातों का चमत्कार दिखा जाता है।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

मोदी की गारंटी भाजपा का भरोसा

मध्य प्रदेश संकल्प पत्र

- 5 सालों तक गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन
- किसानों से ₹2700 प्रति क्विंटल पर गेहूं और ₹3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की होगी खरीद
- उज्ज्वला और लाड़ली बहनों को ₹450 में मिलेगा गैस सिलेंडर
- मध्यप्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करेंगे
- लाड़ली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ मिलेगा पक्का मकान
- प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर
- 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा लखपति बनाएंगे
- लाड़ली लक्ष्मियों को जन्म से 21 वर्ष तक कुल ₹2 लाख देंगे
- गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे
- जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए ₹3 लाख करोड़
- तेंदूपत्ता संग्रहण दर करेंगे ₹4,000 प्रति बोरा
- गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा
- सरकारी स्कूल में मिड-डे मील के साथ मिलेगा पौष्टिक नाश्ता
- IIT और AIIMS के तर्ज पर खुलेगा मध्य प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी और मध्य प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस
- 13 सांस्कृतिक लोकों का होगा भव्य निर्माण
- 6 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण- विंध्य एक्सप्रेस वे, नर्मदा, अटल प्रगति, मालवा निमाड़, बुंदेलखंड एवं मध्य भारत विकास पथ
- 80 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के साथ वंदे मेट्रो, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और रीवा, सिंगरौली और शहडोल में बनेंगे हवाई अड्डे
- एसटी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय और एसटी बहुल जिलों में खुलेगा मेडिकल कॉलेज
- ₹20,000 करोड़ के निवेश से स्वास्थ्य व्यवस्था बनेगी हाई-टेक, हॉस्पिटल और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या होगी दोगुनी

कमल का बटन दबाएं भाजपा को जिताएं

भाजपा का संकल्प पत्र डाउनलोड करने के लिए QR कोड स्कैन करें

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से WhatsApp के जरिए सीधे जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें

खुशहाल परिवार
कांग्रेस सरकार
100 यूनिट बिजली बिल माफ
200 यूनिट बिजली बिल हाफ
₹25 लाख
तक मुफ़्त इलाज
हर स्कूली बच्चे को
₹1500/माह तक
₹500
में गैस सिलेंडर
बढ़ाइए हाथ
कांग्रेस के साथ
फिर कमलनाथ
Issued By: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी